राजथान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र, १६६५ का छठा दिवस [संख्या ५

मंगलवार, २ मार्च, १६६५

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, यातायात, राजकीय उद्योग, सहकारी, समाज कल्याण, विद्युत्, सार्वजनिक निर्माण, पुरातत्व एवं विद्युत्-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री गंगासिंह।

प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल में परिवर्तित करने की मांग

८८. श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) [श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौली पंचायत समिति (जिला बूंदी) में ग्राम उमर के प्राइमरी स्कूल की किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र व छात्रायें शिक्षा पा रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र व छात्रायें अधिकांश में सैनिकों के बालक है ?

(३) क्या नेफा और लद्दाख में लड़ाई के मोर्चे पर तैनात सैनिकों ने राज्य सरकार के पास इस बात के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि हमारे उमर गांव के प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया जावे ताकि हम सैनिकों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र उन्नति कर सकें ?

(४) क्या सैनिकों की मांग को उचित समझ कर उस क्षेत्र के एम. एल. ए. तथा शड्यूल्ड ट्राइब्स के अन्य विधान सभाइयों ने भी सरकार से उमर ग्राम की स्कूल को मिडल स्कूल बनाने का आग्रह किया है ?

Page No 2

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोविन्दसिंह : इस स्कूल में १४२ छात्र-छात्रायें हैं। इनकी संख्या को देखते हुए क्या यहां पर मिडल स्कूल खोलना उचित नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सरकार की इस सम्बन्ध में नीति है उसके अन्तर्गत यहां पर व्यवस्था नहीं है ?

श्री गोविन्दसिंह : वह क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मकान, पैसा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मकान, पैसा नहीं दे सकते हैं तो आपके यहां पर स्कूल नहीं खोलेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नीति का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास :(आसीन्द)गांव के लिये और शहर के लिए क्या आपकी यह अलग अलग भावना नहीं है ? शहरों में क्यों खोलते हैं बिना पैसा दिये ?

श्री दलपतसिंह : गवर्नमेंट शहरों में अपने पास से पैसा लगाती है और हर प्रकार से शहरों में लोगों को पढ़ने के लिये सुविधा देती है और गांवों का सवाल आता है तो कहते हैं कि पैसे का प्रोब्लम है। फाइनेन्स का प्रश्न केवल गांव वालों के लिए क्यों ?

श्री गोविन्दसिंह : तीन हजार आदमी आस-पास में हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स का यह एरिया है। शिक्षा में तो सब बातों को देखकर आपको इस प्रकार के लिए खास-तौर से प्रावधान करना चाहिये। वे क्या दे सकते हैं आपको ? उनके पास कहां पैसा है देने के लिए ? आपको तो बिना यह प्रोब्लम बताये ही करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक नीति का प्रश्न है उसको देखते हुए राज्य सरकार के सामने आपकी भावना को रखूंगा।

श्री गोविन्दसिंह : इस ओर विशेष दिलचस्पी क्या राज्य सरकार लेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं राज्य सरकार के सामने आपकी भावना को रखूंगा इस आधार पर।

श्री अध्यक्ष : आप ही राज्य सरकार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नीति का प्रश्न है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

Page No 3

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह नीति शहर वालों के लिए ही है, गांव वालों के लिए ही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सब के लिये एक नीति है।

श्री दलपतसिंह : फाइनेन्स के लिए क्या प्रावधान है ? छः सात साल हो गये; न तो आप गांवों में स्कूल खोल रहे हैं और न ही होस्टल खोल रहे हैं, वैसी हालत में गांव के बच्चों की शिक्षा का क्या हाल होगा ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप गांव वालों के लिए कंजूसी क्यों बरत रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांव वालों के लिए कोई कंजूसी का प्रश्न नहीं है। गांव और शहर दोनों के लिए एक सी नीति है । इसलिए यह नीति का प्रश्न है और मैं इस समय इस विषय पर कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मैं आपकी भावना को राज्य सरकार को पहुंचा दूंगा।

श्री दलपतसिंह : होस्टल खोलना है तो ५० प्रतिशत गांव वाले जब तक नहीं देते हैं है तब तक नहीं खोलते हैं। स्कूल के लिए भी यही स्थिति है। हम तो यहां तक देखते हैं कि गांव फाइनेन्शियली इतने बैकवर्ड हैं कि आयन्दा दस वर्ष में भी वहां पर स्कूल और होस्टल नहीं खुलेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों का क्या हाल होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह वेदना का विषय है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वह नीति का प्रश्न भी है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो स्कूल खोलने का प्रावधान निर्धारित कर रखा है सामान्यतया उसके अन्तर्गत यह अभी तक नहीं आता है। भविष्य में जैसा मैंने निवेदन किया, गांव के प्रश्न पर, आप भी सजग हैं और मैं भी। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है नीति के सम्बन्ध में। मैं यहां इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। यह विषय गांव और शहर का नहीं है। फौजियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार सहानुभूति रखती है। यह मुझ पर छोड़ दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह नीति का प्रश्न बता रहे हैं, मंत्री महोदय। आपसे निवेदन है कि उनकी इस नीति में हेरफेर करिये। गांवों के लिए उसकी नीति विपरीत है। शहरों के लिए सब कुछ दे देते हैं। उनके यहां पर टेक्निकल शिक्षा, बिल्डिंग्ज़ बनाना, होस्टल बनाना, सब कुछ आप अपनी ओर से दे देते हैं और गांवों के लिए नीति का प्रश्न बना रहे हैं। शहर वालों से कुछ पैसा नहीं लेते हैं और गांवों में मिडल स्कूल खोलना है, हायर सैकन्डरी स्कूल खोलना है और होस्टल खोलना है, तो गरीब लोगों से पैसा मांगते है और जब पैसा नहीं होता है तो आप उनके लिए कोई इस की व्यवस्था नहीं करते हैं। उनसे निवेदन किया जाय कि गांव वालों के साथ जो उनकी हमदर्दी होनी चाहिए वह

Page No 4

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

नहीं, इसलिए उनको चाहिए कि वे शहर वालों के साथ हमदर्दी रखते हैं तो गांव वालों के साथ भी रखें। इसके लिए उनको हिदायत दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांवों के प्रति बहुत हमदर्दी है। हम आप सब गांवों के रहने वाले हैं लेकिन बदकिस्मती है कि आप और हम इन शहरों में आकर पड़ गये हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : शहरों में आप करोड़ों रुपया शिक्षा के लिये बिना शहर वालों से कुछ लिए लगा देते हैं और गांवों से पैसा मांगते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गांव वालों को पैसे वालों को ढूंढना पड़ता है और नहीं मिलता है तो पांच साल तक कोई स्कूल नहीं बन सकता।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा सु.) : शहरों में कदम कदम पर स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं लेकिन गांवों में मिडल स्कूल भी नहीं खोलते हैं। आप गांवों से वोट लेकर आये हैं। फिर भी आप उनके प्रति सौतेला व्यवहार रखते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांवों के वोट ही नहीं लेते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। जमीन संभालते हैं।

श्री नाथूराम : सारी पंचायत समिति में एक भी हाई स्कूल या हायर सैकन्डरी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.); आप कहते हैं कि फौजियों की दर्ख्वास्त ही नहीं आई है। आप शिक्षा मंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी। मेरे पास फौजियों की दर्ख्वास्तें आयी हैं, उसका रिकॉर्ड है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपके पास रह गयी होंगी।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : मंत्री महोदय झूठ बोलते हैं इसलिए......

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहां झूठ बोलता हूं ? शायद माननीय सदस्य के पास यह दर्ख्वास्त रह गयी है। अब भी आप मुझे दे दीजिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कैसे मालूम पड़ा कि सदस्य के पास है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बता रहे हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : फौजियों की दर्ख्वास्तों का आपके पास भी रिकॉर्ड है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(विराम)

'एक व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने जो प्रार्थना-पत्र बताया, उस पर मान लेता हूं।

Page No 5

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसमें आश्वासन दे रखा है, आने वाले बजट में इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा माननीय मंत्री महोदय इसके लिए कुछ हद तक सहमत हैं और वे अपने ढंग से कोशिश करेंगे।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.): हमदर्दी तो हमेशा बताते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है।

कोटा-भोपाल रूट की बसों से आय

८६. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०)** : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

१. कोटा भोपाल रूट पर रोडवेज की बसें कब से चल रही है ?

२. उनसे आज कितनी आय हुई है ?

३. उक्त रूट पर भ्रष्टाचार के आज तक कितने केसेज पकड़े गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री रामप्रसाद-लड्ढा): १. दिनांक १७.१०.६३ से कोटा भोपाल मार्ग पर रोडवेज की बसें चालू हैं।

२. दिनांक १७.१०.६३ से जनवरी ६५ तक कुल आय २,०५,२३३.०८ पैसे हुई।

३. कोटा-भोपाल मार्ग पर पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामलों की सूची मय उन पर की गई कार्यवाही के संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री श्रवणलाल : जिनको बगैर टिकट पकड़ा है वे कहा से कहां जा रहे थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में इतना ही है कि वे बिना टिकट थे।

श्री श्रवणलाल : बगैर टिकट तो थे, लेकिन कहां से कहां जा रहे थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस स्थान से कहां जा रहे थे इसकी विगत नहीं दे सकता क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गये उसकी विगत आपको दे दी गई है।

श्री श्रवणलाल : इन २८ व्यक्तियों को एक ही बस में जाते पकड़ा गया और इस पर केवल उसकी एक वेतन की वृद्धि रोकी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सजा दी गई।

श्री श्रवणलाल : २८ व्यक्ति एक ही बस में फ्री चले और उस पर केवल एक वेतन वृद्धि रोकना क्या आप पर्याप्त समझते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेंट द्वारा जो सजा दी गई जिन परिस्थितियों को देखते हुए दी, उससे आपको अवगत करा दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : एक बस में इतने व्यक्ति फ्री चलें और उसके बाद दूसरी बस

Page No 6

(श्री श्रवणलाल)

में ३ आदमी और फ्री जाते हुए पकड़े जायं इतने पर उस कन्डक्टर की एक वेतन–वृद्धि रोकना आप उचित समझते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कहीं कन्डक्टर ने पैसे तो उनसे नहीं ले लिये ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह सब सरकार की नीति के अनुकूल है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जुर्म किया उसके अनुसार विभाग ने सजा दी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकेलरा-सु.) : भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, चोरी क्यों करते हैं, इसकी भी आपने जानकारी की है ? किस कारण से करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कारण तो स्पष्ट है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पूरा खाने को देते हैं क्या ? पूरी तनख्वाह देते हैं क्या ? कन्डक्टर और ड्राइवर दिन में तीन चारा बार चाय पीते हैं उसका भी तो निकालें........

श्री अध्यक्ष : पूरी तनख्वाह वाले भी भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं इसीलिए तो भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बातें न करें। इस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। तनख्वाह का प्रश्न तो दूसरा है। किस कारण वे भ्रष्टाचार करते हैं उनका विश्लेषण करना आवश्यक नहीं।

श्री श्रवणलाल : २८ आदमियों को फ्री ले जाते हुए पकड़ना और उसके बाद तीन आदमियों को और पकड़ना, उस पर एक वेतन वृद्धि रोकने से आप समझते हैं इस प्रकार के कारनामे रुक सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक सजा है उसके बाद अगर और इस प्रकार के मामले पकड़े गये तो सख्त सजा दी जा सकती है नौकरी से निकाला भी जा सकता है।

श्री श्रवणलाल : इन आदमियों को जो सजा दी गई वह उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : साज दी वह उचित है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ऐसे मामलों में जरा सख्त सजा दी जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा परिस्थिति होती है उसके अनुसार दी जाती है।

पाकिस्तान से आये माध्यमिक स्कूलों के विस्थापित अध्यापक

६०. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर-पश्चिम) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान से आये हुए माध्यमिक स्कूलों के

Page No 7

(श्री पोहूमल ईसरदास)

विस्थापित अध्यापकों को जिनके पास बम्बई अथवा सिन्ध के पब्लिक इन्सट्रक्शन विभाग के माध्यमिक प्रमाण-पत्र हैं, प्रशिक्षित अध्यापक नहीं माना जाता है ?

(२) क्या यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने एस. टी. सी. के पश्चात् दस वर्ष के अनुभवी ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षित तथा दिल्ली के एस. ए. वी. के समतुल्य तथा दिल्ली के एस. ए. वी. के समानित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी. टी. बी. एड. तथा एल. टी. के समतुल्य भी माना है ?

(३) क्या यह सही नहीं है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य में सेवा नियुक्त सिंध के ग्रेजुएट एस. टी. सी. ओ. को प्रशिक्षित ग्रेजुएट प्रस्वीकृत (रिकगनाइज्ड) किया गया था तथा हाई स्कूलों में हैडमास्टर के पद पर नियुक्त किया गया था ?

(४) यदि हां, तो ऐसे ग्रेजुएट एस. टी. सी. ओ. को हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किये जाने का अवसर क्यों नहीं दिया गया है, तथा राजस्थान में विलीनीकरण के पश्चात् यह समाहृता (पैरिटी) वापिस क्यों करली गई है ?

(५) क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान सरकार ने फरवरी, १९६२ में आदेश निकाला था कि ५ वर्ष के अनुभवी अप्रशिक्षित ग्रेजुएट्स प्रशिक्षित ग्रेजुएट की वेतन श्रृंखला (ग्रेड) में आने के पश्चात् वरिष्ठता अनुसार हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किये जा सकते हैं ? क्या इस आदेश को प्रभावशील बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस बारे में शिक्षा कमीशन भी विचार कर रहा है, ऐसी हालत में इसको पोस्टपोन किया जाय ताकि सांगोपांग रूप से निर्णय लिया जा सके।

सोडियम सल्फेट कारखाने का उत्पादन

९१. **श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मन्त्री राजकीय उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अप्रेल १९६४ में डीडवाना के सोडियम सल्फेट के कारखाने के चालू होने की घोषणा की गई थी ?

(२) क्या कारखाने का कार्य चालू हो गया है ?

(३) यदि हां, तो कितने दिन काम चला और उत्पादन कितना हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि यह कारखाना बार बार बन्द होता रहता है यदि हां, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्रीरामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं ? ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

Page No 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पिछले बजट सेशन के समय यहां जर्मन इन्जीनियरों ने प्लांट के खड़ा हो जाने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी कर दिए थे और ऐसी आशा दिलाई थी कि कॉमर्शियल उत्पादन जल्दी ही शुरू हो जावेगा। लेकिन प्लान्ट में फिर भी कई त्रुटियां पाई गई; जिनमें से कुछ पूरी कर दी गई है। अब भी तीन जर्मन अभियन्ता परीक्षण में लगे हुए हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) कारखाने ने अभी परीक्षण की स्टेज पूरी नहीं की है। और वह एक्सपेरिमेन्टल स्टेज में है। और जिस कम्पनी ने प्लान्ट सप्लाई किया है उनके इंजीनियर अभी तक इसको पूरा करके राज्य को सम्भलाने के काम में लगे हुए हैं। परीक्षण में तकनीकी-त्रुटियां सामने आती हैं और उनको सही करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं कारणों से कारखाना बार बार बन्द होता है। जब जब ये त्रुटियां आती गई हैं जर्मन इन्जीनियर इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : योजना के अनुसार कब तक उत्पादन शुरू हो जाना चाहिये था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस वक्त तक काम शुरू हो जाना चाहिये लेकिन कुछ खामी ऐसी रह गई है जिसके लिये इन्जीनियर्स कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयत्न करने पर भी अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। वह खामी ठीक हो जाने पर काम शुरू हो जायगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि देश भर में यह एक ही कारखाना इस प्रकार का है, इस पर भी वक्त पर काम चालू न होने से लाखों रुपये के फोरिन एक्सचेन्ज का घाटा होता है ३५० रुपये टन के हिसाब से ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : देश भर में यह एक ही कारखाना है पहला एक्सपेरिमेन्ट राजस्थान में किया गया है, इसको पायलेट प्रोजेक्ट कहते है। इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। बीस टन पर डे उत्पादन करने का कम्पनी के साथ में एग्रीमेन्ट था वह पूरा न होने के कारण हमने इसको टेक ओवर नहीं किया है। कम्पनी को वापिस लिख दिया है, जब तक आप २० टन पर डे प्रोडक्शन करके नहीं देंगे हम इसको टेक ओवर नहीं करेंगे। कम्पनी के एक्सपर्ट्स बराबर काम कर रहे हैं जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के। काम बराबर चल रहा है, अभी भी तीन एन्जिन्स चालू हैं, बीस टन प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, राज्य सरकार उसको लेकर कॉमर्शियल स्केल पर चलायेगी।

प्रश्न संख्या ६२

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

Page No 9

सहकारी भण्डारों का निर्माण

६३. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य में अब तक कुल कितने सहकारी भण्डारों का निर्माण हुआ और इनमें से कितने सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(२) इन सहकारी भण्डारों को अब तक राज्य सरकार ने कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी है और कितनी धन राशि का कर्जा दिया है ?

(३) कर्ज दी गई राशि में से कितना कर्जा वसूल हुआ है और कितना वसूल होने योग्य नहीं रहा है ?

(४) क्या जो धन राशि सहायता के रूप में दी गई है उसका सही उपयोग हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राजस्थान राज्य में अब तक ७०४ सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का गठन हुआ। उनमें से ३८४ भण्डार सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

(२) इन सहकारी भण्डारों को निम्न आर्थिक सहायता दी गई है:—

(१) केश क्रेडिट व अन्य ऋण २१.२५ लाख

(२) हिस्सा राशि अंश दान ५,६५,७५०

(३) अनुदान ३,८२,३०७.३७

(४) व्यापारिक कार्य के लिये ऋण ७२,०००

(३) रु० ७२.२०० जो वसूली योग्य हुआ है उसमें से रु० ५८,५६३ की वसूली हो चुकी है, बाकी की वसूली की जा रही है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, जिनकी वसूली न हो सके।

(४) जी हां, दी गई सहायता का सही उपयोग किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर इस प्रकार के भण्डार हैं वे बन्द हो गये हैं। काम नहीं कर रहे हैं, इसकी आपने जांच पड़ताल की है? जिस समय इनका निर्माण हुआ था क्या उन्होंने काम करने की कोशिश भी की या नहीं ? अगर कोशिश की तो इतने ज्यादा बन्द क्यों हैं ?

दूसरा आपने रुपया जो दिया वह पोइन्ट्स में बताया, उसमें से कितना वसूल हो चुका है ? सेपरेट आंकड़े बताने की कृपा करें।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान में ३८४ भण्डार इस समय सुचारु रूप से काम कर रहे हैं बाकी जो बन्द हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के दर्मियान वस्तुओं के वितरण के लिये बनायी गई थी। वे स्टेट के समय से चली आ रही हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं के देने के लिये जो भंडार निर्मित किये हैं वे काम कर रहे हैं। पुराने

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टेट के समय के जो थे वे बन्द हो गये हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुले थे।

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है, इसमें मैंने पोइन्ट्स में नहीं कहा है। २१ लाख २५ हजार, यह तो कैश क्रैडिट में दिया गया है।

दूसरा हिस्सा राशि अंश-दान में दिया गया, वह कुल रुपया डिफरेन्ट हैड के नीचे उन संस्थाओं को काम करने के लिये दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : पौण करोड़ रुपये के करीब दिया है, पर वसूली के के आंकड़े इतने नहीं होते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : रुपया समय पर ड्यू होता है और जब ड्यू होता है तभी पेमेन्ट होता है। ड्यू होने पर नहीं दिये जाने का केवल एक केस है अजमेर कोऑपरेटिव स्टोर्स का। ७२ हजार ड्यू हैं इसमें से ५८ हजार वसूल कर लिया गया है। बाकी की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। औरों का भी जब ड्यू हो जावेगा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने बताया कि कुछ बन्द पड़े हैं उनमें वार पीरियड के हैं, तो जो नये बने हैं उनमें से भी कोई बन्द पड़ा है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : ये भण्डार दो स्कीमों के तहत चल रहे हैं एक सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड हैं, दूसरे पंचसाला योजना में स्टेट के अन्डर में हैं। इसके नीचे १६० भण्डार हैं और ८ जिले की उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं। बाकी १६०, जिनकी आबादी ५० हजार से ऊपर है उन कस्बों में लागू की हैं यह योजना।

श्री विजयसिंह झाला : नये भण्डार कितने बने ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ये जो उपभोक्ता भण्डार बने हुए हैं इनमें महायुद्ध के समय के कितने हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया टोटल संख्या कितनी है और जो बंद हैं उसका कारण बता दिया। ३८४ भण्डार सुचारू रूप से काम कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मै जानना चाहता हूं कि नये भी ऐसे हैं कितने उपभोक्ता भण्डार, जिनको सहायता दी गई हो और बन्द पड़े हों ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नये ऐसे नहीं हैं। नाम कहें आप तो जिलेवार पढ़ सकता हूं। उनको रिवाइटेलाइज कर दिया गया है। १६० भण्डार चल रहे हैं इनमें से कोई बन्द नहीं है इस वक्त तक तो जब तक यह कन्ट्रोल का मामला चल रहा है।

लड़कियों के लिये माध्यमिक पाठशाला

६४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में अभी तक लड़कियों के लिए कोई

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

माध्यमिक पाठशाला सरकार द्वारा नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि सांचोर में लड़कियों की स्कूल के लिये ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के अनुदान द्वारा एक अच्छा स्कूल भवन का निर्माण कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार अगले सत्र में सांचोर में लड़कियों के लिये एक माध्यमिक पाठशाला खोलना उपर्युक्त समझेगी ? .

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, क्योंकि न तो यहां पर मिडल स्कूल के लिए भवन की व्यवस्था है और न ही लड़कियों की मिडल स्कूल के लिए पर्याप्त संख्या है ।

(२) प्राइमरी स्कूल के लिये भवन जनता द्वारा तैयार करवाया गया है लेकिन मिडिल स्कूल के लिए नहीं । छात्राओं की संख्या में से प्रतीत होगा कि वहां मिडल स्कूल खोलना सम्भव नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां पर प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का उसका भवन बनेगा । अब मिडल स्कूल रेज करेंगे तो उसके लिये अलग से भवन बनाने की क्या आवश्यकता है ? प्राइमरी स्कूल में ही मिडल स्कूल नहीं खुल सकती क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भवन की समस्या तो मैं बाद में लूंगा पर पहले लड़कियों की संख्या ले लूं । क्लास पांच में एक लड़की है और उसकी भी सगाई हो गई है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सगाई से क्या मतलब ? क्या अब वह पढ़ेगी नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो तथ्य बता रहा हूं ।

श्री हीरा भाई : शादी के बाद आपने वकालत की या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी भी वकालत की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): और उसमें भी फेल हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो एक लड़की की सगाई हो गई है । पता नहीं वह आगे पढ़ेगी कि नहीं ? छठी में १५ की संख्या होनी चाहिये । तो अब संख्या तो पर्याप्त कर दीजिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले सत्र में दस लड़कियां हो जावेंगी । आज भी लड़कियां छठी क्लास में हायर सैकण्डरी में लड़कों के साथ पढ़ रही हैं । आपके पास पूरी जानकारी नहीं है । आप लड़कियों की स्कूल तो खोलते नहीं, प्राइमरी में वे जा नहीं सकती, तो फिर कहीं न कहीं तो उनको पढ़ने जाना पड़ता है । वहां की करीब एक लाख १६

Page No 12

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हजार की पूरी जनसंख्या वाली तहसील में लड़कियों की एक भी मिडल स्कूल नहीं। ३ कमरे बना दिये हैं और बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब डाइरेक्टर के यहां से चिट्ठी आई है कि तीस हजार रुपया दो तो खोलें। आप कहते हैं लड़कियों के लिये तो छूट रक्खी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैंने तो एक आधार को कहा है लड़कियों के प्रश्न पर।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वहां प्राइमरी स्कूल के लिये भवन है। मिडल के लिये ८ कमरे, एक कमरा हैड मास्टर का, एक स्टोर रूम और एक पानी का, और छठी में १५ लड़कियों की संख्या चाहिये। आप विश्वास कहां तक दिलावेंगे?

श्री रघुनाथ विश्नोई: दस लड़कियों के लिए आपका नियम है और लड़कों के लिए १५ का है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: छठी में १५ लड़कियों के होने का आप विश्वास दिलावेंगे तो मैं भी इसमें प्रयास करूंगा।

राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा विज्ञापन-प्रकाशन पर व्यय

९७. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम ने गत दो वर्षों में किन किन दैनिक साप्ताहिक, मासिक अखबारों या पुस्तकों में अपना विज्ञापन प्रकाशित कराया है? इसकी सूची व प्रत्येक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पुस्तकों में छपाये गये विज्ञापनों की धनराशि प्रति वर्ष की सदन की मेज पर रक्खें हैं

(२) उदयपुर जिले में कितने वेयर हाउस हैं और गंगानगर जिले में कितने वेयर हाउस हैं?

(३) क्या इन विज्ञापनों को सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया था?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के दो वर्ष (१९६२–६३ व १९६३–६४) में जिन जिन अखबारों व पुस्तकों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है उनकी सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी है। इन विज्ञापनों के कार्यकर्ताओं को जो शुल्क दिया गया है वह भी परिशिष्ट 'क' में प्रत्येक अखबार व पुस्तिकाओं के सामने अंकित कर दिया है। यह राशि १९६२–६३ में १०७२·५० व १९६३–६४ में २३८०) है।

(२) उदयपुर जिले में दो वेयर हाउस और गंगानगर जिले में ८ वेयर हाउस हैं।

(३) इन विज्ञापनों को सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से प्रकाशित नहीं करवाया गया है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 13

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूची दी है और जो आंकड़े दिए हैं इस सूची के अनुसार क्या यह सही है कि ३६ में से २० विज्ञापन सिर्फ उदयपुर के अखबारों को दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो सूची है वह सदन की मेज पर रख दी है और आपके हाथ में भी है।

श्री मानिकचंद सुराणा : सूची के अनुसार उदयपुर में २ और गंगानगर में ८ वेयर हाउस हैं। अब जहां ८ थे वहां के एक भी अखबार को विज्ञापन न देना और जहां केवल दो थे वहां ३६ में से २० को दे देना कौन सी सरकार की सही नीति है और किस आधार पर यह तय की गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह राज्य सरकार की नीति कतई नहीं है। वेयर कॉर्पोरेशन इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी है जिसके डाइरेक्टर को विज्ञापन देने का अधिकार है: राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इस प्रकार दिए गए विज्ञापनों को डिसप्रोपोर्शनेट और अनुचित नहीं मानती सरकार ?

श्री मथुरादास माथुर : यह क्वेश्चन अवर है। इन्फोर्मेशन के लिए होता है ओपीनियन जानने के लिए नहीं होता।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं ओपीनियन नहीं सीक कर रहा। पर क्लीयरकट यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के एक कॉर्पोरेटेड बॉडी स्वायत्त शासन के नाम से खड़ी कर दें और पैसा तो लेजिस्लेशन से दें, और किसी तरह का कन्ट्रोल, इस तरह से फिजूलखर्ची और पक्षपात के मामले में न लेजिस्लेचर का हो और न मंत्रीजी का है और न मंत्रीजी डिफेन्ड करने की पोजीशन में हैं और न कहने की पोजीशन में हैं कि वे इसे उचित नहीं समझते ?

श्री मथुरादास माथुर : यह भारत और राज्य सरकार की धन–राशि से बनता है। अगर हमारे नीचे आप दे देंगे तो शिकायत की कम ही गुंजाइश रहेगी।

श्री मानिकचंद सुराणा : उसे देने न देने का अधिकार आप नहीं मानते और अगर आप अपने नीचे लेना उचित समझते तो विधान सभा को मूव करना क्या आप उचित नहीं समझते ?

श्री मथुरादास माथुर : इससे इन ओटोनोमी बोडीज में खलल पड़ेगी ?

श्री मानिकचंद सुराणा : कोई खलल नहीं पहुंचेगी। यह हजारों रुपयों का अपव्यय है। जिस जिले में दो हैं वहां के बीस अखबारों को विज्ञापन दे दिया जाय और जहां आठ हैं वहां बिल्कुल न दिया जाय और बाकी के विज्ञापन सिर्फ जयपुर, भीलवाड़ा और कलकत्ता के अखबारों में दिए जायें, यह कहां उचित है; फिर कलकत्ता के अखबारों को देने से मतलब क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : वैसे इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता। तो भी मैं निवेदन

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कर दूं कि विज्ञापन उनको दिया जाता है जिनका सर्कूलर राजस्थान में हो। इन्डस्ट्री जिस जिले में है उस जिले के ही अखबारों को नहीं देते, बल्कि राजस्थान भर के अखबारों को देते हैं जो वहां सक्यूं लेट होते हैं। वैसे बाहर के अखबारों को भी देते हैं। ये जिले तक ही सीमित नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आप डी० पी० आर० की पॉलिसी बता रहे हैं, मैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बात पूछता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : डी० पी० आर० और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की फिलॉसफी अलग अलग नहीं हो सकती, इस दलील पर कि वहां पर दो हैं और वहां पर ८ हैं इसलिए उनको नहीं दिया जाना चाहिए और उनको दिया जाना चाहिए, यह धारणा तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बल्कि आप यह कहें कि वहां पर दिया गया; और जगह नहीं दिया गया, उसका क्या कारण है तो उसके लिए तो बीती की बात है। आगे के लिए संचालक महोदय को आपकी विचारधारा हम कन्वे कर देंगे करना नहीं करना उनका काम है। मैं तो उसमें दखलन्दाजी करता नहीं हूं, क्योंकि वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ यह कह देना कि उनको बुलाकर कह देंगे काफी नहीं है....

श्री मथुरादास माथुर : और मैं क्या करूं?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप राज्य सरकार के मंत्री है और आपको सोवरिन पॉवर्स दी हैं और आप मंत्री की हैसियत से कहते हैं कि मैं क्या करूं?

श्री मथुरादास माथुर : पचास-पचास रुपये के एडवर्टाइज़मेन्ट्स में मैं इन्टरफियर कहां करूं?

श्री रामकिशन (बैर) : सवाल रकम का नहीं है? सवाल तो अनियमितता का है; नियम भंग का है। उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी?

श्री मथुरादास माथुर : अगर करप्शन होगा तो मैं बराबर दखल करूंगा, लेकिन यह करप्शन का सवाल नहीं है। सिर्फ २००० का मामला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सब फेवरेटिज्म है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

छात्राओं के लिए छात्रावास

९६. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील में छात्राओं के लिए एक भी छात्रावास नहीं है?

Page No 15

(श्री हरलाल मीणा)

(२) क्या सरकार प्रतापगढ़ में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है ? यदि हां, तो अब तक प्रतापगढ़ में आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रावास क्यों नहीं खोला गया ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) फिलहाल नहीं।

(३) अन्य समीपवर्ती जिलों की तहसीलों में आदिवासियों की जनसंख्या प्रतापगढ़ तहसील की आदिवासी जनसंख्या से कहीं अधिक है। अत: पहले वहां आदिवासी कन्या छात्रावास खोले गये थे।

श्री हरलाल मीणा : कब तक खोलने का विचार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने प्रश्न के भाग २ के उत्तर में बताया कि फिलहाल अभी नहीं।

श्री हरलाल मीणा : जिले में एक भी छात्रावास है क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रतापगढ़ तो तहसील है।

श्री हरलाल मीणा : चित्तोड़ जिले में आदिवासी कन्याओं का एक भी छात्रावास है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : लड़कियों का नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : छात्रावास खोलने के लिए कितनी कन्याओं की संख्या होनी चाहिए ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रश्न बजट का है। जितना प्रावधान होता है उसी के अनुसार कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

देवली में आवास गृह बढ़ाने हेतु भारत सेवक समाज को ठेके

९७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि चीनी नजरबन्दियों के लिए देवली में आवास बनाने हेतु भारत सेवक समाज को ठेके दिये गये थे ? यदि हां, तो वे ठेके कितने लाख के दिये गये ?

(२) क्या इन ठेकों के लिए और ठेकेदारों ने भी टेन्डर दिये थे ? यदि हां, तो किन किन ने और कितने के ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि अन्य ठेकेदारों के टेन्डर नीचे होते हुए भी ठेके भारत सेवक

Page No 16

(श्री रामकिशन)

समाज को ही दिये गये हैं और बाद में भारत सेवक समाज ने ५ प्रतिशत अधिक लेकर अन्य ठेकेदारों को भी अपने में शामिल कर लिया ?

(४) क्या यह सत्य है कि जो मकानात बनाये गये हैं वे बहुत कमजोर अवस्था में हैं और उनकी छतें चूती हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, ८, ६८, ६३६) रु० का ।

(२) जी हां । सूची संलग्न है ।

(३) जी नहीं, जोन डी तथा ई के कार्य भारत सेवक समाज को दिये गये हैं जो अन्य ठेकेदारों की रेट से कम थे । इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(४) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन : आपने जो कहा है प्रश्न संख्या ३ में कि ऐसी जानकारी नहीं है तो आपने जांच कराई क्या ? अगर कराई है तो उसका परिणाम आप सदन के सामने रखने को तैयार हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात की जांच ?

श्री रामकिशन : जैसे भारत सेवक समाज ने ऊंची रेट पर ठेका लेने के बाद भी दूसरे ठेकेदारों को दे दिया गया । यह किससे जांच कराई ?

श्री हरिश्चन्द्र : रेट कम होने से ही उनको दिया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सदस्य का कहना यह है कि जो आपने भारत सेवक समाज को ठेका दिया वह कार्य उन फर्म ने नहीं किया बल्कि अन्य ठेकेदारों से ५ प्रतिशत मुनाफा लेकर भारत सेवक समाज ने काम कराया, ऐसी जानकारी है आपके पास ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : शतप्रतिशत ऐसा हुआ है । क्या अब आप ऐसी जानकारी कर लेंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या

६८. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग में विभाग के अधीन कितने होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट, इन्सपेक्टर व अन्य राजपत्रित अधिकारी हैं जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं ? उनके नामों की सूची पदवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No 17

(श्री सांवलियाराम)

(२) अन्य जातियों के उक्त तीनों श्रेणियों के व्यक्ति कितने हैं ? उनके नामों की सूची, पद व उनकी योग्यता सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या समाज कल्याण विभाग में उक्त जातियों के लिये साढ़े बारह प्रतिशत नियुक्तियों में रिज़र्वेशन की अभिपूर्ति की गई है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के १८ होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, ४ इन्सपेक्टर्स, इन्वेस्टीगेटर्स व १ राजपत्रित अधिकारी हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अन्य जातियों के ६३ होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २२ इन्सपेक्टर, इन्वेस्टीगेटर और १२ राजपत्रित अधिकारी हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां !

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जो लिस्ट दी है उसमें अलग अलग नहीं बताया है। इसके अलावा मेरा एक और मकसद था कि होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट जो छात्रावासों में लगे हुए हैं वह सब समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये गये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं इसलिए वहां पर सभी होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट या अधिकारी सब उसके ही क्यों नहीं लगाये शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, इनके लगाने में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि लिस्ट दोनों को मिलाकर के ही दी है और दूसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि जो लोग हैं वे इन्टीग्रेटेड सर्विसेज के हैं जो कि विभिन्न राज्यों में काम करते चले आ रहे थे, इसलिए उनको अलग करना सम्भव नहीं है।

श्री सांवलियाराम : समाज कल्याण विभाग तो अभी स्थापित हुआ है इसलिए इनको हटाकर दूसरी जगह लगा दीजिये और जितने समाज कल्याण विभाग में काम करने वाले लोग हों व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के क्यों नहीं हो सकते ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दूसरी स्टेट्स में बराबर वह काम करते चले आ रहे थे इसलिए इन्टीग्रेशन में उनको यहां इस विभाग में लगा दिया गया इसलिए उनको हटाना उचित नहीं दीखता।

श्री सांवलियाराम : उचित तो है। जगह यहीं थोड़े ही है और भी जगह तो जगह हैं। यहां तो उन आदमियों की जरूरत है जो कि पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हों क्योंकि उन्हीं के लड़के वहां पर पढ़ते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जरूरी नहीं है कि जो अनुसूचित जाति के होस्टल हों उनमें वही लोग काम करें। धीरे धीरे यह

Page No 18

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

भेदभाव मिटने वाला है और सबको साथ मिलकर ही काम करना होगा ।

श्री सांवलियाराम : उच्च वर्ग के लोग छूआछूत बरतते हैं ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : यह ठीक नहीं रहेगा कि जो अनुसूचित जाति के छात्रा-वास हैं वहां पर सवर्ण जाति के लोग लगायें और दूसरी जगह सवर्ण जाति के जहां छात्रावास है उनमें हरिजन लोगों को लगाया जाये इससे उचित वातावरण बनेगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ९९

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए

श्री बिरदाराम फुलवारिया ।

जालोर जिले में डिग्री कॉलेज

१००. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. जालोर जिले की आवश्यकताओं और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार वहां कब तक डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : १. जालौर में कॉलेज खोलने के विषय में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा विचार किया जावेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो ५ साल की होगी । यही तो लंबा-चौड़ा विषय है । कोई निश्चित अवधि तो होनी चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगली साल बाड़मेर में खोल रहे हैं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अभी प्लानिंग मिनि-स्टर ने कहा कि चतुर्थ योजना में आपकी भावनाओं का आदर करते हुए पहली साल में खोलने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह जिला इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर पैसे वाले तो मिलते नहीं हैं, इसलिए सारी स्कूल और कॉलेज खोलने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे जिलों के लिए कुछ तो राज्य सरकार नीति निर्धारित करे कि इन इन कठिनाइयों के कारण वे पिछड़े हुए न रहें ।

श्री मथुरादास माथुर : बाड़मेर जिले के लोगों ने २ लाख रुपया बिल्डिंग के लिए देना तय किया है । उसमें कुल ६ लाख रुपया लगेगा । वहां की जनता ने यह आश्वासन दिया है, और जालौर के अन्दर भी मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य कोशिश करें और जैसा कि वहां के भूतपूर्व प्रमुख और एम० एल० ए० ने

(श्री मथुरादास माथुर)

कहा है उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया है कि २ लाख रुपया दे देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : २ लाख में तो आप आश्वासन देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनको कहा है कि २ लाख रुपया जमा करा दो और बिल्डिंग की कार्यवाही अगले साल अप्रेल में शुरू करवा देंगे। लेकिन जहां तक जालौर का सवाल है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले साल में खुल जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार की पॉलिसी है ? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस तरह से दो लाख रुपये कोई नहीं दे और प्लान पर उनको खर्च ज्यादा करना पड़े, यह क्राइटेरिया आप ऐलान करके कहते हैं। क्या यह पॉलिसी है कि दो लाख रुपया हो और रुपया हो तभी उनके बच्चे पढ़ सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह राज्य सरकार की नीति नहीं है। मगर जहां पर लोग रुपया इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों की इच्छा है वहां के प्रमुख ने लिखकर भेजा है कि मैं दो लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, फिर इन्कार कैसे कर दिया जाये ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रुपया लिये फिरते हैं ऐसी बात नहीं है। कोशिश करते हैं और फिर मुकर जाते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सवाल यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है। वह उनको दें इसमें मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आपने यह कहा कि किसी एक आदमी ने कह दिया कि दो लाख रुपये देंगे और वह नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो आपका क्या कर्तव्य है ? आप उसकी युटिलिटी और मेरिट पर केस को क्यों नहीं सोचगे कि वहाँ पर कॉलेज की जरूरत है और १००-१०० मील पर उनको जाना पड़ता है तो क्यों नहीं खोलेगी सरकार ? अब पैसा नहीं मिले तो खोलेगी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी जो फिलॉसफी है उसको राज्य सरकार मानती है, कि जहां की जनता गरीब है और उनके पास पैसा नहीं है वहां पर यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां की जनता ज के पास पैसा है और जनता पैसा देने को तैयार है और थोड़ी सी कोशिश करने पर मिल जाता है तो वहां पर पैसा लेकर सोच सकते हैं और एक्सचेकर पर उसका भार न पड़े तो जो बचा हुआ है पैसा वह शिक्षा के प्रसार में काम आ सके।

श्री अध्यक्ष : (श्री ज्वालाप्रसाद के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज़ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम हुआ है राजस्थान के समस्त जिलों में से सिर्फ दो ही जिले ऐसे हैं कि जहां पर कॉलेज नहीं है। उन दो जिलों में से जालोर एक ऐसा जिला है जहां कि कॉलेज नहीं है। तो कुछ लोगों से सौदागिरी जो आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, लेकिन मान लीजिये

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि २ लाख रुपया आपको नहीं मिले तो आपका उत्तरदायित्व जालौर की प्रजा के प्रति कुछ है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल है और वह पूरा निभाया जायगा ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपने कहा कि पैसा होगा तो खोलेंगे और नहीं होगा तो नहीं खोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री भिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : जालौर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है, वहां कब तक खोलेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जालौर जिले में लखपति बैठे हुए हैं । भाखरा में, भीनमाल में और जालोर में हैं; क्या बात करते हैं आप ?

टौंक नगर में बिजली बन्द रहने का कारण

१०१. श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टौंक नगर में अगस्त, १९६४ में कब कब कितने कितने समय के लिए बिजली बन्द रही ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) बार बार बिजली बन्द होने का क्या कारण था ?

(३) भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाया गया है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) तेज वर्षा और आंधी के कारण तार टूट गये थे ।

(३) हर दूसरे महीने लाइन का पेट्रोलियम करा दिया जाता है और जो भी खराबी दृष्टिगोचर होनी है ठीक करा दी जाती है । यदि बीच में कोई खराबी होती है तो पार्टी तुरन्त भेज दी जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, पहले वहां पर जो एन्जिन था उसको इस विश्वास के साथ हटाया गया था कि इसके बदले में दूसरा इन्जिन ले आया जायेगा, लेकिन यह सूची भी शायद सही नहीं है । तीन दिन तक लगातार लाइट एक साथ बन्द रही थी और इसमें एक साथ १ घंटा ४० मिनट बताया है । इसलिए मन्त्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

श्री चन्दनमल वैद : ११ घण्टे ४० मिनट बताये हैं । १ घंटा ४० मिनट नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ७ तारीख को १ घंटा ४० मिनट बताया है, जबकि ६, ७ व ८ तारीख तक लगातार बिजली बन्द रही है ।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : टाइप गलत हो गया होगा ।

श्री चन्दनमल बैद : टाइप की गलती नहीं, पढ़ने की गलती हो सकती है ।

प्रश्न संख्या १०२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सिंचाई प्रयोजनों के लिए बिजली

१०३. **श्री केदारनाथ शर्मा** (गंगानगर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर में सिंचाई प्रयोजनों के लिए कुओं पर बिजली लेने के लिए कितनी दरख्वास्तें चल रही हैं और उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद) : राजस्थान विद्युत् मंडल को १६ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए वे जिनमें से ३, जगह कनेक्शन्स दिए हुए हैं । गङ्गानगर जिले में इस वर्ष २० स्थानों में बिजली की सुविधा दी गई है । इन स्थानों में १६ कुओं पर बिजली देने के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार हो रहा है । जल्दी ही इन्हें भी कनेक्शन दे दिये जायेंगे । आगामी वर्ष में ३१ स्थानों पर बिजली देने की प्रस्तावना है ।

श्री केदारनाथ शर्मा : ये दरख्वास्तें कितने अर्से से पेंडिंग हैं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह स्टेट तो अभी पास है नहीं । आपको बताया नहीं है कि १६ दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, उनमें से तीन को दे दिया है और वहां पर धनराशि कुछ कम होने से दूसरे केन्द्रों को नहीं दी गई है । वह जहां तक होगा जल्दी ही दिलवा देंगे ।

श्री केदारनाथ शर्मा : आपको अभी भाखरा के कॉमन पूल से १५ हजार किलोवाट बिजली सरप्लस मिली है । उसमें से कुछ गङ्गानगर के इलाके में जो कुए सिंचाई पर्पज के लिए बनाए गए उनके लिए रिजर्व करना आपके विचार में है ?

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा : १७ हजार कहां पर ?

श्री केदारनाथ शर्मा : १५००० किलोवाट भाखरा कॉमन पूल में से जो पंजाब सरकार ने आपको देना मन्जूर किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कहां पर, किस जगह ?

श्री केदारनाथ शर्मा : राजस्थान सरकार को ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो राजगढ़ ग्रीड में आयेगा ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिए क्या कर रहे हैं ?

Page No 22

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, this is a different Question,

प्रश्न संख्या १०४।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०५

श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६

वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

क्राफ्ट विषय के अध्यापक

१०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि हायर सैकन्ड्री कक्षाओं में क्राफ्ट विषय पढ़ाया जाता है तथा उसके लिए संस्थाओं में अध्यापकगण नियुक्त हैं ?

(२) उक्त अध्यापकों में से कितने पी० एस० सी० द्वारा एप्रूव्ड हैं तथा उन्हें किस ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है ?

(३) कितने क्राफ्ट अध्यापक बिना पी० एस० सी० के एप्रूवल के किस वेतन पर व ग्रेड पर काम कर रहे हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि पी० एस० सी० अनएप्रूव्ड क्राफ्ट टीचर्स की अस्थाई नियुक्ति को समय समय पर बढ़ाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सच है कि उक्त अध्यापकों को आरम्भ में ११०-२२५ व १५०-३०० का ग्रेड दिया गया और और अब ग्रेड समाप्त कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब से व क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ-आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार राजस्थान में केवल ६ अध्यापक पी० एस० सी० के एप्रूव्ड हैं (मैट्रिक पास का ७५-१६० व ग्रेजुएट का १३०-२५० की ग्रेड दी जाती है।)

(३) जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ३०७ अध्यापक बिना पी० एस० सी० के एप्रूव्ड हैं। इनमें जो मैट्रिक पास हैं उनकी भी ७५-१६० व ग्रेजुएट की १३०-२५० की वेतन श्रृंखला दी जा रही है।

(४) जी हां, ऐसे अध्यापकों को जो ऐसे ग्रेडों में नियुक्त किये गये थे जिनकी एप्रूवल पी० एस० सी० से आवश्यक थी उनके पी० एस० सी० से एप्रूव्ड होने अथवा पी० एस० सी० से एप्रूव्ड अध्यापक न मिलने के कारण समय समय पर नियुक्ति का समय बढ़ाया गया। जो पी० एस० सी० एप्रूव्ड नहीं हैं उन्हें स्थाई तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(५) पहले ११०-२२५ की वेतन श्रृंखला में क्राफ्ट अध्यापकों को ऑफिशि-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

येटिंग प्रमोशन दिये गये थे परन्तु नवीन वेतन श्रंखला जो १-६-६१ से लागू की गई है उनके अनुसार ट्रेन्ड ग्रेजुएट की ग्रेड केवल उन्हीं अध्यापकों को दिया जा सकता है जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट हों। अतः ऐसे क्राफ्ट अध्यापक जो केवल हाई स्कूल व डिप्लोमा प्राप्त हैं १-६-६१ को ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड पाने के अधिकारी नहीं हैं जब तक कि वे ग्रेजुएट की योग्यता न प्राप्त करें। नवीन वेतन श्रंखला में ११०-२२५ व १५०-३०० की वेतन श्रंखला क्रमशः ११५-२५० व १७०-३३५ में परिणत कर दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि आरम्भ में जब क्राफ्ट टीचर्स को नियुक्त किया गया था तब उनके साथ ग्रेजुएट या मेट्रिक होने की कोई शर्त नहीं रखी थी और उनको केवल क्राफ्ट ट्रेन्ड टीचर्स होने की ग्रेड दी गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस शर्त का प्रश्न पैदा नहीं होता हैं। एपौइन्टमेन्ट के आधार पर किया गया है। किसी का न तो फेवर किया है और न कुछ किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ में जब क्राफ्ट टीचर्स को नियुक्त किया गया था उस समय उनका ग्रेड निर्धारित करते समय वह अन्तर नहीं रखा था कि अमुक व्यक्ति मेट्रिक या ग्रेजुएट है। उनको ट्रेन्ड ग्रेजुएट की एक ग्रेड दी थी। अब यह निर्धारित किया जा रहा है कि वह मेट्रिक है या ग्रेजुएट है तो इस प्रकार की आरम्भ में कोई शर्त नहीं थी। उनके लिए आरम्भ में उनको नियुक्त करते समय यह शर्त नहीं थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आरम्भ में तो उनको नियुक्त कर दिया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह नियुक्त होने के पश्चात् कितने समय तक क्राफ्ट टीचर की ग्रेड पाते रहे। वह जो कि आरम्भ में उनकी ग्रेड थी और जिसमें कि मेट्रिक या ग्रेजुएट का प्रश्न नहीं था तो यह क्राफ्ट टीचर कितने साल तक काम करते रहे उस ग्रेड में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १-६-६१ तक जब कि रेशनलाइज्ड ग्रेड हुआ है उस समय तक ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने साल पहले तक वे आपके यहां उस ग्रेड में सर्विस देते रहे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी सूचना, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या यह सही है कि म्यूज़िक और ड्राइंग टीचर को ट्रेन्ड गेजुएट की शर्त हटाकर उनको ट्रेन्ड ग्रेजुएट की ग्रेड दे रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है मुझे, पता नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि जो शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के अध्यापक हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है लेकिन उनको जो ग्रेड दी जा रही है वह १३० की दी जा रही है न कि इस आधार पर, जो कि आज आप वता रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह भी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि हर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स अपने क्षेत्र में क्राफ्ट टीचर्स को अलग अलग तरह के ग्रेड्स देते हैं। एक जगह एक तरह का दिया जा रहा है तो दूसरी जगह दूसरा ग्रेड दिया जा रहा है। क्या सारे राजस्थान में इनके ग्रेड्स का रेशनलाइजेशन नहीं होगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अलग अलग नीति है। नीति के संबंध में एक चीज निर्धारित क्यों हो, क्या न हो; इस पर विचार किया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अधूरा मान कर पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा भी यही निवेदन है।

प्रश्न संख्या १०८

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०९

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

अजमेर में रोडवेज़ का बस स्टेशन

११०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर में राजस्थान रोडवेज़ का बस स्टेशन बनाये जाने में इतनी देर क्यों लग रही है ?

(२) क्या यह सही है कि वर्तमान में वहां शेड भी नहीं हैं और शौचालय आदि का प्रबन्ध भी नहीं है ? यदि हां, तो अगर स्टेशन बनने में समय लगने की संभावना हो तो कम से कम अस्थाई तौर पर ही शौचालय आदि का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अजमेर में शीघ्र ही बस स्टेशन बनाने की योजना यातायात निगम के विचाराधीन है।

(२) जी हां। वर्तमान बस स्टेशन ऐसे स्थान पर है जहां अस्थाई तौर पर शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह बस स्टेशन कब तक बन जायगा ? कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें जल्दी ही कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जल्दी-जल्दी सुनते हुए तो बहुत से दिन हो गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; जमीन का तकाजा था, अब जमीन ले रहे हैं।

प्राइवेट बंगलों के निर्माण से सरकारी सामान

१११. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा के सिटी सब डिविज़न (१) के असिस्टेन्ट इंजीनियर तथा ओवरसियर की देखरेख में प्राइवेट बंगलों का निर्माण हुआ है और इस काम में सरकारी मिस्त्री तथा मजदूरों से काम लिया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सरकारी काम के नाम पर सरकारी सामान स्टोर से इन्डेन्ट द्वारा निकलवाकर प्राइवेट बंगलों में लगाया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है कि सरकारी कर्मचारियों ने बंगले बनाये हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों से काम लिया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक पत्र में चर्चा निकली थी। स्वयं जानकारी के लिये पूछा गया तो मालूम हुआ कि कोई सामान या कोई आदमी, मकान बने हैं, उनमें काम में नहीं लिये गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगों के पास प्रूफ्स ही नहीं बल्कि फोटो-ग्राफ्स मौजूद हैं कि सरकारी सामान किस प्रकार ले गये। दुःख का विषय तो यह है कि गम्भीर आरोप लगाने पर भी जांच नहीं कराई गई।

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास और भी गम्भीर आरोप हों तो बताइये।

श्री रामकिशन : आपने बताया कि अखबार में सूचना निकली, तो क्या आपने पता लगाया कि किस किस ने मकान बनाये……

श्री अध्यक्ष : नाम बताने की आवश्य-कता नहीं है।

श्री रामकिशन : बड़े बड़े अफसरों ने मकान बनाये हैं, और उनके खिलाफ शिकायत हुई है .. ....

श्री अध्यक्ष : जांच के बाद उसको तथ्यहीन बताया है।

श्री रामकिशन : जांच भी हुई या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमने स्वयं ने जांच कराई, उसका नतीजा यह निकला कि सामान या सरकारी कर्मचारी काम में नहीं लाये गये। आपके पास प्रमाण हों तो बताइये, और जांच करवा लेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस अधिकारी के द्वारा जांच की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर के द्वारा जांच कराई गई ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आपने यह संतोष किया है कि जांच अधिकारी ने जिस पत्र में यह सूचना निकली है उस पत्र के प्रनिनिधि को भी इस संबंध में एग्जामिन किया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : राष्ट्रदूत में प्रकाशित हुआ था।

श्री रामकिशन : पत्र वालों से जानकारी किये बिना आपको कैसे जानकारी हुई कि सरकारी सामान काम में नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि उन्होंने जांच करवा ली। माननीय सदस्य के पास अगर और तथ्य हैं तो उन्होंने कहा है कि वे दे दें और जांच करवा लेंगे।

श्री रामकिशन : हम तथ्य देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : तो जांच हो जायेगी।

जालौर के प्राचीन किले की मरम्मत

११२. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या शिक्षा (पुरानन्द) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जालौर के प्राचीन ऐतिहासिक और दर्शनीय किले की शीघ्र मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां, विभाग इस दिशा में सक्रिय है और इसकी मरम्मत के लिए गत वर्ष ५०००) रु० की राशि भी विभाग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। परन्तु निर्माण विभाग ने अभी इस कार्य को सम्पन्न नहीं किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : विभाग सक्रिय है, लेकिन खाली सक्रिय कहने से काम नहीं चलेगा, राज्य सरकार ने आज तक क्या किया, यह बताइये ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : यह काम केन्द्रीय आर्चियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट का है या राज्य के ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी तो राज्य सरकार ने ही इसके लिये पैसा मंजूर किया है।

Page No 27

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तो फिर अब तक काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निर्माण नहीं किया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या निर्माण विभाग और आपके विभाग में को ऑर्डिनेशन नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है ।

श्र [illegible]नाथ बिश्नोई : यह बहुत बड़ा किला है । यह प्रश्न आने के बाद ही आपने सोचा होगा कि इसकी मरम्मत करानी चाहिये जब कि मरम्मत बहुत पहले करानी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कह रहे हैं कि गत वर्ष रुपया मंजूर हुआ था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं निर्माण विभाग से आग्रह करूंगा कि ५०००) रु. से मरम्मत शीघ्र करावे । अब शिथिलता दिखाई नहीं देगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हमें शिक्षा मंत्रीजी के प्रति गंभीर शिकायत है कि वे सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति बहुत उदासीन हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति इतना सजग हूं कि बाहर भी आपकी सहायता करता रहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने योजना नहीं बताई कि क्या कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । श्री गोकुलचन्द ।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, ५०००) रु० मरम्मत के लिये काफी नहीं हैं; यह किला बहुत लंब-चौड़ा है, दूर दूर के लोग इसे देखने आते हैं, यह बहुत पुराना किला है इसको अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिये । इतने कम पैसे से कुछ नहीं होगा ।

प्रश्न संख्या ११३

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचंद ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कोटा शहर के स्कूल

११४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा शहर में प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है और प्रत्येक स्कूल की किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र, छात्रायें पढ़ती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उपरोक्त स्कूलों के लिये भवनों की क्या व्यवस्था है ? कौन कौन सा स्कूल

Page No 28

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल)

किराये के मकान में चलता है और किस स्कूल के पास सरकारी भवन है ?

(३) राजस्थान बनने के बाद कोटा शहर में कितने प्राइमरी तथा कितने मिडल स्कूलों के लिये सरकारी भवन बनाये गये हैं ?

(४) क्या सरकार कोटा शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए प्राइमरी तथा मिडल स्कूलों के भवन सरकारी तौर पर बनाने का इरादा रखती है ?

(५) यदि हां, तो शहर के इर्द गिर्द तमाम भूमि जनता को मकान बनाने हेतु दे दी गई, तो फिर स्कूलों के लिये जमीन की किस प्रकार व्यवस्था हो सकेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह सूचना भी प्रश्न भाग (१) के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित हैं ।

(३) कोई नया भवन नहीं बनाया गया सूरजपोल मिडल स्कूल को नहर योजना के कारण तुड़वा दिया गया था, उसके एवज में गुमानपुरा कोटा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाकर शिक्षा विभाग को सौंप दिया ।

(४) सरकार की आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार द्वारा नए भवन बनवाना सम्भव नहीं है ।

(५) कोटा का मास्टर प्लान अभी प्रारूप मान चित्र है, जो अभी सरकार के विचाराधीन है । इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में में कोटा की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए जमीन की व्यवस्था है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' : कोटा शहर में ५५ स्कूलें प्राइमरी की चलती हैं जिनके लिये एक भी नई इमारत नहीं बनाई हैं १८ साल हो गये हैं । कुछ स्कूलें गरीबों के मुहल्लों में चलती हैं । थेगड़ा आदि में जहां छोटे-छोटे गरीब लोग रहते हैं वहां स्कूल भवन का प्रबन्ध वे गरीब खुद करते हैं और जहां बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं वहां सरकार खुद किराया देती है । अभी पहले एक प्रश्न का जवाब दिया था अध्यक्ष महोदय, देवली, खेड़ली, बालीता, बड़गांव–ये ऐसे स्थान हैं जहां छोटे लोग, मजदूर लोग रहते हैं वहां प्राइमरी स्कूलों का इन्तजाम लोगों को खुद को करना पड़ता है, और जहां शहरी सीमा में जो स्कूलें बड़े बड़े मुहल्लों में आती हैं सरकार किराने के मकानों में स्कूल चलाती है । शहर में ५५ स्कूल किराये पर सरकार चलाती है, जब कि गांवों में मास्टर प्लान चल रहे हैं, सब जगह भवन एक साथ बनेंगे नहीं, इसमें दिक्कत आयेगी; इसके लिये सरकार ने क्या योजना रखी है, स्कूलों के भवन बनायेंगे या नहीं·······

श्री निरंजननाथ आचार्य आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ।

Page No 29

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सत्य है कि....

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले इनका तो उत्तर दे दूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप उनका सवाल नहीं समझे इसलिये स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप शहरों के साथ पक्षपात करते हैं गांवों के लिये मास्टर प्लान क्यों नहीं रखा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि मास्टर प्लान में प्रावधान है।

श्री भैरवलाल काला बादल—नहीं साहब, मास्टर प्लान बना लेकिन सब प्लॉट्स को बेच दिया। तीन बार मास्टर प्लान बदल गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह मास्टर प्लान बना था या हैडमास्टर प्लान बना था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मण्डी कमेटी बनाकर सारी जमीन बेच दी गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपके सवाल जब तक मास्टर प्लान का इनको ज्ञान नहीं हो तब तक वाजिब हैं। मास्टर प्लान में कहां कहां प्ले ग्राउन्ड हों, कहां कहां मदरसे की बिल्डिंग वगैरह हों इन सबका प्रावधान किया गया है। जब तक उस पर पूरा विचार न हो जाय तब तक मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं कि उसमें आपकी जो शंकायें हैं उनका समाधान किया गया है। हम उसके सम्बन्ध में जागरूक हैं। कोटा में हायर सैकन्डरी स्कूल्स, कॉलेज और उनके प्ले ग्राउन्ड्स और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल—उन सबके लिए एलोकेशन उचित स्थान में मास्टर प्लान में किया गया है।

अब रहा सवाल कोटा में स्कूलों का तो १६ प्राइमरी स्कूल्स तो किराये की बिल्डिंग में हैं और कुल हैं ५५ प्राइमरी स्कूल्स। अभी माननीय सदस्यों ने एक अभिव्यक्ति दी थी कि शहरों को ज्यादा सहायता दी जाती है। स्कूलों के प्रश्न पर। मैं उस सम्बन्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि शहर का मामला कोटा का, लेकिन वहां पर स्कूल ५५ हैं, उनमें से १६ हैं, जो किराये की बिल्डिंग में है। दूसरे सरकार के एडेड इन्स्टीटयूशन्स को मिला कर ३९ की संख्या है। लड़कियों के दो हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं; एक में बस चलती है और एक में नहीं है।

प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि वे पास पास में हैं, दूर नहीं है। जब मैंने यह कहा कि ५५ प्राइमरी स्कूल हैं तो उसमें यह स्थिति भी हो सकती है कि किसी इलाके में जैसा कि आपने कहा, मजदूरों के इलाके का प्रश्न आता है, उसमें स्कूलों की कमी हो सकती है। लेकिन ५५ स्कूलों के बारे में गांवों के संतुलन से शहरों को देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी नीति है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने हैं। शहरों में ज्यादा स्कूल खोलते जायं तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उचित मालूम नहीं होता है। लेकिन फिर भी यथाशक्ति जहां कहीं मजदूरों के इलाके में स्कूल की जरूरत है वहां प्राइमरी स्कूल खोले है और फिर भी विचार किया जा सकता है। जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, प्राइमरी स्कूलों में लड़कियां भी जाती हैं, छोटे-छोटे बच्चों के साथ लड़कियां पढ़ती हैं और...

श्री नत्थीसिंह : भाषण हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर ज्यादा संख्या लड़कियों की हो जाती है तो उनके लिए पाठशाला खोली जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल। आपका अगला प्रश्न भी इससे सम्बन्धित है।

कोटा के मास्टर प्लान में स्कूलों-कालेजों के लिये सुरक्षित स्थान

११५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा सिटी में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा की तरफ शिक्षा विभाग का अधिक उत्साह नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या शिक्षा विभाग ने लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिये हैं कि कोटा सिटी के नये बनाये जाने वाले मास्टर प्लान में गर्ल्स माध्यमिक शाला, हायर सैकन्डरी स्कूल तथा कॉलेज की इमारतों के लिये अमुक अमुक वार्डों में भवन बनाने के लिये प्लॉट सुरक्षित कर दिये जायें ?

(३) यदि हां, तो किस स्थान पर कन्या माध्यमिक शाला, गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल व गर्ल्स कॉलेज के लिये कोटा के मास्टर प्लान में स्थान सुरक्षित किये गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि छावनी, गोरधनपुरा, कोठरी, मेड़ी एरिया, फैक्ट्री एरिया, छत्रपुरा, सिन्धी कोलोनी, बल्लभ बाड़ी, वल्लभ नगर व गुमानपुरा क्षेत्र की छात्रायें शिक्षा से इसलिये वंचित रह जाती हैं कि इस क्षेत्र में न तो माध्यमिक शाला है न हाई स्कूल, न प्राथमिक शाला ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : मास्टर प्लान का इसमें कह चुका हूं पहले।

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) कोटा का मास्टर प्लान अभी ड्राफ्ट मास्टर प्लान है जो सरकार के विचाराधीन है। इसी ड्राफ्ट मास्टर प्लान में कन्या माध्यमिक शाला, गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल, गर्ल्स कॉलेज के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं परन्तु निश्चित स्थान विस्तृत प्लान बन जाने के बाद ही निश्चित होंगे।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(४) जी नहीं, क्योंकि छावनी, गोरधनपुरा व गुमानपुरा में कन्या प्राथमिक शालायें चल रही हैं। कोठरी व गुमानपुरा में कोई दूरी नहीं है। अतः अलग अलग दोनों स्थान पर पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। केवल गुमानपुरा की कन्या पाठशाला इस समय भवन के प्राप्त न होने से एक दूसरे वार्ड मोखापाठा में चलाई जा रही है। भवन की काफी तलाश की जा रही है परंतु उपलब्ध नहीं है। गुमानपुरा में लड़कों की प्राथमिक शाला अवश्य चल रही है और उसमें छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। इन स्थानों पर माध्यमिक शाला व उच्च शालाएं नहीं हैं। मेंडी एरिया, फैक्ट्री एरिया छत्रपुरा, सिन्धी कोलोनी, वल्लभवाड़ी व वल्लभनगर में कन्या शालाएं नहीं हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): यहां तो माध्यमिक शालाओं में लड़कियों की कमी नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह पूछेंगे तो बताऊंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं पूछ सकती हूं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मंत्री महोदय जवाब देते हैं वह घुमा-फिरा कर जवाब देते हैं। यह लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है; छावनी, गोरधनपुरा, कोठरी, मेडी एरिया,-जहां कहीं भी स्कूल नहीं है। वहां की लड़कियां जाती हैं-रामपुरा बाजार में, जो दो,तीन, चार मील के फासले पर हैं। इन लड़कियों के स्कूल में ऑफिसरों की लड़कियां तो कारों में चली जाती हैं लेकिन गरीबों की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं और सरकार कहती है कि लड़कियां इतनी दूर पढ़ने जाती हैं। इतने लम्बे-चौड़े एरिया में इसका प्रबन्ध क्यों नहीं करते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्योंकि कोटा का विकास हो रहा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कोटा का विकास हो रहा है लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं है। यह विचार कर लें कि मास्टर प्लान में इस तरह व्यवस्था वार्ड में बनाने जा रहे हैं कि पांच स्कूल चल रहे हैं वार्डों में, वहां तो स्कूल चलायें नहीं है। और अलग तरह की अलग कोलोनी चलायें इन स्कूलों की ? इसका क्या कारण है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि छात्र और छात्राओं की संख्या को देखते हुए कोटा शहर के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल-चाहे किराये की बिल्डिंग में हों चाहे सरकारी भवनों में हों-वे संख्या में बहुत कम हैं। तो क्या सरकार दूसरी बिल्डिंग किराये पर लेने का विचार कर रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने निवेदन किया, किराये की बिल्डिंग में जो प्राथमिक शाखाएं चल रही हैं-उनके सम्बन्ध में अभी कोई बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था सरकार कर सकती हो-ऐसी संभावना नहीं है। जहां तक यह प्रश्न है कि प्राथमिक शालाओं की न्यूनता है या नहीं,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तो जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया, ५५ प्राथमिक शालाएं हैं, उनकी न्यूनता देखी जाय तो सारे शहर और गांवों में स्कूल नहीं रख सकते हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने मजदूर एरिया के लिए कहा है वहां पर प्राथमिक शालाएं नहीं हैं। सारे कोटा नगर की ५५ प्राथमिक शालाओं को ध्यान में रखते हुए इस ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी मैं यही निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

ग्राम बरगमा, तहसील हिन्डौन में ग्राम बैंक सहकारी संस्था

११६. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ग्राम बरगमा, तहसील हिन्डौन में ग्राम बैंक के नाम से कोई सहकारी संस्था थी ?

(२) यदि हां, तो यह कब बनी और इसके कितने शेयर थे ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस समय यह संस्था कार्य कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): जी हां, यह सच है कि ग्राम बरगमा, तहसील हिन्डौन, जिला सवाई माधोपुर में बरगमा सहकारी ग्राम बैंक लि० बरगमा के नाम से सहकारी संस्था थी।

(२) इस संस्था का पंजीयन १६-६-१६४७ को हुआ तथा इसके ३१ शेयर थे।

(३) जी नहीं, यह सच नहीं है कि इस समय यह संस्था कार्य नहीं कर रही है।

श्री श्रवणलाल : यह कब से नहीं कर रही है ?

श्री रामकिशन (वैर) : कभी से नहीं कर रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा, यह सच नहीं है कि इस समय यह संस्था कार्य नहीं कर रही है।

वित्त-मन्त्र (श्री बालकृष्ण कौल) : कर रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

महारानी तथा महाराजा कालेजों की प्रयोगशाला

६२. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) महारानी कॉलेज तथा महाराजा कॉलेज जयपुर की विज्ञान की विभिन्न

Page No 33

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रयोगशालाओं के वार्षिक बजट क्या है ? कॉलेजवार तथा विषयवार सूचित करें।

(२) क्या यह सही है कि इन प्रयोगशालाओं में एपरेटस तथा केमिकल्स का सर्वथा अभाव है तथा एक एक एपरेटस पर कई कई विद्यार्थियों को एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त दो कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में पानी का सर्वथा अभाव रहता है ? जिसके कारण कई बार प्रयोग नहीं हो पाते तथा विद्यार्थियों की शिक्षा को काफी नुकसान हो रहा है ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में तुरन्त सुधार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

बल्लभनगर तहसील के ग्रामों में बिजली

९९. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वल्लभनगर तहसील में वल्लभनगर, मेणार, रून्डेडा, लवणियां, भटेवर व दरोली ग्रामों को बिजली देने की व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

वल्लभनगर तहसील में दरौली गांव का विद्युतिकरण गत वर्ष के दिसम्बर माह में हो चुका है।

वल्लभनगर तहसील मे बटेवर गांव को इस वर्ष के मार्च महीने तक बिजली देने की सम्भावना है।

बल्लभनगर, तहसील में, वल्लभनगर को बटेसर से जोड़ने का प्रस्ताव अगले वर्ष के सुझाव में सम्मिलित कर लिया गया है। आशा है कि यह कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण हो जायेगा।

वल्लभनगर तहसील में मेणर, रून्डेडा लवणियां गांवों के विद्युतिकरण का कार्य अभी तक किसी योजना में स्थान नहीं पा सका है।

हायर सैकन्डरी स्कूल सिकराय में दो कमरे बनाए जाने की स्वीकृति

१०२. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हायर सैकन्डरी स्कूल सिकराय में दो कमरे बनाए जाने हेतु १९६३-६४ व १९६४-६५ के बजट में १४०००) रु. की स्वीकृ तिविभाग ने दी थी?

Page No 34

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

(२) यदि हां, तो वे कमरे आज तक नहीं बनने का क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार वर्तमान बजट ६४-६५ में ही वे दोनों कमरे बनवाने का इरादा रखती है ?

(४) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्थानीय जनता व पंचायत ने श्रमदान से ६ कमरे इस स्कूल के लिये तामीर करा दिए हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां ।

तहसीलों व पंचायत समिति हैडक्वार्टरों पर जूनियर व हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जाने हेतु उठाये गये कदम

१०४. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या प्रत्येक तहसील व पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर जूनियर हायर सेकेन्डरी व हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये सरकार कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां ।

कठूमर गांव के बीच में डामर की एप्रोच रोड

१०५. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कठूमर (अलवर) गांव के बीच में से एक एप्रोच रोड बनाने का कार्य कब आरम्भ किया गया था ?

(२) उस रोड पर, जो मिट्टी की बनाई गई है, कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) उस रोड पर सीलिंग वगैरह डालना व डामर की बनाने का कार्य क्यों पूरा नहीं किया गया ?

(४) अब कब तक वह एप्रोच रोड डामर की बनाई जा सकेगी ?

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा इस सड़क पर कार्य आरम्भ नहीं कराया गया है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No 35

ग्राम वजीरपुर में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने की मांग

१०६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम वजीरपुर, तहसील गंगापुर का प्रतिनिधि मन्डल ५ मार्च, १९६४ को शिक्षा मन्त्रीजी से मिला था ?

(२) क्या यह सही है कि उस समय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि राजस्थान में कहीं भी हायर सैकन्डरी स्कूल खोलेंगे तो ग्राम वजीरपुर को प्रथम अवसर दिया जायेगा? क्या यह सही है कि वजीरपुर ग्राम के प्रतिनिधि मन्डल से मन्त्री महोदय ने यह लिखित में ले लिया कि दो वर्ष का पूरा खर्च ग्रामवासी वहन करें ?

(३) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने के बारे में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की यह सिफारिश थी कि जिले में प्राथमिकता वज़ीरपुर को दी जावे ।

(४) वर्ष १९६४ में राजस्थान में कितने हायर सैकन्डरी स्कूल खोले गये हैं और कहां कहां ? उसकी सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

(५) क्या यह सही है कि १९५८ में वर्तमान शिक्षा मन्त्री महोदय वजीरपुर पधारे थे तब ग्रामवालों को यह आदेश देकर आये थे कि ग्राम वाले मकान तैयार करा देंगे तभी कसैहायर न्डरी स्कूल वजीरपुर में खोल दिया जावेगा ?

(६) क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय के आदेश पर ग्राम वजीरपुर वालों ने मकान तैयार करा दिया है ? यदि हां, तो फिर भी वहां स्कूल न खोलने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) स्मृति में नहीं ।

(२) स्मृति में नहीं परन्तु आश्वासन जैसा कोई प्रश्न नहीं था ।

(३) जी हां, निरीक्षक शिक्षणालय करौली के इस वर्ष १९६४ में माध्यमिक शाला वजीरपुर को उन्नत करने का प्रस्ताव किया था । छात्र संख्या की दृष्टि से प्रथम विचारणीय वजीरपुर था । लेकिन वहां की जनता प्रथम वर्ष में १६,१००) रुपया व द्वितीय वर्ष में २५०००) रु० जमा कराने में असमर्थ थी और इसी कारण इस पर विचार नहीं हुआ ।

(४) चालू वर्ष में जहां जहां जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल खोले गये हैं उनकी सूची संलग्न है । कोई हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खोला गया ।

(५) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । वजीरपुर ग्रामवासियों से संख्या का पूरा भवन बनाने का आश्वासन लिखित रूप से निरीक्षक शिक्षणालय को दिया था परन्तु जनता ने भवन बनाने की व्यवस्था नहीं की ।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(६) वजीरपुर की जनता भवन की व्यवस्था न कर सकी। अतः वहां पर स्कूल न खोला जाना स्वाभाविक है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रोडवेज़ की बसों से दुर्घटनायें

१०८. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में राजस्थान रोडवेज़ की बसों के कितने कितने एक्सीडेन्ट्स हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि अधिकतर ये एक्सीडेन्ट्स गाड़ियों के ब्रेक वगैरह ठीक न होने के कारण हुए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इन एक्सीडेन्ट्स के बाद कई गाड़ियां महीनों तक थानों व अदालतों में जमानत न दिये जाने के कारण खड़ी रहीं और इस कारण सरकार को भारी हानि हुई ?

(४) यदि हां, तो उपरोक्त ऐसी गाड़ियों की सूची, मय उनके नम्बर एवं गाड़ी खड़े रहने की अवधि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सन् १९६२-६३, ६३-६४ व ६४-६५ में राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की गाड़ियों के होने वाले एक्सीडेन्टों की संख्या मय गाड़ी नं० दिनांक, स्थान व एक्सीडेन्टों के कारणों तथा डिपो से बाहर रहने के अर्से की सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। ब्रेक की खराबी से होने वाले एक्सीडेन्ट्स की संख्या बहुत कम है।

(३) जी नहीं। सिर्फ एक गाड़ी १२ दिन तक गैरिज से बाहर रही। अन्य सभी गाड़ियां दो या चार दिन बाद जमानत देकर प्राप्त कर ली गई।

(४) गाड़ियों की सूची, जो एक्सीडेन्ट के कारण गैरिज से बाहर रहीं, मय नं० एवं खड़े रहने की अवधि के संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक शाला से हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१०९. श्री **अब्दुलजब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या माध्यमिक कन्याशाला निम्बाहेड़ा को हायर सैकन्ड्री स्कूल बनाया जा रहा है ?

(२) क्या सरकार इस शाला को अप ग्रेड करने हेतु भवन निर्माण में जनता से सहयोग चाहती है ? यदि हां, तो कितना ?

Page No 37

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

(३) क्या अपेक्षित रकम की व्यवस्था होते ही राज्य सरकार द्वारा स्कूल को अपग्रेड करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) अन्य ऐसे ही स्कूलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर विचार किया जायगा।

(२) जी हां। चार कमरे २०" × २०" के तथा २ कमरे १०"×१०" की आवश्यकता होगी।

(३) उपयुक्त भवन बनाने पर निर्धारित रकम जमा कराने पर यदि यहां लड़कियों की उपयुक्त संख्या हुई तो अन्य ऐसी स्कूलों के साथ २ इस स्कूल के लिये भी विचार किया जायगा।

कठूमर में बिजली

११३. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है खेड़ली मन्डी जिला अलवर में गत वर्ष बिजली पहुँच गई उसका उद्घाटन मुख्य मन्त्री ने किया था

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि उसी दिन पंचायत समिति हैडक्वार्टर "कठूमर" की ओर से हायर सैकन्ड्री स्कूल भवन का शिलान्यास भी मुख्य मन्त्री ने किया था ?

(३) क्या यह बात सही है कि एक विशाल सभा में मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि कठूमर में बिजली सन् १९६४ में पहुंच जायगी ? यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है और कब तक कठूमर में बिजली पहुंच जायगी ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि कठूमर के दोनों तरफ नगर व खेड़ली में बिजली पहुंच गई है जो क्रमशः ७ व ६ मील के फासले पर है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस विभाग को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(३) आश्वासन के बारे में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। वस्तु प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां।

(१२. ७ म. म.)

पुरः स्थापित विधेयक

(क) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५.

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री) राजस्व : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति

Page No 38

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरंतर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरंतर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रदान प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि

(क) राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक १९६४

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को ३० मार्च, १९६५ तक बढ़ा किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापक हेतु नियत समय को ३० मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(ख) राजस्थान भू-गृहादि किराया और बेदखली नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि किराया और बेदखली नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को १५ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि किराया और बेदखली नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को १५ मार्च, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१२.१० म. प.)

जयपुर में रिक्शा चालकों की हड़ताल विषयक औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री के वक्तव्य के बाद भी आज तक रिक्शा चालकों का धरना अभी तक चल रहा है और मैं समझता हूं कि आज वे अपने कुटुम्ब सहित जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं भूख हड़ताल कर रखी है। ऐसी स्थिति में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री पुनः बताने की कोशिश करेंगे कि जो वक्तव्य दिया गया उसके पश्चात् भी उन लोगों को धरना देने की क्यों नौबत आई ? जहां तक मैं समझ पाया हूं कि वे अमानवीय कार्य को बन्द करना चाहते हैं, लेकिन रिक्शा-चालकों ने लाइसेन्स रिक्शा चलाने के पहले से ही ले रखे हैं और जब उनके पास लाइसेन्स रिक्शा चलाने का है तो वे रिक्शा मालिकों से लेकर

(श्री विजयसिंह झाला)

रिक्शा चलायेंगे क्योंकि उनके पास ऑल-रेडी रिक्शा चलाने का लाइसेन्स है। वे रिक्शा मालिकों से किराये पर रिक्शा लेकर चलायेंगे। इससे जो समस्या हल करना चाहते हैं वह नहीं होगी और उनको लाइसेन्स नहीं देने से उनका शोषण मालिकों द्वारा जारी रहेगा और उनके आदेशों से रिक्शा मालिक उनका शोषण करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री जी को स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में सरकार की ओर से व्यक्तव्य दे दिया गया है। माननीय सदस्य अगर और कोई बात कहना चाहें तो बहस के दौरान में कह सकते हैं, उसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया जावेगा। इस समय वक्तव्य का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, सरकार सदन के समक्ष अगर कोई नये तथ्य होंगे तो रखेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया, उसके बाद भी आज तक हड़ताल जारी है...

श्री अध्यक्ष : इसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस संबंध में बहस में बातें उठा सकते हैं और सरकार के सामने कोई नये तथ्य होंगे तो सदन में सरकार उसका उत्तर देते समय बता देगी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अभी हड़ताल जारी है और उनके कुटुम्ब की स्त्रियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।...

श्री अध्यक्ष : यह समय इस पर बहस के लिए निर्धारित नहीं है। जो समय पहले जिसके लिए निर्धारित है उस पर बहस होगी। इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकेगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी। आपने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ने कोई सूचना नहीं चाही है और यह सूचना चाहने का सयय नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कोई बात ऐसी नहीं करें जिसके लिए पूर्व सूचना नहीं दी गई हो।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे रहे हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : प्रिविलेज मोशन का जिक्र किया, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता ने जो स्पीच दी उसमें प्रिविलेज मोशन का जिक्र

Page No 41

(श्री बरकतुल्ला खां)

किया गया । जब आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने मेरे पर आरोप लगाये थे तो उसी समय मैंने कहा था कि यह मैं प्रिविलेज का मोशन रखना चाहता हूं उसके बाद कांग्रेस व्हिप नेप्रिविलेज मोशन मूव किया । मेरे पास कोई पॉवर तो नहीं है कि मैं बद्तमीजी कर सकूं कि आपको जबरदस्ती करके कहूँ कि मोशन को लिया जाय । मैंने आपके पास तीन मर्तबा हाजिर होकर दरख्वास्त दी कि आप जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले लें और इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दें ताकि इसका निर्णय हो जावे । हम यह समझते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं हो, जिससे किसी सदस्य पर झूठे आरोप लगें और अगर लगे हों, तो साफ होने चाहिये और सदस्य भी यही चाहते हैं कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिये । क्योंकि सदन के सदस्यों का प्रोटेक्शन आपके हाथ में है और सदन के सदस्यों के लिए सबसे बड़ी कोर्ट सदन ही हो सकता है, इसलिये मैंने सदन के सामने प्रिविलेज मोशन मूव किया । अगर मैंने कोई ऐसी बात की हो तो मुझे मंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं दे देना चाहिये बल्कि एसेम्बली से भी इस्तीफा दे देना चाहिये । मैं इसको चैलेंज करता हूं । मैं जनसंघ के नेता जिन्होंने यह कहा, उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने यह कहा कि मैं उस मोशन को पेश नहीं करना चाहता, जबकि उनको मालूम है कि यह मोशन आपके सामने है । जबकि यह बात मालूम है कि यह मोशन आपके सामने पेन्डिग है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनका यह कहना कि मैं उस मोशन से निकलना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है । हम मिनिस्ट्री में आये हैं तो हमारी भी कोई इज्जत है, लोग हमें भी जानते हैं और हम यह चाहते हैं कि अगर हमने गलती की है तो फिर सजा मिलनी चाहिये और अगर गलती नहीं की है तो दुनिया के सामने यह न हो जावे कि हम बेईमानी करके निकलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अभी मंत्री महोदय ने जो सदन में भाषण दिया है उसके लिए मैं आपका निर्णय चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय का प्रश्न नहीं है, न इन्फोर्मेशन का प्रश्न है । इस पर कोई बहस करके सदन का समय लेना उचित नहीं है । उस पर जो उचित आज्ञा होनी चाहिये वह होगी ।

(१२. ११ म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव श्री अमृतलाल यादव ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे संक्षेप में ही बोलें ताकि ज्यादा सदस्य भाग ले सकें ।

श्री मोतीलाल चौधरी : अपोजिशन के नेता और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं, इन पर मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, इतना ही कहूंगा कि उनको राजस्थान की समस्या को सामने रखना होगा और राजस्थान की समस्या को सामने रखते हुए एमर्जेन्सी, खाद्य की समस्या, भाषा आन्दोलन आदि जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उससे देश के अन्दर कमजोरियां आई हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक देश के सामने ऐसी परिस्थिति और उसकी खाद्य समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद में राष्ट्रभाषा की समस्या खड़ी हुई है और आने वाले समय में राजस्थान में समाजवाद के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को कम से कम समझ पाया हूं। राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया है कि समाजवादी व्यवस्था कायम करने की दिशा में सरकार ने कार्य किया है, और भी कार्य हमें करना पड़ेगा। जो भी कार्य सरकार ने किया है उसको देखते हुए मुझे भय हो रहा है कि समाजवादी समाज की ओर किस तरह ले जाने को तैयार है। इस पर मैं स्पष्टरूप से कहना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस सारे भाषण को पढ़ा है। इस सम्पूर्ण भाषण को देखता हूं तो यह समस्यापूर्ण भाषण है, इसमें कहा गया है कि हमें समाजवाद को लाने के लिये कार्य करने हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से जो जो कार्य सरकार की ओर से किये गये हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको देखते हुए मुझे डर लगता है कि इनमें इन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखते हुए तो हम कहीं समाजवाद से पीछे नहीं हट जायं। सारा इन्वेस्टेमेंट आने वाली सालों का, सारी फोर्थ प्लान का हमारे सामने है, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में व को-ओपरेटिव सेक्टर में कितना इन्वेस्टेमेंट किया गया इनका कम्पेरिज़न करें तो मुझे डर है कि हमारा समाजवाद की ओर का कदम पीछे न हट जाय। ३५ इन्डस्ट्रीज़ को लाइसेंस दिया गया है, उन ३५ इन्डस्ट्रीज़ में से केवल दो ही इन्डस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर में हैं, ३३ इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में गई हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को देखिये। इससे एम्प्लॉयमेंट पर जो असर होने वाला है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन पर असर होने वाला है, इन सबको देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैपिटलिस्ट्स के हाथों में राजस्थान की सारी इन्डस्ट्रीज़ जा रही है।

हम एक तरफ जहां देश में समाजवाद लाने का कहते हैं, दूसरी ओर सब लाइसेंस इन्डस्ट्रीज़ के स्फिअर में केवल प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में, को-ऑपरेटिव सेक्टर में एक भी लाइसेंस नहीं दिया जाय, तो मुझे भय लगता है कि कहीं हमारा कदम समाजवाद से पीछे की तरफ नहीं हट जाय। इसलिये मैं बड़े दुःख के साथ राजस्थान के उद्योग मन्त्री से, खाद्य और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, प्लानिंग मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इण्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, एग्रीकलचर प्रोडक्शन में ? इन्वेस्टमेंट का रेशियो पब्लिक सेक्टर में और को-ऑपरेटिव सेक्टर में नहीं बढ़ायेंगे, तो हमारे यहां राजस्थान में पूंजीवादी व्यवस्था कायम होने का डर है।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जिस दृष्टिकोण से मैंने इस भाषण को पढ़ा, जो दूसरे महानुभाव बोले उनको भी मैंने गौर से सुना और इस सबके बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और सरकार के सामने यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कि जो फोर्थ प्लान का ढांचा आवे उसमें २५ प्रतिशत तो कम से कम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये किये जाने वाले इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट सेक्टर में, को-ऑपरेटिव सेक्टर में नहीं डालेंगे तो आज राजस्थान में दिन ब दिन कैपिटलिस्टिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है वह और बढ़ता जायगा। ब्लैक मनी को निकालने के लिये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्यवाही की है उससे पता लगता है कि लोगों के पास ब्लैक की पूंजी पड़ी हुई है और इन्डस्ट्रीज़ को कैपिटलिस्ट्स कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं और अगर यही रवैया रहा तो चाहे टैक्सटाइल की इन्डस्ट्री हो, चाहे ऊन की इन्डस्ट्री हो, कोई भी इन्डस्ट्री खड़ी की जायगी उसमें केपिटलिस्टिक कैरेक्टर ज्यादा आयेगा।

तो, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां राज्यपाल महोदय ने भाषण में कहा कि लोकतन्त्रीय समाजवाद को कायम करने के लिये दृढ़ता से बढ़ना है वहां जो आंकड़े दिये हैं, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये इन्वेस्टमेंट के आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों को देखते हैं तो भय लगता है। तो सरकार को देखना चाहिये कि किस तरह से इन्डस्ट्रियलाइजेशन करने से हम समाजवाद ला सकते हैं।

दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की समस्या राजस्थान में हमारे राष्ट्र को देखते हुए एक सबसे बड़ी समस्या है। हमें आज राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पर-कैपिटा पर-एकड़ बढ़ाना है पर आज अधिकांश जनता का इन्ट्रेस्ट इन्डस्ट्रीज़ की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग नॉन एग्रीकल्चरिस्ट्स थे उनकी एग्रीकल्चर की तरफ दौड़ लग रही है, जो लोग खेती करने वाले नहीं थे उनका इन्वेस्टमेंट खेती में बढ़ रहा है और जो लोग खेती करने वाले थे वे दूसरे धन्धों की तरफ जा रहे हैं, इस दौड़ को देखते हुए मुझे भय लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जिस तरह का केपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इंगलैंड और यू. एस. ए. में हुआ था उसी तरह का कहीं राजस्थान में भी नहीं हो जाय। व्यक्तिगत पूंजी की दृष्टि से यदि केपिटलिस्ट लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ चले गये, खेती करने वाले लोगों की अगर सरकार ने मदद नहीं की, लोन्स से, फर्टीलाइज़र्स से, केमिकल्स से, आधुनिक कृषि के सब प्रकार के साधनों से, तो मुझे डर है जो इंगलैंड में हुआ था, यू. एस. ए. में हुआ था वही हमारे यहां राजस्थान में होगा जो खेती करने वाले है वे मजदूर हो जायेंगे और जो पूंजीपति हैं वे खेतों के मालिक हो जायेंगे। इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस ओर वह सतर्कता से ध्यान दें। कभी कभी पेपर्स में आता है कि अमुक पूंजीपति भेड़ पालने के लिये धरती ले रहा है, अमुक बड़ा पूंजीपति शीड मल्टिप्लाई के लिये धरती ले रहा है, जिस तरह बिड़ला ने पंजाब में

Page No 44

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भेड़-पालन के लिये धरती ली है, राजस्थान में कुछ पूंजीपति भेड़-पालन के लिये धरती लेना चाहते हैं, इस तरह यदि यही रवैया रहा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर केपिटलिस्टिक कैरेक्टर का कन्ट्रोल हो जायगा।

मैं सबसे बड़ी बात जो राजस्थान सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जो इंग्लैंड और यू. एस, ए. के अन्दर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है और जो प्रगति जापानियों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में की है, इन दोनों को कम्पेअर कीजिये तो इंग्लैंड और यू. एस. ए. में केपिटलिस्ट्स, जमींदार और जागीरदार आगे आये हैं। पर जापान में सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि केपिटलिस्ट्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आगे नहीं आने देकर एग्रीकल्चरिस्ट्स को ही लोन देकर, सीड देकर, फर्टीलाइज़र देकर और सब तरह की सहायता देकर उनकी हालत को बढ़ाया है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पर-केपिटा डेवलपमेंट जापान ने किया है उसी तरह हिन्दुस्तान में भी चलाना पड़ेगा।

आज राजस्थान के किसी अधिकारी से बात करते हैं; सरकार से बात करते हैं; तो यही बात कही जाती है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिये मेकेनिज्म को एग्रीकल्चर में लाना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में मेकेनिज्म को लाने से जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं वे मजदूर हो जायेंगे, केपिटलिस्ट्स आगे आयेंगे। जिन देशों में पॉपुलेशन कम है, वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मेकेनिज्म की जरूरत रहती है हमारे यहां राजस्थान में तो फर्टीलाइज़र सीड देकर; लोन देकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहां मेकेनिज्म की जरूरत नहीं है। इस बारे में मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा।

राजस्थान के किसान के पास जो खेती को बढ़ाने के साधन हैं, उनमें सबसे बड़ा एनीमल हस्बेन्डरी है। एनीमल हस्बेन्डरी को आगे नहीं बढ़ायेंगे तो हमारे यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकेगा। ५ होर्स-पॉवर के ट्रेक्टर पर, ६ हार्स पावर के ट्रेक्टर पर, सरकार लोन देती है। किसान के पास बैल हैं, जिनको भुलाकर आज ट्रेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। हिन्दुस्तान में हम गायों को, बैलों को मार नहीं सकते। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बैल रहेंगे या ट्रैक्टर रहेंगे तो इन ५ होर्स पॉवर के, ६ होर्स पॉवर के और १४ हार्स पॉवर के ट्रैक्टर्स से बैलों का कम्पीटिशन होने वाला है; आज नहीं तो ५ साल बाद कम्पीटिशन होगा। एक न एक दिन यह कम्पीटिशन अवश्य होगा। राजस्थान की एग्रीकल्चर पॉलिसी यहां के बैलों से, गायों से, ऊंटों से, भेड़ों से सम्बन्धित है।

यहां के बैल के साथ संबंध है, यहां के ऊंट के साथ संबंध है, यहां के भेड़ के साथ संबंध है, उसका कैपीटल इन्वेस्टमेंट, उसका डेवलपपेट एनीमल हस्बेंडरी से

(श्री मोतीलाल चौधरी)

होने वाला है। ५० ट्रैक्टर्स, ५० बैलों की जोड़ी को खेत से निकालते हैं। ५० साल में कितने ट्रैक्टर्स आएंगे। पिछले एक साल के अंदर १२ के ऊपर ट्रैक्टर्स आए। ट्रैक्टर्स जो हिन्दुस्तान के अंदर इम्पोर्ट हुए हैं; उनकी एक एक की कीमत १३ हजार रुपये है और जो हिन्दुस्तान में मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी कीमत १६ हजार हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रैक्टर डेवलपमेंट हों, एग्रीकल्चर में आएं; लेकिन उसको साथ में प्लानिंग करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बहुत गंभीरता से देखा। फूड प्रोडक्शन की समस्या के संबंध में ६ महीने पहले के चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। गुजरात और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स ने एक बात कही कि यदि हम हिन्दुस्तान की यूनियन में रहते हैं तो राजस्थान का फूड प्रोडक्शन हमको देना पड़ेगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन किस किमत पर ? एक तरफ राजस्थान का किसान तो गरीब रहे और गुजरात का अमीर रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कैस्टर सीड १९५५-५६ में एक एकड़ जमीन में भी नहीं था लेकिन १९६१-६२ में २ लाख एकड़ जमीन में कैस्टर सीड आता है। इसी तरह से वेल सीड जहां पहले महाराष्ट्र में १० लाख एकड़ था वहां आज ५१ लाख एकड़ है। इसके बाद शुगर केन है, उसका किस तरह से रेश्यो गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ा है। किस रेश्यो में क्रोप पेटर्न चेंज हुआ है ? इसलिए मेरा कहना है कि हमारा काश्तकार गरीब रहेगा और वहां का काश्तकार साहूकार रहेगा। मुझे आपत्ति नहीं कि इस पेटर्न को डेवलप करें। अगर फूड प्रोडक्शन राजस्थान में करना है तो राजस्थान को राष्ट्रीय दृष्टिकोण को देखना है। मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि राजस्थान का काश्तकार फूड प्रोडक्शन करे। पिछले १० साल में जितना प्रोडक्शन बढ़ गया है, राजस्थान कैनाल के बाद, या माही के बाद या ट्यूब वेल्स के डेवलपमेंट के बाद हो सकता है कि राजस्थान अकेला ही हिन्दुस्तान की फूड प्रोडक्शन को मिटा सकता है; लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यहां का काश्तकार गरीब रहेगा तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारे प्रदेश का काश्तकार पॉपूलेशन का ८० परसेंट है तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है इसीलिए मेरा सुझाव है कि रेगिस्तान के इलाके में जहां फूड प्रोडक्शन हुआ है, वहां काश्तकार को कम से कम एक रिलीफ दिया जाय; कि जो फूड प्रोडक्शन करता है। उस इलाके के काश्तकार से लैंड रेवेन्यू न लिया जाय, जमीन पर उनको इन्सेंटिव दिया जाय। लोकस्ट को मारने की व्यवस्था है, स्टेट कॉन्ट्रिब्यूटरी फंड देता है इसलिए सारा स्टेट जो फंड चाहती है उस इलाके को माफ करती हैं, और करना चाहती है, क्योंकि कैश का प्रोडक्शन की दृष्टि से राजस्थान में अकाल में पानी नहीं पहुंचने वाला है उसको ट्रैक्टर से कम्पीट करना पड़ेगा; तो ऐसे काश्तकार की इकानोमी गिरेगी, ऐसे इलाके में फूट

(श्री मोतीलाल चौधरी)

प्रोडक्शन करना है। हमें दूसरी स्टेट्स को भी अन्न देना है, हिन्दुस्तान की खाद्यान्न स्थिति को सुधारना है तो जिस जमीन का मालिक किसान को बनाया है, उसको इन्सेंटिव दिया जाय, लैंड रेवन्यू से फ्री किया जाय ताकि उसकी हिम्मत बढ़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर फूड प्रोडक्शन के अंदर बढ़ावा देना है तो उसका रिलीफ दिया जाय।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ग्रामीण जनता की भलाई के लिए, मुझे एक बात पढ़ने को नहीं मिली। मैं आशा करता था कि फोर्थ प्लान या थर्ड प्लान के एंड के अन्दर एक बात सरकार जरूर करेगी, वह यह कि पिछले १७ साल के अंदर जो हमारा टेक्निकल स्टाफ बढ़ा है उसके अंदर रेश्यो देखते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वेटेरिनरी डॉक्टर्स एग्रीकल्चरल साइंस के ग्रेजुएट्स के अंदर तो १०:६० का रेश्यो मिलता है। अगर ६० आदमी शहर के इंजीनियर या डॉक्टर्स बनते हैं तो १० आदमी गांव के बनते हैं। मैं सोचता था, शायद सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही थी। जिस देश का समाजवाद का ढांचा ही गांवों पर निर्भर है, जहां पर ८० प्रतिशत गांव की आर्थिक हालत, सामाजिक हालत, शिक्षा और टैक्नोलौजी की हालत गांव के निवासियों के उत्थान पर निर्भर है, वहां किस प्रकार आप देश के अन्य भागों के समकक्ष ला सकेंगे? किस प्रकार सत्ता को ला रहे हैं? इसलिये सरकार को फोर्थ प्लान के अन्दर निश्चित रूप से इस ओर कदम उठाने चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज इन्जीनियरिंग कॉलेज में, गांव का रेश्यो डेफिनिट रूप में रहे। पचास प्रतिशत लड़के आप गांव के भर्ती कीजिये और ५० प्रतिशत शहरों के। डॉक्टर लोग आज गांवों में जाते नहीं हैं, जाना चाहते नहीं; शहरों में ही बैठे रहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, आपको सुन कर बड़ा दुख होगा कि अभी मैंने डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल एण्ड हैल्थ का स्टेटमेन्ट देखा है उसमें उन्होंने बताया है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर १८८ हैं, उनमें से ८८ पर डॉक्टर नहीं हैं। राजस्थान में डॉक्टर नहीं, यह कहा जाता है। एक प्रश्न था कि देवगढ़ में या भीलवाड़ा में कहीं लेडी डॉक्टर नहीं हैं। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि शहर में जाना नहीं चाहते। बड़े शहरों में रहने वाले हैं, वे गांव में जाना नहीं चाहते। आप उनको गांवों में जाने के लिए १००), १५०) रूरल अलाउन्स के तौर पर दीजिए। एग्रीकल्चर में, इन्जीनियरिंग कॉलेजेज़ में एडमिशन के टाइम पर आप ५० प्रतिशत गांव के लोगों को एडमिशन दीजिए और ५० प्रतिशत शहर वालों को। यदि गांव में रहने वाले ८० प्रतिशत लोगों में कोई आप टैक्निकल एजुकेशन नहीं बढ़ायेंगे तो न तो आपकी खेती की उन्नति होने वाली है, न पशुपालन की ओर, न आगे जाकर ही आपका समाजवाद ही आने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मोतीलाल चौधरी)

इसके बाद एक बात और अन्त में निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के उन इलाकों के लिए जिनके लिए पिछले तीन साल से और अगले तीन साल के लिए इसमें आंकड़े हैं पेय जल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की दृष्टि से १५ शहर में होंगे तो २० गांव में होंगे। कितना रुपया गांव के लिये खर्च हो रहा है, यह देखने का है ? शहर का एक प्रोजेक्ट, आप अजमेर शहर को पानी देने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको ही ले लीजिए, अकेले प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा है उसके मुकाबले सब गांवों के जितने प्रोजेक्ट हैं और उनका खर्चा है वह है । अजमेर का प्रोजेक्ट १।। करोड़ का है और गांव के प्रोजेक्ट सब मिलाकर १, १।। करोड़ के होंगे । यदि काश्तकार को ड्रिंकिंग वाटर आदमी के लिए और पशुओं के लिए सहूलियत से नहीं मिलता है तो आप निश्चित समझिये कि एग्रीकल्चर नहीं बढ़ सकेगा। एक किसान खेती करता है रेगिस्तान में वह कहां से पानी ले जाता है ? बीकानेर और जोधपुर का पूरा डिवीजन और जयपुर का आधा हिस्सा, झुंझुनू और सीकर, किसान खेती करता है, पीने के लिए पानी दो कोस से ले जाता है, पशुओं को दो कोस पर पानी पिलाने के लिए ले जाता है, यहां तक कि उसको पांच कोस से पानी लाना पड़ता है। आप देखिए कि किसान को कितनी लेबर करनी पड़ती है। इसलिए मेरा ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था के लिए निवेदन है। हमने घग्घर के पानी के लिए मांग की थी। ड्रिंकिंग वाटर की दृष्टि से चूरू, बीकानेर, सीकर, नागौर और झुंझुनू को आप दीजिये पानी। उस पानी को गंगानगर में सिंचाई के लिए ले लिया है। जो काश्तकार प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनको पानी नहीं है, उनके कैटल डेवलपमेन्ट के लिए पानी नहीं है। उस हिस्से में दूध, अन्न आदि प्रोड्यूस करने की काफी गुन्जाइश है, लेकिन पानी नहीं है। सारा इलाका एनीमल हस्बेन्डरी पर है, लेकिन बढ़ोत्तरी के साधन आपने नहीं जुटाये। सबसे पहली समस्या उनकी पानी की है। इसके बिना उनकी सारी गुन्जाइश बन्द हो गई है। इसलिए मैं आपकी मार्फत एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है उसको सामने रखते हुए, आप इरिगेशन के प्रोजेक्ट को बन्द रखिए, लेकिन पीने के पानी की जो समस्या है उसकी आप पहले व्यवस्था कीजिए। सारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट भी इसीलिए रुका हुआ पड़ा है । नागौर, चूरू कहीं पर भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हुआ। सीमेन्ट वगैरह का सबसे अधिक रॉ-मेटिरियल यहां पर है । रेगिस्तान के इलाकों में इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करने के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण वे सब दबे पड़े हैं। बीकानेर में जिप्सम का डेवलपमेन्ट नहीं हो सका।

फर्स्ट क्लास सोप स्टोन नागौर में है, पिग-आइरन है, सीमेन्ट और अन्य फैक्ट्रीज़ वहां पर नहीं लग रही हैं। इसका कारण क्या है ! कारण यही है कि वहां पर पानी नहीं है। पानी मिल जाय तो उद्योग हो सकते हैं । इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि घग्घर, राजस्थान नहर का पानी ३०० फिट लिफ्ट लगा कर उनको दीजिए।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आपने अजमेर को पानी देने के लिए १४०० फीट लिफ्ट दिया, केवल तीन लाख पोपुलेशन के लिए। लेकिन यहां तो लाखों आदमियों को पीने के लिए पानी और खेती और उद्योग के लिए पानी पहुंचाने में २५०—३०० फीट लिफ्ट देनी पड़ती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर ने कोई इसके लिए कॉन्ट्रिब्युशन नहीं किया होगा, लेकिन इस इलाके के लोग १५ पर्सेन्ट कॉन्ट्रिब्युशन इसके लिए देने के लिए तैयार हैं। यदि उनको पानी मिल जाय तो ब्लड बैंक में अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। अजमेर के प्रोजेक्ट से प्रोडक्टिविटी नहीं है लेकिन यहां तो लाखों आदमियों को पानी देना और उनके पशु धन और अन्य उद्योगों को डेवलप करना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी यदि उनको पानी नहीं मिलेगा तो समाजवाद कैसे आवेगा ? यह मुझे समझ में नहीं आता।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। वह यह है कि सरकार ने पिछले साल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की मिनिमम कीमत बाध दी। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इस बात के लिए राजस्थान की सरकार को राजस्थान के किसान बहुत धन्यवाद दे सकते हैं और वे काबिल भी हैं इसके। काश्तकारों को यह एक रिलीफ मिला है कि उसके भाव नीचे नही जावेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ साथ मैं, माननीय अध्यक्ष, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आदेश सरकार ने निकाले हैं उनका प्रचार नहीं हुआ है। उसकी पूरी तरह से काश्तकारों को जानकारी मिली है। सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए काश्तकारों को कि इससे भाव नीचे नहीं जावेंगे और न ही जाने दिए जावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्यपाल का भाषण हुआ और भाषण के अन्तर्गत जो सरकार की पॉलिसीज् हैं उनके सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार रखे और यह भी धारणा प्रकट की कि सरकार उत्तरोत्तर उन्नति करती जा रही है और राजस्थान का विकास हो रहा है। अगर सारे भाषण की जो पॉलिसीज् सरकार के द्वारा प्रतिपादित की गई है उनको मद्देनजर रखें तो ऐसा आभास होगा कि सरकार ने अभी तक अपने १७—१८ साल के शासन में कुछ भी प्रगति नहीं की है। भाषण के अन्तर्गत इस तरह से पॉलिसी का जो प्रतिपादन हुआ है वह सामान्य तौर पर कैसी भी, कोई भी सरकार हो वह करती ही है। परन्तु हमारी यह सरकार एक सिद्धान्त के रूप में, एक सिद्धान्त को लेकर जिस समाज की रचना करना चाहती है, वह सिद्धान्त है उसका

-(श्री गंगासिंह)

समाजवाद और समाजवादी समाज की उसकी कल्पना। उसके अन्तर्गत सरकार अपनी पोलिसीज़ चला रही है। उनको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार की ये पोलिसीज़ सक्सेसफुल हुई हैं, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

समाजवादी समाज की व्यवस्था का नारा लगा कर सरकार चली थी। परन्तु जब से समाजवादी समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयत्न किया गया, कितनी समाजवाद की भावना देश में आयी या समाजवादी व्यवस्था पनपी, इसकी ओर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि यह सरकार जो एक समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है, अभी तक समाजवाद का कुछ भी सिद्धान्त उन्होंने नहीं अपनाया है।

जब से सरकार द्वारा इस समाजवाद की स्थापना की गई हैं जो समाजवाद का नारा लगाया गया है, उसके बाद लगातार हर चीज के भावों में वृद्धि हुई है। समाज के जो वर्ग हैं उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है। लगातार उनकी आर्थिक हालत गिरी हैं। देश के अन्दर किसी प्रकार का सुधार प्रतीत नहीं होता। यहां किसी प्रकार से भी समाजवाद का नारा फलीभूत नहीं हुआ। तो फिर समाजवाद क्या ?

मैं इस समय यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद के इस सिद्धान्त के ऊपर, जहां समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, इस सिद्धान्त पर राजनैतिक और आर्थिक पोलिसीज़ को बेसिस रखना चाहते हैं, कम से कम आपका जो सिद्धान्त समाजवाद का है वह स्पष्ट होना अनिवार्य है। यह जो आपने समाजवाद का सिद्धान्त रखा है और उसके अनुसार जो समाजवादी सरकार की स्थापना की गई है और समाजवाद की कल्पना जो हरेक आदमी के दिमाग में रहती है उससे भिन्न है आपके, समाजवाद जिस पर सरकार चल रही है अब तक इस सरकार ने इन १७-१८ सालों में कुछ भी उन्नति नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राज्य-पाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पंचायतों के चुनाव जो इस साल हुए उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। जहां नीति निर्धारण सम्बन्धी यह भाषण हुआ है उसके अन्तर्गत इस राज्य के अन्दर सबसे बड़ा जो काम हुआ है उसका उल्लेख अभिभाषण में आना चाहिये। इससे यह मालूम होता है वे खुद भी इस सरकार के पंचायत चुनावों के अन्दर जो कार्य हुए उससे असन्तुष्ट है। इस पंचायत राज की जो स्थापना हुई वह केवल सोशियल बेसिस पर नहीं। इसका इकोनोमिकल और पोलिटिकल रूप है। अगर इस संस्था की ओर पूरा ध्यान नहीं रखा गया तो निस्सन्देह इसका तीन रूप में असर पड़ेगा- इकोनोमिकल, सोश्यल, और पोलिटिकल। इन संस्थाओं में राजनैतिक पार्टियों का हाथ हो गया तो यह राजनीति का अखाड़ा बन जायगी। इससे पंचायत राज का जो ध्येय है वह अपने आप समाप्त हो जायगा। अब की बार के जो इलेक्शन्स देखे हैं उससे यह मालूम होता है कि जिस मतलब से इलेक्शन किये

Page No 50

(श्री गंगासिंह)

जाते हैं वह मतलब पूरा नहीं होता। पंचायत राज की जो स्थापना की गई है, उसका उद्देश्य है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें डेवलपमेंट का काम करें, जन-सुविधा का काम करें। हमारे यहां पंचायतों के चुनाव जिस ध्येय से हुए हैं वह एक प्रकार से प्रेस्टिज पोइन्ट बन जाता है। पंचायतों के चुनाव आज तो केवल आन शान के चुनाव हो गये हैं। इस तरह का ध्येय रहा तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। अगर इसी प्रकार की नींव पड़ती गई तो निस्सन्देह कोई दिन ऐसा आयगा जब कि सारे रूरल एरिया में पंचायत राज खत्म हो जायगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी धारणा है कि पंचायतों की तरफ आप ध्यान दें; उसके चुनावों का विश्लेषण करें, और ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे पंचायत राज्य राजनीति का अखाड़ा न बने और न प्रेस्टिज पोइन्ट पर इलेक्शन्स हों। पंचायत राज के ध्येय की पूर्ति हेतु इलेक्शन किये जायं, ताकि अच्छे अच्छे आदमी इसमें आकर कार्य कर सकें।

इसके साथ ही मेरी धारणा है कि पंचायत समिति और जिला परिषदों में काम करने वाले लोगों ने जो वर्तमान में प्रधान थे, प्रमुख थे उनकी पार्टी को पूर्णतया मदद दी है। विलेज लेवल के जितने अधिकारी हैं जो प्रधान था उसकी पार्टी को मदद की है इससे जो सर्विसेज की इन्डेपेन्डेंसी का वातावरण होना चाहिये वह धीरे २ हटता जा रहा है जो वातावरण आज पंचायतों का दिखाई दे रहा है वह वातावरण बहुत ही बुरा मालूम पड़ता है। इस तरह की मेरी यह धारणा है कि पंचायत राज को कायम करना है तो निस्संदेह इसको फिर से जांचा जाय! आज जो दुर्भावना आई है उसको निकाला जाय। आपकी जो चुनाव प्रणाली रखी गई है वह इस तरह की रखी गई है जिससे ये चुनाव बहुत दिनों तक टिक नहीं पायेंगे। यह बहुत खर्चीली प्रणाली है, इसके अन्दर बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिये गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति व जिला परिषद इनके चुनाव एक साथ में रखे जावें। इसके अन्तर्गत जब पंचायतों के चुनाव होते हैं उस समय पंच और सरपंच के साथ होते हैं उनके साथ में ही प्रधान और प्रमुख के भी चुनाव करा दिये जांय तो निस्सन्देह ही चुनाव होंगे वे इतने जटिल व कठिन चुनाव नहीं हो पायेंगे।

इसके साथ साथ में मैं सदन का ध्यान पश्चिमी राजस्थान की समस्या की ओर भी ले जाना चाहता हूं जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर रेतीला स्थान है जिसके अन्दर पानी की बहुत कमी है, अगर देखा जाय तो यह राजस्थान का बहुत उपजाऊ भाग बन सकता है अगर इसमें पानी की पूर्ति कर दी जावे तो।

दूसरा यहां पर खनिज-सम्पदा भी बहुत है जो दुनिया के दूसरे स्थानों पर नहीं मिले, वह खनिज इस रेगिस्तान में है, ऐसी एक्सपर्ट्स की धारणायें हो रही हैं, इसके अन्दर बड़े बड़े मगरे पड़े हैं, उनका

Page No 51

(श्री गंगासिंह)

अन्वेषण किया जाय तो इस देश को बहुत बड़ा धन मिल सकता है।

पीने के पानी की कमी की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर पिछले वर्ष में लगातार इस समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अभी तक सरकार इस ओर कुछ कदम नहीं उठा सकी है। कुछ कुए जरूर बनाये गये हैं, उन कुओं को मद्देनजर रखते हुए और प्रोब्लम को देखते हुए ये कुए बहुत कम हैं। सबसे पहले राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यह बहुत बड़ा इलाका है, कम से कम इस इलाके के लिए पीने का पानी की व्यवस्था तो करें।

(१.०० म० प०)

इसी इलाके में वहां पर खारी पट्टी नामक इलाका है। इसमें कुए से भी पानी निकलेगा तो खारा होगा। मवेशी यह पानी भर पेट पी जावें तो मर जावें। ऐसी स्थिति में वहां पानी का प्रबन्ध करना चाहिये। विज्ञान का युग है। आस पास में जैसे जैसलमेर और गंगानगर की तरफ नहरें आ रही हैं तो उन नहरों का पानी इन इलाकों तक भी लाया जाय। इससे इस इलाके की तरक्की होगी। खेती की दृष्टि से उतनी न सही, पर पशु-पालन की दृष्टि से यह इलाका प्रगति कर सकेगा।

इस इलाके के पशु-पालन के व्यवसाय की ओर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया। पिछले पन्द्रह सोलह सालों में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि गिरावट आई है नस्लों में। नस्ल सुधार की तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी धारणा है कि कई पशु आज भी ऐसे हैं जिनकी नस्ल सुधार कर विदेशों में भी भेजा जावे तो काफी पैसा मिल सकता है। घोड़े की नस्ल सुधार कर दूसरे देशों में भेजा जावे जिसकी यहां अधिक कीमत तो अपने यहां का थोड़ा अच्छी कीमत दे सकता है। यह विदेशी मुद्रा कमाने का अच्छा साधन हो सकता है।

इसके साथ शिक्षा के प्रति राजस्थान सरकार का इस प्रदेश के हिस्से के प्रति ठीक रुख नहीं रहा है। जिला-स्तर के शहरों में भी वहां कॉलेज नहीं है। नागौर नगर के लिये बार बार लिखा गया था सरकार को और अध्यक्ष महोदय, आपने भी ध्यान आकर्षित किया था पर इतना बड़ा शहर होते हुए, आसपास के गांवों की संख्या देखते हुए, जिला हैड क्वार्टर होते हुए भी यहां कॉलेज नहीं बन रहा है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

टैक्नोलोजी का जमाना है, इसके कॉलेज भी उधर खोले जावें। इसके साथ साथ धर्म के सम्बन्ध में भी थोड़ी शिक्षा दी जानी चाहिये, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक और नैतिक विकास अधूरा रह जावेगा।

(श्री गंगासिंह)

राज्य सरकार का सड़कों की तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। अकाल के समय इस इलाके में काफी सड़कें बनी थीं पर वे अभी तक अधूरी पड़ी हैं। तो गर्मियों की धूल उड़े उस से पहले अगर वहां का अर्थ वर्क का काम जो पड़ा है उसे पूरा करके सड़कें पूरी कर दी जावें तो लाखों रुपया व्यर्थ जाने से रह जावेगा। इसलिये जल्दी से जल्दी इन सड़कों का काम पूरा किया जावे।

इसके साथ साथ अन्न समस्या पर भी मैं कुछ शब्द कहूंगा। नागौर जिले के बड़े बड़े गांवों में जो कुछ दूकानें खोली थीं वे भी सरकार ने उठा दी और जो हैं वहां भी अन्न उपलब्ध नहीं है पिछली वक्त जब अन्न नहीं आया तो सड़ा गला आटा दिया गया। इससे काफी बीमारियों का सामना जनता को करना पड़ा। कलेक्टर को कहा गया तो उसने जवाब दिया क्या करें। यही आटा आया है। मजबूरन लोगों को वह लेकर खाना पड़ा। यह गल्ती किसकी है?

आप दूकानें भले ही कम खोलें, पर सप्लाई खत्म नहीं होनी चाहिये। इससे दो नुकसान होते हैं; एक तो वहां के लोग उन दूकानों पर निर्भर रहते हैं इसके कारण दूसरी जगह जाते नहीं, और अन्न नहीं मिलने की पहले कल्पना नहीं कर सकते थे और इसलिये भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इसलिये कलेक्टर को लिख दिया जावे कि कम से कम उनका जो गेहूं रहे स्टॉक को ध्यान में रखते हुए सरकार को पहले सूचना दे दे और सप्लाई में रुकावट न आने दे।

इसके साथ साथ इस समय जो कोऑपरेटिव सोसायटियां हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। ये जो सोसाइटियां बनी हैं केवल नाम की हैं। जिस हेतु पैसा इनको मिलता है, उसमें खर्च नहीं करते। कोऑपरेटिव का अर्थ है मिल जुलकर मदद करें। अब जिस काम के लिये इनको पैसा दिया जाता है उस पर खर्च नहीं करते; तो इस कारण काश्तकारों को राहत नहीं मिलती और वे कर्जदार ही बने रहते हैं।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान हमारे यहां पर जो सोशियल बोडीज़ काम करती हैं उसकी ओर आकर्षित करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अन्तर्गत राज्य सरकार की जो पॉलिसी रही है और उसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार अपने ऑफिसर्स भेजती है लेकिन सुचारु रूप से उसकी तरफ भी काम नहीं हो रहा है तो उनके जो होस्टल वगैरह बने हैं वहां पर जो पैसा दिया है वह मनमाने तौर पर खर्च हो रहा है। इसको मुद्दे नजर रखते हुए जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है और उसमें कहा है कि हमारे यहां आर्थिक, पॉलीटीकल और इकोनेमिक परिस्थिति में लगातार उन्नति कर रहे हैं; परन्तु आप देखें तो, इन्हीं सभी पहलुओं में जो राज्यपाल महोदय ने बताया है उसमें ऐसी प्रगति सरकार की नहीं हो रही है जिसके कि कारण राज्यपाल महोदय को

(श्री गंगासिंह)

धन्यवाद दिया जाये। तो, मैं इन शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है और उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसका मैं समर्थन करती हूं। पिछले वर्षों की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल महोदय ने सिंहावलोकन किया और गवेषणा की और राज्यपाल महोदय ने बताया कि पिछला वर्ष हमारे राज्य के लिए आर्थिक संकट का वर्ष था और बहुत बड़े अकाल का हमें सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय यह वास्तविकता है कि पिछले साल एक बहुत बड़े अकाल का हमें सामना करना पड़ा और हमें खुशी है कि बड़ी सफलता के साथ हम उस अकाल का मुकाबिला कर सके। लेकिन साथ ही दुख इस बात का है कि इस साल भी राजस्थान में, एक में नहीं, सैकड़ों गांवों में फिर से अकाल आ गया। हम बराबर देखते हैं कि हर दूसरी साल तीसरी साल अकाल हमारे राज्य में छाया रहता है। मैं तो कहूंगी कि यह हमारे राज्य की एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें इस समस्या को बहुत ही समझदारी के साथ मुकाबिला करना चाहिये या इसे सुलझाना चाहिए। प्रतिवर्ष हम करोड़ों रुपये अकाल पर खर्च करते हैं और इससे एक बार तो आरजी तौर पर लोगों को राहत मिल जाती है लेकिन वह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती आई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार इसके लिए एक प्लानबद्ध योजना बनाये जिससे कि हमेशा के लिए इस अकाल के भूत से हम पीछा छुड़ा सकें और जितनी राशि हम खर्च करते हैं यदि इसे प्लानबद्ध योजना में खर्च किया होता तो अवश्य हम इस अकाल से छुटकारा पा गये होते।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि अन्न संकट हमारे प्रान्त में पिछली साल रहा है। अन्न संकट की ओर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इशारा किया है, और हम देखते हैं कि अन्न-संकट की समस्या जो हमारे सामने बहुत ही भीषण रूप है। साल दो साल से यह समस्या बराबर हमारे सामने है। हमने पिछले वर्ष कई तरह के कानून बनाये, नियम बनाये और इसे कन्ट्रोल करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेन्ट्स किये। लेकिन दुख के साथ हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम इस समस्या को नही सुलझा सके बल्कि इस साल वह और भी भीषण से भीषण तर रूप में हमारे सामने आ रही है। हमें इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम इस संकट का सामना नहीं कर सकेंगे। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है, कि इस समय राज्य को प्रति मास १५ हजार टन दिशावरी गेहूं मिलता है। अतः यह गेहूं चुने हुए स्थानों पर ही बांटा जा सकता है। इससे हम संकट का सामन नहीं कर सकेंगे। मेरा कहना है कि इससे हम संकट का सामना नहीं कर सकेंगे। यह राशि इतने कम मात्रा में है; कि संकट का मुकाबिला नहीं हो

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत)

सकता। इस राशि से ज्यादा से ज्यादा अपने डिवीज़नल टाउन्स में राशन दे सकते है। मैं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान गांवों की ओर भी दिलाना चाहूंगी। सन् १९५७-५८ में जबकि पुराना राशन हमारे शहरों को दिया जाता रहा; उस समय, जोधपुर शहर के लिए जो सप्लाई करना पड़ता था, वह २२०० टन था और अकेले जयपुर शहर को ४००० टन था। हालांकि इस ७-८ साल में शहरों की आबादी बढ़ी है लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हिसाब लगायें तो १५ हजार टन गेहूं मिलेगा। अगर हम पूरा राशन दें तो सिर्फ डिवीज़नल टाउन को ही इससे मुश्किल से कवर कर सकते हैं। आज–कल हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। इसी तरह से दें, तो फिर भी इस राशि से कुछ होने का नहीं है। हम डिवीज़नल सिटीज़ को थोड़ा थोड़ा ही दे सकेंगे और फिर बाकी के लोगों के सामने हमारी क्या समस्या होगी? यह बात ठीक है कि राज्य सरकार ने भावों को कायम किया है लेकिन क्या हम उससे समस्या का समाधान कर सकते हैं? अगर आप व्यवसाइयों को फ्लेट रेट से अधिक देकर अनाज अपने कब्जे में कर लें; तो उस समय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की स्थिति क्या होगी।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे पास दो ही जरिये हो सकते हैं जिससे हम अपनी अन्न की समस्या को सुलझा सकते हैं; या तो वह अन्न इम्पोर्ट किया हुआ हो या फिर अपनी ही फसल से लें। अभी फसल आने वाली है। हमारी अगली फसल महीने, दो महीने में आयेगी। हम फसल को नियंत्रित करने के लिए आगे कदम उठायेंगे तभी कुछ सम्भव है। अगर आज हम अपना कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो साल भर के लिए हमें पछताना पड़ेगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगी कि अभी केन्द्र में एक फूड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गयी और उसका हैड ऑफिस मद्रास में रखा गया है। उसने इसी पहली जनवरी से काम करना शुरू किया है; हालांकि कोर्पोरेशन चावल जोन के लिए बनाया गया था। चावल की फसल आ गई है, क्या उसी की एक ब्रांच हमारे राज्य में भी खोले जाने का सरकार विचार रखती है? उसके नियम यह हैं कि कोई भी व्यापारी आस-पास के क्षेत्र में २०, ३०, ४० मील में बैलगाड़ी से या दूसरे साधनों से अनाज एक जगह से दूसरी जगह ला सकता है, लेकिन रेलगाड़ी के द्वारा दूर दूर स्थानों में नहीं पहुँचा जा सकता। तो इसके लिए और प्रबंध किया जाये। अगर राज्य सरकार भी इस तरह कोई ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खोले या ऐसा कदम उठाये जिससे हम आने वाली फसल को अपने कब्जे में कर लें तो उचित होगा। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सबसे पहले इस आने वाली फसल को सरकार अपने कन्ट्रोल में ले। जब तक सरकार के पास स्टॉक में इतना अनाज नहीं होगा कि लोगों को सप्लाई कर सके तब तक एक अनिश्चित लोगों के दिमाग में बनी रहेगी। पिछले एक, दो, तीन साल में इतना बिटर एक्सपीयरेन्स हमें हो चुका है। यदि सरकार के पास स्टॉक होगा तो जनता को

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

निश्चित भरोसा हो जायेगा कि वक्त के ऊपर हमें अनाज मिल सकेगा। इसलिए मेरी राय में सरकार को इतना स्टॉक कायम कर लेना चाहिए कि वह सारे के सारे टाउन्स को और जो बड़े बड़े टाउन्स हैं जिनकी आबादी ८-१० हजार की है उनको साल भर को गेहूं सप्लाई कर सके और हमारी सरकार के पास स्टॉक में इतना गेहूं भी जरूर होना चाहिए कि हम अपने कर्मचारियों को, मुलाजिमों को और बड़े बड़े कारखाने जिनमें दो-तीन हजार आदमी काम करते हैं उनको भी साल भर के लिए राशन दे सकें। इसके अलावा हमारे पास इतना स्टॉक रहना जरूरी है; कि आने वाली फसल में उसको बोने के लिए बीज के लिए आसानी से हम दे सकें। यदि सरकार इतना काम कर सकेगी तो इससे बहुत बड़ी निश्चितता हो जायेगी। अगर आने वाली फसल खो दी, तो फिर पछताना पड़ेगा और वही तकलीफ देखनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, अनाज की मंहगाई का असर दूसरी चीजों के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी चीजों के भाव भी बराबर ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे सामने तरह तरह की समस्यायें इस मौके पर आ रही हैं। इधर हमारे कर्मचारियों का डियरनैस अलाउन्स हमें बराबर बढ़ाना पड़ता है। अगर ५ रु० बढ़ाते हैं तो उधर बाजार में भाव १० रुपये ऊपर चढ़ जाते हैं।

हमारे खजाने पर वजन पड़ता है, फिर भी लोगों को फायदा नहीं मिलता है। उससे असन्तोष बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि हम जो जरूरी चीजें हैं, एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ हैं, उनकी एक सूची बना दें और उनको हम फेयर प्राइस पर अपने कर्मचारियों को दे सकें। मैं याद दिलाऊंगी, मन्त्री महोदय को कि पिछले युद्ध के वक्त में रेलवे विभाग ने भी एक ऐसी व्यवस्था की थी कि अपने कर्मचारियों को एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ ठीक भाव से दी जायं। उसका नतीजा अच्छा हुआ। आज भी हम देखते हैं कि उसी लाइन पर चला जाय तो उस समस्या को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। हमने सुना है कि यहां के कर्मचारियों ने इसी तरह की सारी वस्तुओं की एक सूची बना कर, पूरी की पूरी स्कीम बना कर हमारे योजना मन्त्री को दी है और यह भी सुनने में आया है कि वह स्कीम केबीनेट स्तर पर पड़ी हुई है। मैं यह निवेदन करूंगी कि वह जल्दी से जल्दी इस काम को अपने हाथों में ले कि एसेन्शियल कॉमोडीटीज़ को ठीक भाव से दिलवाया जाय।

इस मंहगाई का असर केवल उसी पर न पड़कर चारों तरफ पड़ रहा है, कई तरह का कुप्रभाव हमारे सामने आया है। इस मंहगाई का असर पड़ता है हमारे प्लानिंग पर। हम जो प्लानिंग करते हैं उसको हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाव ऊंचे होने से, मंहगाई बढ़ने से जो काम करते हैं वह काम अधूरा ही होता है। हम जो काम करना चाहते हैं उसकी कीमत आधी ही रह जाती है। सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत दिया

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

था कि चौथी योजना में २३६ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी रकम है। इस रकम से हम संतुष्ट थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हम अपने भावों पर कन्ट्रोल नहीं कर सके तो क्या २३६ करोड़ रुपया लगाने पर भी वह काम पूरा होगा ? वह आधी ही रकम होगी, क्योंकि जो कुछ लगायेंगे उसका आधा होगा और जो कुछ रिटर्न मिलेगा वह भी आधा ही मिलेगा। इस प्रकार इस महंगाई के कारण हमारा प्लानिंग है, वह कटता-छंटता चला जायगा। इससे सबसे जरूरी चीज यह है कि इस महंगाई पर कन्ट्रोल करें। अगर हमने इस पर कन्ट्रोल नहीं किया तो हमारी योजनाएं गड़बड़ होती चली जायेंगी। आज जो हमें योजना में पूरी सफलता नहीं मिल रही है, उसका एक कारण यह है कि ये भाव ऊंचे जा रहे हैं और जो खर्चा हम करते हैं वह खर्चा वहीं का वहीं रहता है, लेकिन उसकी असली कीमत आधी रह जाती है। उसके साथ ही मैं अर्ज करूंगी कि हम देखते हैं कि महंगाई के कारण जनता में असन्तोष बढ़ता जा रहा है और निरन्तर बढ़ता जा रहा है और हमारी पार्टी या हमारा राज्य चाहे जितना काम करे विकास का, चाहे जितने तालाब बनायें, लेकिन इस महंगाई के कारण जनता में असन्तोष बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारे उन कामों का जो फल मिलना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और उसका फायदा उठा लेती है हमारी राजनैतिक विरोधी पार्टियां। सबसे पहले महंगाई और भावों को नीचे लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैं निवेदन करूंगी कि फर्स्ट प्रयोरिटी इस काम को दी जाय। महंगाई को नीचे लाया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह तो आप दो साल से चर्चा कर रही हैं महंगाई के लिए लेकिन कोई सुझाव दीजिये कि कैसे करेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सुझाव दिये जा चुके हैं, आप सुनिये। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विकास के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम यह जानते हैं कि हमारा राज्य औद्योगिक विकास में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। जब तक औद्योगिक विकास आगे नहीं बढेगा, न हमारी गरबी दूर हो सकती है; न हमारी भुखमरी मिटाई जा सकती है और न लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। औद्योगिक विकास करने के लिये सबसे आवश्यक होता है पॉवर। पॉवर और बिजली के बिना न उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं और न कृषि को ही आगे बढ़ा सकते हैं। पिछली बार बजट सेशन के इन्हीं दिनों में राज्यपाल महोदय ने हमको बताया था कि हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता मजबूत है। उन्होंने हमको बताया था कि हमारी जेनेरेटिंग कैपेसिटी पॉवर ६६ हजार किलोवाट हो गई है। इस पर सन्तोष जाहिर किया गया था, हमने खुशियां जाहिर की थीं। एक बहुत बड़ी आशा

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बंधी थी कि ९६ हजार किलोवाट की कैपेसिटी को लेकर हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि हमारे खुशी मनाते हुए चार महीने नहीं हुए, राज्य के मन्त्री को बधाई दिये हुए चार महीने नहीं हुए; कि अचानक खबर मिलती है कि राज्य में पॉवर का अकाल है। यह हमारी समझ में नहीं आया। जहां खुशियां मनाने जा रहे हैं वहां अकाल एकदम कैसे पड़ गया? कहने सुनने में आता है, हमको कहा गया है कि गांधी सगर में पानी नहीं भरा उसकी वजह से बिजली में कमी पड़ी। यह समझ में नहीं आता है। आखिर योजना बनाने से पहले इसका हिसाब भी लगाया होगा, आंकड़े भी तैयार किये होंगे, उनमें अनावृष्टि और अतिवृष्टि का भी ख्याल रखा गया होगा, फिर यह एकदम कैसे हो गया? मगर हम यह देखते हैं कि इस योजना में इस तरह से अकाल आने की वजह से हम लोगों के दिमागों में एक प्रकार का शक पैदा होता है, एक प्रकार की दिमागी अस्वस्थता पैदा होती है कि यदि उनके आंकड़े लगाने में भ्रम हुआ है, या आंकड़े गलत लगा लिए हैं या अनुमान अधिक लगा लिया है। इसका नतीजा दूसरे कामों पर क्या होगा? अगर हमने यहां पर गलती कर दी है तो इसका असर कोटा बैरेज पर नहीं पड़ेगा? इसका असर हमारी आशा केन्द्र राणा प्रतापसागर पर लगने वाले ऑटोमेटिक एनर्जी पॉवर स्टेशन पर नहीं पड़ेगा? इन सबका पानी का स्त्रोत तो गांधीसागर ही है। अगर हमें वहां असफलता मिली है तो किस कारण से मिली है, अगर हमारे आंकड़े गलत हैं, तो इसका आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा लगता है कि हम जिस औद्योगिक विकास की आशा लगाये बैठे थे उस पर तुषारापात होता नजर आता जा रहा है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय ने इस गम्भीर स्थिति की ओर कोई संकेत नहीं किया। यह एक ऐसी गम्भीर स्थिति है जिसको कि पूरे राज्य में पूरी गम्भीरता के साथ लेना चाहिए था। अब इसके सामने प्रश्न यह पैदा होता है कि आगे आने वाले सालों में पॉवर का क्या होगा? आज से डेढ़ दो साल पहले इसी सदन में मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या ३-४ साल बाद राजस्थान में बिजली की कमी नहीं पड़ेगी? वह चीज आज सामने आई क्योंकि हम जानते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा? जितनी हमारी पॉवर देने की कैपेसिटी है, आज उसके बेसिस पर हमारे पास देने के लिए दूसरों को रहा ही नहीं। इधर हमारी मांग बराबर बढ़ती जा रही है। हम यह जानते हैं कि एटोमिक एनर्जी पॉवर स्टेशन अभी तक कम से कम ५-६ साल पहले हमें पॉवर नहीं दे सकेगा। इधर जो सतपुड़ा का प्लानिंग है वह हमारे मंत्री महोदय के आश्वासन के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार और आंकड़ों के अनुसार इस साल बिजली दे देने वाला था लेकिन वह बिजली नहीं दे सका हम नहीं कह सकते कि एक-दो साल में देगा। हमारे दिमाग में अनिश्चितता पैदा होती जा रही है। इसी तरह से पौंग डैम का प्रश्न आता

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

है । जो हिस्सा हमें वहां से मिलने वाला था, उस हिस्से का क्या हुआ? उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ? सुकेती बांध से जो हिस्सा हमको मिलने वाला है, उसकी प्रगति क्या है ? उसका हिस्सा हमें मिलने वाला है या नहीं ? या उसकी भी आशा छोड़ दें, अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, जिन पर सोच-विचार करना होगा । इन गम्भीर प्रश्नों को, इन मुद्दों को, यहां पर छोड़ा नहीं जा सकता है । यह मैं जरूर मानती हूं कि इस अकाल में रतनगढ़ लाइन हर जिस मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है उसकी तारीफ करें । जिस एफिशियेन्सी से मंत्री महोदय और उनके विभाग के सब लोगों ने काम किया है, उसकी तारीफ हम किए बिना नहीं रह सकते । हम चाहेंगे कि हमारी जो पॉवर की दूसरी चीजें हैं उसी एफिशियेन्सी के साथ में और मुस्तैदी के साथ में उन्हें भी लिया जाय, क्योंकि राजस्थान पावर व इन्डस्ट्री के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है, उसके मैं एक-दो आंकड़े सदन के सामने रखूंगी । जो कि पार्लियामेंट के सदस्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य श्री गजाधर सोमानी ने प्रस्तुत किए हैं । उन आंकड़ों को मैं रखूंगी । हमारे यहां पॉवर की ३०. ६३ कुल कैपेसिटी काम कर रही है जब कि वैस्ट बंगाल में ६१.७२ किलोवाट ।

इसी तरह हम टोटल इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी सबसे पीछे हैं । हमारे यहां टोटल प्रोडक्शन १.१ है । सिर्फ १.१ जब कि महाराष्ट्र में २७.६८ है । इसी प्रकार हमारे राज्य की पर-केपिटा इन्कम २६७.२८ है. जो केवल बिहार से ऊंचा है बाकी सबसे नीचा है । हालांकि राज्य के आंकड़ों में और श्री जी. डी. सोमानी द्वारा दिए गए आंकड़ों में कुछ फर्क है, लेकिन सारे के सारे दूसरे राज्यों के आंकड़े एक ही स्त्रोत से दिये हैं, वे ही मैंने प्रोड्यू किएस हैं । तो अध्यक्ष महोदय, हम पोंग डेम के लिए कह सकते हैं, कि इसके लिए दूसरों से बात करनी पड़ेगी, सुकेती बांध के लिए भी कह सकते हैं कि दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा । लेकिन इनके अलावा भी राज्य के पास ऐसे साधन हैं जिनको टैप करके पॉवर में हम आगे बढ़ सकते हैं । आप सभी जानते हैं कि पलाना में लिग्नाइट का अपूर्व भंडार है, उससे थरमल पॉवर स्टेशन कायम कर सकते हैं । गांधी सागर के लिए तो कहा जा सकता है कि प्रकृति के प्रकोप के कारण यह नहीं भरा, लेकिन लिग्नाइट तो कहीं नहीं जायगा क्यों नहीं थरमल पॉवर स्टेशन चलाया जाता । हम कई वर्षों से सुन रहे हैं कि वहां पर थरमल स्टेशन कायम किया जायगा, लेकिन आज तक नहीं बना । इसके साथ ही हमें गैस का भंडार मिलने की उम्मीद है । यह सुनने में आया है कि जैसलमेर में गैस का भन्डार है । दिल्ली की मिनिस्ट्री से भी सुना था और अखबारों में भी पढ़ा था । अभी मुख्य मंत्रीजी ने जैसलमेर का दौरा किया और इसके बाद तो खबर मिली कि वहां पर गैस मिलने की पूरी संभावना है । मैं आशा करती हूं, आशा ही नहीं, विश्वास करती हूँ कि हमें गैस उपलब्ध होगी ।यदि यह सही है तो आज ही उसकी प्राप्ति के लिए योजना क्यों नहीं बनाते ? जब तक गैस

मिले तब तक जल्दी से जल्दी कारखाने क्यों नहीं स्थापित कर दें क्योंकि आखिर योजना बनाने में और मशीन लाने में वक्त लगेगा ।

(समय-समाप्ति—सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजाई तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहती, हालांकि पॉवर मंत्री जी इस समय यहां नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं, कि जल्दी से जल्दी पॉवर लाकर हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए । आज वह वक्त है जब केवल उद्योग में हीं नहीं बल्कि कृषि के लिए भी पॉवर की जरूरत है। छोटे छोटे कुओं में, छोटे छोटे किसान बिजली के जरिए मशीन लगा सकते हैं। यदि हमारे पास होगी तो हम उद्योग और खेती में उन्नति कर पायेंगे ।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा । उन्होंने कई एक विषयों पर चर्चा चलाई ; जैसा उचित ही था । खाद्यान्न के प्रोडक्शन और उसके वितरण को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ प्राथमिकता दी है । मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्षजी, यह एक ऐसी चर्चा हे, ऐसा विषय है, जो नेशनल पोइन्ट ऑफ व्यू से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सब परिस्थितियों के मुकाबले में पहले आता है ; यदि खाद्यान्न का उत्पादन और उसके वितनण की समस्या संतोषजनक एवं नजदीक भविष्य के अन्दर हल नहीं हो सकती तो हमारे देश के सामने एक खतरे की परिस्थिति उपस्थित हो सकती है । यह अनिवार्य सा प्रतीत होता है ।

माननीय अध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि वैसे तो हमारा भारतवर्ष हजारों वर्षों से ही नहीं बल्कि अतीत काल से एक कृषि-प्रधान देश रहा है और उस काल के अन्दर हमारे लोग खेती के ऊपर निर्भर रहे हैं। जिस प्रकार उनके बाप-दादाओं ने हजारों और सैकड़ों वर्षों से खेती की उसी प्रकार हमारे काश्तकार आज भी खेती करते है । मेरी शिका— यह यह है कि राज्य सरकार की ओर से इस खाद्यान्न के उत्पादन की तरफ और उसके वितरण की तरफ से जिस गम्भीरता से प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई और इस कारण जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं घोर विरोध करूंगा । अभी कल ही मुझे कृषि विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति प्राप्त हुई थी, मैंने उसको पढ़ा । उसको पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है; मानो हम कोई फेयरीलैंड के अन्दर रह रहे हैं और जो कुछ करना था हमारी सरकार ने वह सब कुछ कर दिया । लेकिन मैं विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, यह एक राष्ट्रीय समस्या है. उस पर पार्टी के दृष्टिकोण से टीका-टिप्पणी या छींटाकशी कदापि नहीं होनी चाहिये । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोओपरेटिव बेसिस पर यदि हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आवश्यक और उचित भी है, तो संभवतः हम इस जटिल समस्या को हल कर सकेंगे । इसलिये मेरे आज के कथन में कटुता का नामोनिशान न होकर, द्वेष भावना या विपक्षी भावना का नामोनिशान न होकर, वास्तविकता के आधार पर कहना चाहता हूं । जितना हल करने की आवश्यकता रहती

(श्री अमरसिंह)

है, मुझे रूप में आपके द्वारा सरकार के सामने पेश करूंगा। यदि इसमें तथ्य हों तो शीघ्रातिशीघ्र मंजूर फरमाकर इन बातों पर विचार करके जो खामियें रही हैं उनको हल करने का प्रयत्न करें।

माननीय अध्यक्षजी, इस खाद्यान्न के उत्पादन के अन्दर मैं यह निवेदन करूंगा कि आधुनिक समय के जो साधन उपलब्ध हैं उनको बताया जाय तो अवश्य ही प्रौडक्शन में तरक्की होगी। जहां एक बीघा जमीन में, जो २० वर्ष पहले उत्पादन होता था उससे सवाया, ड्योढ़ा या दुगुना उत्पादन करने की मजबूती हो तो हमें प्रतीत होगा कि तरक्की हुई है; यदि इतना प्रोडक्शन नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि हमारी प्रगति नगण्य है, कोई प्रगति नहीं हुई है। हम विज्ञप्तियों के अंदर पढ़ते है कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। दूसरे क्षेत्रों के अनुभव का तो मैं कुछ दावा नहीं रखता लेकिन मेरी पंचायत समिति में जो परिस्थिति हो रही है उसके आधार पर विचार करता हुआ मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। उसमें सर्वत्र हरेक जगह त्रुटि रही है। मैं अधिकारियों की बुराई तो नहीं करना चाहता, मैं उनको दोषी नहीं मानना चाहता, लेकिन यह कहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से जो इनिशियेटिव होना चाहिये, जो गाइडेन्स होना चाहिये और जो डाइरेक्टिव होना चाहिये उसका सर्वथा अभाव रहा; और यही कारण है कि प्रगति ठप्प हो रही है। इस उत्पादन के लिये सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि बहतरीन बीज काश्तकारों को दिया जाय। हमारे काश्तकार कंज़र्वेटिव हैं इसलिये एक दम नयी चीज को अंगीकार करने में संकोच रखते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे काश्तकार प्रोग्रेसिव हों, उनको अच्छा बीज मिले और वे उसको उपयोग में लाने के लिये तैयार हों।

पिछले तीन वर्षों में मेरी पंचायत समिति में किसी किस्म का इम्प्रूव्ड सीड नहीं आया। मैं डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर से मिला। वे भले आदमी हैं, उनका दोष नहीं है।

मैंने निवेदन किया कि साहब हमको इम्प्रूव्ड सीड तो दो। तो उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ऐसी हैं कि इसके अन्दर हमारा जिम्मा नहीं है। यदि सरकार ने डिप्टी डाइरेक्टर का जिम्मा इम्प्रूव्ड सीड के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए नहीं रखा तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसा ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका जिम्मा लेता होगा। मैंने विकास अधिकारी से कहा, मैं दो साल पहले का केस आपके सामने सामने रख रहा हूं, तो उसने कहा कि हमारे यहां बजट के अन्दर प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप यह हुआ कि बेचारे काश्तकार बीज के लिए रोते रोते फिरे। एक तो अकाल का समय था, उनके पास पैसा नहीं कि बीज खरीदें और दूसरे अच्छा बीज उपलब्ध नहीं। उस समय सरकार की एजेंसी का कर्त्तव्य था कि उन्हें वह इम्प्रूव्ड सीड दें....

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपकी इन्फोर्मेशन के लिए बता दूं कि आपने काश्तकार को 'बचारा' कहा है, वह बेचारा नहीं है। यह अनपार्लियामेंट्री है, इसलिए इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप बेचारे का अर्थ वह न लें।

श्री दलपतसिंह : आपने दो-तीन दफा बेचारा काश्तकार कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : वे 'बेचारे' हैं। आपको 'बेचारा' नहीं कहा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयना) : आपके अत्याचार के कारण बेचारे हो गये हैं।

श्री दलपतसिंह : आपने यूज़ किया है 'बेचारा' दो तीन दफा। वे बेचारे नहीं हैं। इस शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तरह इन्टरप्ट करेंगे तो मुझ जो बातें कहनी हैं, उनको कहने में असफल रहूंगा।

अस्तु, मेरे इस शब्द को आपत्तिजनक समझा जाय तो I dont mind ; मैं सहर्ष वापिस ले लेता हूं। कोई बेचारा है तो बेचारा मैं हूं; however, तो इतने वर्ष के बाद..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, 'बेचारा' शब्द पार्लियामेन्टरी है या नहीं ?

श्री दलपतसिंह : राजस्थान लेंग्वेज के प्रयोग के अनुसार 'बेचारा' शब्द अन-पार्लियामेन्ट्री है ; आप यह नहीं जानते।

श्री अमरसिंह : मेरा 'बेचारे' से मतलब गरीब काश्तकार से था। आप अंग्रेजी में कुछ ऐसे समझ लें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका उद्देश्य अनपार्लियामेन्ट्री नहीं था।

श्री अमरसिंह : इस साल यह सवाल आया, क्योंकि देश के अन्दर खाद्यान्न की समस्या बड़ी जटिल होती गई तो राज्य सरकार को कहा जाकर, और कहां जाते कहने कि बीज लाओ। तो फिर मेरी जुबान से निकल जाता है, 'बेचारा'। तो बेचारा कलेक्टर, I say poor Collector, poor Vikas Adhikari हैं, उनके पास........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : असली बेचारे तो यही हैं कलेक्टर। काश्तकार क्यों हो 'बेचारा' ?

श्री अमरसिंह : उनके पास कौनसी खान है। उनको कहें तो वे कहेंगे कि मेरे पास कौनसी खान है कि बीज ले आऊं। तो मेरा कहना है कि अगर गेहूँ का अच्छा बीज पर्याप्त नहीं था तो जून के महीने के अन्दर इन्तजाम कर लेना था। ज्यों ही आपके इम्प्रूव्ड सीड में शोर्टेज हो गई थी तो आप इम्प्रूव्ड सीड और लेकर रखते। तो आपको दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए था, और जहां जहां पर बीज की आवश्यकता थी वहां वहां पर बीज पहुंचाना चाहिए था। यह समस्या आयी सितम्बर, अक्टूबर के महीने में, जब कोई बीज नहीं मिल सकता। हाउएवर, हमारे ऑफिसरों ने कहा कि कहीं से लूट-खसोट कर लाऊं। इस लूट-खसोट में मेरा भी हिस्सा गया। मेरे पास आर. एस. ३१.० का बीज था; मैंने यह निखालिस बीज प्राप्त किया था। उस बीज को बाजार में बेचता तो एक मन के तीस-बत्तीस रुपये ब्लैक में कोई भी जरूर दे देता। लेकिन उनको न देकर मैंने स्टेन्डर्ड रेट से गवर्नमेंट को दे दिया। मैंने

(श्री अमरसिंह)

सोचा कि यह पाप है कि यह अच्छा बीज फ्लोर मील में जाय। तो यह बीज भी कुछ दिनों में व्यतीत हो गया। उसके बाद भी उपयुक्त मात्रा में बीज नहीं मिला, क्योंकि जो काम होना चाहिये था वैसा काम हमारे यहां नही हुआ। यह अदूरदर्शिता के कारण नहीं हुआ। यह नम्बर १० दूसरा, और मैं निवेदन करूंगा कि केमिकल के लिए कहा जाता है, कि हम रासायनिक खाद देकर खेतों का उत्पादन बढ़ाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि कई साधारण फंडामेंटल हैं, जो सरकार को देखने चाहिए थे। उसको मद्दे नज़र न रखते हुए वगैर किसी राइट पॉलिसी के इनको डेम्प करने की कोशिश की। इस सम्बन्ध में वर्षो पहले मैंने सरकार को लिख कर भी दिया था कि जहां जमीन के अन्दर ऑर्गेनिक मेन्योर हो वहीं पर रासायनिक खाद आपको फायदा करेगी, जहां आर्गेनिक मेन्योर नहीं है वहां रासायनिक खाद को एग्ज़ॉस्ट करती है। लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला था। मेरा ख्याल है कि सरकार ने अब महसूस किया है कि वगैर ऑर्गेनिक मेन्योर के रासायनिक खाद जमीन को बरबाद करती है। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सोइल क्लासिफिकेशन नहीं हो, आप निर्णय नहीं कर सकते कि कौनसी जमीन में कौन से रसायनिक की आवश्यकता है। कौन सा रसायन देने से आप स्पोइल करेंगे, कौन सी रसायन देने से आप डिटीरियोरेट करेंगे। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां सोइल क्लासिफिकेशन किया हो। आपके एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफीसर का यह हाल है, मैं समझ नहीं सकता, शायद हमारे मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र पर कटु दृष्टि डाली हो या.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्रूर दृष्टि है।

श्री अमरसिंह : यह तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहां एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफीसर वही हैं......

एक माननीय सदस्य : समझा कर कहिए।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय दिया जाय तो मैं अर्ज कर सकूंगा। विशेष समय वैसे मैं अर्ज करने में नहीं लूंगा।

हाऊएवर, तो उनकी यह हालत है कि न जाने किस कागज के पुलिन्दे के नीचे दब कर रखे जाते हैं। उनका काम यह है कि जहां पर प्रोपर क्षेत्र है वहां फील्ड के ऊपर जाना, काश्तकारों की समझाइश करना, उनको समझना और फिर जो कुछ आपकी बुक-नॉलेज है उसको ट्रान्सलेट करके क्षेत्र में समझाना, इसके बजाय इन महानुभाव को कभी काश्तकार के खेत पर जाने की फुर्सत नहीं। चाहिए तो यह कि उनका सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, कुछ काश्तकारों की मीटिंग्ज़ करनी चाहिए। यह मानते हुए भी कि ये कन्ज़रवेटिव हैं, उनकी भाषा में बोलते हुए, उनके स्थान पर और उनके स्तर पर बैठ कर उनको कई बातों में कन्वीनियेन्स करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, आज तीन साल से कोशिश कर रहा हूं, मैं भी काश्तकार हूं-चाहे बेचारा कहें या बे-बेचारा, लेकिन मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील हूं, कि ये महानुभाव आकर मुझे भी सुझाव दें। अगर सुझाव

(श्री अमरसिंह)

नहीं दें तो डिस्कस कर लें और हम दोनों अपनी बुद्धि-चाहे मेरी बुद्धि कितनी ही वैसी हो, दोनों की बुद्धि शामिल कर लें, तो शायद कुछ अच्छा नतीजा निकले। बड़ी मुश्किल से कोई तरीका निकला, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। मैंने दूसरे काश्तकारों से भी पूछा-क्या आपके खेतों पर आते हैं; तो कहते है-हमें पता नहीं, कौन साहब हैं और कहां रहते हैं। मैंने जानकारी हासिल करने के लिए कुछ व्यक्तियों से पूछा कि इसका क्या कारण है, यानी आफिशियल्स से पूछा, क्या कारण है, कि संकुचित होकर हमारे खेतों पर नहीं आते हैं। तो मुझे बताया गया कि ये स्कूल्स से उठकर तो आते हैं इसलिए खुद की नोलेज तो इतनी अपूर्ण है कि वे काश्तकारों के पास जाकर नॉन-प्लस हो जाते हैं और कुछ सुझाव नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं खेती के बारे में और कभी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर भी रह चुका हूं, शायद यही ख्याल करके वे नहीं आये हों कि मेरे पास आकर उनकी पोल खुल जायेगी। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के अन्दर आज ऐसे लोग भी हैं कि जाने कुछ नहीं, काम कुछ करें नहीं, और काम करना चाहते भी नहीं हैं। इसके विपरीत में एक दफा मण्डोर के फार्म में गया था। वहां बड़े सूझ-बूझ के इन्सान से मिला। काश्तकार का बेटा, मारवाड़ का रहने वाला और मारवाड़ी भाषा में बोला, सभ्यता से बोला, ओब्लाइजिंग मैनर्स से बात की और मुझे प्रतीत हुआ कि वह जानता है और बड़ी उत्सुकता से उसने मदद की, जो मुझे बीज वगैरह छांटना था।

मैं यह निवेदन करूंगा कि समदृष्टि होकर तमाम क्षेत्रों के लिये सरकार एक सा व्यवहार करे, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। मैं यह समझता हूं कि मेरे यहां पर ही घोटाला हो, ऐसी बात नहीं है, यह घोटाला तो सर्वत्र है। किसी से भी बात करें तो वह यही कहेगा कि हमारे यहां पर भी इसी प्रकार का घोटाला है। कोई यह नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ पर घोटाला नहीं है। हमारे सामने हमारे डिपार्टमेंट वाले इस तरह के घोटालों में फंसे रहे हैं, यह कहां तक काबिले बर्दाश्त हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्रीजी और खाद्यान्न मंत्री जी के सामने यह प्रश्न रखूंगा कि अगर आप खाद्यान्नों की समस्या पर केबिनेट एज ए होल ध्यान देते हैं तो ठीक है, वर्ना कृषि मंत्री को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अब तक कृषि मंत्रीजी को खतरा है।

श्री अमरसिंह: हमें कृषि मन्त्रीजी से किंचित भी विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वे कृपा करके काम करें।

श्री विजयसिंह झाला: यह तो आप वापिस विथड्रॉ करते हैं।

श्री अमरसिंह: मुझे इनसे यही शिकायत है कि जितना प्रयत्नशील इनको होना चाहिये उतना नहीं है। इनके दौरे होते हैं अन-पर्पज़ली। इनके दौरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को गाइड करने के बजाय पोलिटिकल दौरे होते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : पंचायत इलेक्शन में दौरे हुए हैं।

श्री अमरसिंह : हमारे उधर पंचायतों का दौरा नहीं हुआ। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इनके रिलेशन्स बड़े ही अच्छे है। हाउस के बाहर भी बहुत अच्छे है।

(विराम)

मगर मुझे यहां पर ये कटुक्तियां कहनी पड़ती है। उसके बिना राहत ही नही है।

श्री विजयसिंह झाला : आला जजमेंट दें।

श्री अमरसिंह : ऐसे मौके पर आपके दौरे होने चाहिये, और उनसे बातचीत करनी चाहिये और अपने डिपार्टमेंट के ओफिसरों को हिदायत होनी चाहिये कि वे लोकल व्यक्तियों के साथ बातचीत करें और जो काश्तकार हैं उनसे बात करें और हर तबके के आदमियों से बात करनी चाहिये और उनसे कृषि के बारे में पूछना चाहिये। मगर इनके दौरे होते है वे अदरवाइज होते हैं और जितने खाली हाथ निकलते हैं वैसे ही वापिस आ जाते हैं, और कोई जानकारी नहीं करते। इसलिये जो फायदा उनके दौरे से लोगों को होना चाहिये नहीं हो सकता। इसलिये जनता और डिपार्टमेंट को कोई दोरे का फायदा नहीं होता और मैं तो यह कहूंगा कि वह ग्रोसनेग्लीजेन्स ऑफ ड्यूटी है। मैं चाहूंगा कि कृषि मन्त्री विशेष तौर से अपनी योग्यता को साबित करें जिससे हम लोगों को उनकी योग्नता का लाभ हो सके।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां दो फसलें होती हैं; सावनू और उन्हालू। जहां तक सावनू का प्रश्न है यह तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर होती है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) अध्यक्ष महोदय, चेयर की तरफ मूंछों के बल लगाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले मूछों पर बल लगाते थे तो किसी से लड़ने के लिये तैयार होते थे। जैसे दिल्ली की तरफ मूछों पर बल लगाते, तो उसका अर्थ होता था दिल्ली पर चढ़ाई करना। यहां चेयर की तरफ मूछों के बल लगाता है तो....

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष जी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कठिनाई यह है कि आप मुकाबले में बल नहीं लगा रहे हैं।

श्री अमरसिंह : अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सावनू एरिया है वहां कम से कम मैं डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की महरबानी से उनसे बीज लाया और उस बीज को बोया। वह बीज इतना बढ़िया साबित हुआ कि दूसरे लोग भी यह चाहते थे कि उनको भी वह बीज मिले। हम यह चाहते हैं कि जब ऐसा अच्छा बीज हमारे पास है तो उसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिले? उसको आपके यहां पर स्टोर में दबाये हुए रखने से क्या फायदा हो सकता है? मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री इस गफलत से बाहर निकलेंगे।

(श्री अमरसिंह)

दूसरा मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे यहां दो तरह की जमीन है । एक तो सख्त है और दूसरी है रेतीली । रेतीली जमीन में छानबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो सख्त जमीन है, उस जमीन में एक तो सर्दी में प्लोइंग हो और दूसरा गर्मी में प्लोइंग दे दिया जावे तो उसकी उपज बढ़ सकती है और उस भूमि में सुधार हो सकता है । अगर पंचायत समिति में जहां सख्त जमीन है, अगर एक गवर्नमेंट ट्रेक्टर रखा जावे और प्लोइंग के लिये देने की व्यवस्था रखी जावे तो मैं समझता हूं कि इससे लोगों को बड़ा लाभ होगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके लिये बनिये की दूकान का सा हिसाब नहीं लगाया जावे और एक्चुअल चार्जेज जो लगते हैं वे किसानों से लिये जावें और "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व" के आधार पर ट्रेक्टर उपलब्ध किया जावे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे लोगों को काफी लाभ होगा । मैं यह समझता हूँ कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी ।

दूसरा मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे उधर पचपदरा की तरफ पंपिंग सेट लगे और मैं यह भूल गया कि हमारे यहां पंचायत समिति का यह पोज़िटिव कार्यक्रम रहे कि वहां पर डीजल सेट लगें और बिजली हो तो वह बहुत इकोनोमिकल होता है और इससे हमारे इलाके की पैदावार बढ़ाई जा सकती है । मैने कई दफा विद्युत् मंत्रीजी से निवेदन किया, उनसे बंगले पर भी जाकर निवेदन किया, एसेम्बली के चेम्बर में भी निवेदन किया, लेकिन समझ में नहीं आता कि अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ? उन्होंने कृपा करके यह जरूर फरमाया कि हम करेंगे । लेकिन अभी तक जो विद्युत शक्ति उपलब्ध होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाई है और यह भी मालूम नहीं कि कब तक उपलब्ध हो जावेगी । मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में डीज़ल पॉवर लगावें, जिससे काश्तकारों को बिजली उपलब्ध हो । आप कोई काम न करें और फिर आप यह कहें कि हम खाद्यान्नों की समस्या को सुलझा रहे हैं तो वह कैसे हो सकता है ? जिस समय भुखमरी होगी उस वक्त न मालूम कौनसी समस्या उपस्थित होगी, उसका हमें अन्दाजा नहीं लग सकता । इस लिये मैं नम्रतापूर्वक अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमारी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक खाद्यान्नों की समस्या का सवाल है आप उस पर अपना समय लगा दें ताकि विषम स्थिति का सामना नहीं करना पड़े ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि अगर आप करना चाहें तो तमाम पार्टी बेसिस पर एक समिति बनावें और मेरी धृष्टता को क्षमा करें; अगर मुझे भी उस कमेटी का सदस्य बना दिया जावे तो मैं कोई अलाउन्स नहीं चाहता, मैं सेवा करने के लिये जो कुछ कर सकूंगा करूंगा और हर दो-तीन महीनों में वह समिति मिलनी चाहिये और मंत्री महोदय को ऊंचा नीचा लेना चाहिये कि आपने यह क्यों नहीं किया और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो....

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री महोदय को ऊंचा-नीचा लेने से क्या मतलब है ?

श्री अमरसिंह् : अगर आपको अंग्रेजी में कहने से कोई आपत्ति नहीं हो तो उसका अर्थ है पुल हिम अप और वह इतना कर्टसी के साथ और सम्मानपूर्वक कहूंगा कि कृषि मंत्रीजी इतना काम करवा दीजिये ।

श्री विजयसिंह् झाला : साहब, एक मिनिस्टर को ऊंचा-नीचा करके बता दें ।

श्री अमरसिंह् : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे समय दें....

श्री विजयसिंह् झाला : आप इन्हें इसके लिये जरूर समय दें ।

श्री रामकिशन (वैर) : हाउस में ऊंचा-नीचा नहीं करें, बाहर करें ।

श्री अमरसिंह् : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सरकार में नुक्ताचीनी करते हैं, उसका अधिकांश जिम्मा हमारे ऊपर हैं । यदि हम कर्तव्य-पालन सीख जायं, यदि हम स्पष्ट वक्ता हो जायं, सफेद को सफेद कहना और स्याह को स्याह कहना सीख जायं तो मन्त्री महोदय को मालूम हो जाय कि अब यह पोल इनके सामने नहीं चलेगी, ये जागरूक हैं सतर्क हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे सरकार में, मन्त्री मण्डल में ओवर नाइट सुधार हो सकता है. आखिरकार सरकार में सब बुद्धिमान् हैं । शेक्सपीयर ने कहा है । ये देखतें हैं कि ये सब हमारे पिछलग्गू हैं, हमारी हां में हां मिलाने वाले हैं । ये किंचित भी कर्तव्य से विमुख रह जायं तो यह हमारी जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :अब आप मुख्य मंत्रीजी को ऊंचा-नीचा कर रहे हैं ।

श्री अमरसिंह् : मैं मुख्य मंत्रीजी को यह निबेदन करना चाहता हूं, बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चीज को भूल गये हैं । "Strength of a chain lies in its weakest link."

आप हमको भाषण देते हैं, आप दिल्ली जाकर फरमाते हैं कि हमारा राजस्थान बहुत प्रगति कर रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि आज की प्रगति का मापदण्ड जो पिछड़ा हुआ इलाका है वही हो सकता है, उसके अलावा प्रगति की डींगें मारना अच्छा नहीं होगा । हमारा बाड़मेर का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है । कुदरत ने उतनी महरबानी हमारे साथ नहीं कि जितनी कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों के साथ की । हम आशा करते हैं कि हमारा मंत्रालय उस सबका मुकाबला नहीं कर सकता, पर उसको कम्पेन्सेट करने के लिये वह तमाम कदम उठायेगा, जो उचित हैं और मन्त्रालय द्वारा शक्तिसाध्य हैं । पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मन्त्रालय ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है, जो कि हमारे उस इलाके को पिछड़े पन से उठा कर आधुनिकता का आस्वादन करा सके । और तो क्या उस इलाके में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है । Human memory is proverbially short. मनुष्य की याददाश्त कमजोर होती है । पर सात-आठ वर्ष पहले केबिनेट मीटिंग

(श्री अमरसिंह)

बाड़मेर में हुई। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा मैं बहुत बड़ी बड़ी आशाएं मुख्य मंत्री जी से लिए बैठा हूं। पर दुःख की बात है...

श्री रामकिशन : अब भी आशाएं लिए बैठे है ?

श्री अमरसिंह : कि उन सब आशाओं पर वे पानी फेर रहे हैं, मटड़ा फेर रहे है। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि दिल्ली में यह योजना हो रही है कि बच्चों को मुफ्त में दूध दिया जाय, तो कम से कम हमको पीने को पानी तो दिया जाय। वे मुस्कराये। कहा जाता है...

"चर्चिल की पेटेन्ट मुस्कान थी"; पेटेन्ट करा लिया जाय हमारे सुखाड़िया जी साहब की मुस्कान को भी। इनकी मुस्कान भी पेटेन्ट कराने लायक है; वे सिर्फ मुस्कुरा कर रह गये।

श्री विजयसिंह झाला : उससे पानी नहीं निकला क्या ?

श्री अमरसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि यह विषय ऐसा नहीं कि जिसको आज से कल और कल से परसों के लिए ठुकराते जायं, यह आपकी समाजवादी सरकार के ऊपर एक धब्बा सा मालूम होता है। यदि विनम्रता से कहूं तो यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। आपके पास वह मशीन है, आप वहां पानी दे सकते हैं, आज से बहुत पहले सरकार को इस इलाके में पानी दे देना चाहिये था। कृषि का बुलेटिन निकाला। उसमें पढ़ा कि पानी का प्रबन्ध करेंगे। इस विषय में मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि पीने के पानी का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करें

मैं दुबारा कहूंगा कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी विद्युत् शक्ति प्राप्त हो, ऐसा प्रबन्ध करें।

एक बात और भी निवेदन करूं कि यह पिछड़ा हुआ इलाका और भी बहुत सी बातों में पिछड़ा हुआ है। दवाइयों का भी हमारे यहां प्रबन्ध नहीं है। इतने बड़े इलाके में बालोतरा में शफ़ाखाना है। वहां पर न दवाई का प्रबन्ध है, न सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स हैं, न इन्डोर पेशेन्ट्स के बैड्स हैं। एक छोटा सा घोंसला है तो पक्का पत्थर का, फिर भी हॉस्पिटल बैड के लिए रख दिया। इतना इनसेनिटेरी, बदबू देने वाला कि मैं एक दफा उधर चला गया तो एक मिनट भी वहां खड़ा नहीं रह सका। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी ओर भी सरकार ध्यान दे। हमारे यहां स्टाफ बढ़ावे, दवाइयों का प्रबन्ध करे, इन्डोर पेशेन्ट्स के लिए प्रबन्ध करे। जब शुरू शुरू में अंग्रेज राजस्थान में आये, जोधपुर में आये तो हमारा मालानी इलाका थोड़ा भिन्न सा समझा जाता था, मैं अस्सी-सौ वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, तो मालानी में. जासोल में एक शफ़ाखाना खोला। बचपन में मैं वहां जाता था, वहां दवाइयों का अच्छा साधन था। बाद में उस शफाखाने को हटा कर बालोतरा रखा गया, जासोल का खाली पड़ा है। मैं समझता हूं, बालोतरा क्षेत्र को लेडी डाक्टर दी जाय

(श्री अमरसिंह)

शीघ्रातिशीघ्र लेडी डाक्टर दी जाय और उसका हैड क्वार्टर जासोल में रहे। जहां सब प्रकार का रहने का प्रबन्ध है। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैंने कहा था पर उन्होंने मिन्नी पर हाथ फेर कर जैसी कि इनकी पोलिसी है मुझे वापिस भेज दिया। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही हाल है वहां जानवरों के शफ़ाखाने का। न वहां दवाइयां हैं न पट्टी है, न मरहम बनाने के लिए ग्लेसरीन है, बल्कि यह कहा जाय कि सिवाय कुछ स्टाफ के वहां कुछ नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि यह पशुपालन क्षेत्र है, जहां कसरत से मवेशी रहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि वहां मोबाइल डिस्पेन्सरी, चलते फिरते शफ़ाखाने का प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र किया जाय, जिससे ज्यादातर देहातों में रहने वाले लोग हैं उनको दवाइयों के साधन उपलब्ध हो सकें।

एजुकेशन के संबंध में माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जैसे दूसरी बातों में यह इलाका पिछड़ा हुआ है उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में यह पिछड़ा हुआ है। यह सरकार की घोषित नीति है कि हम शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे। यदि इसके अंदर कुछ सत्य भावना है तो फिर आज प्लानिंग मिनिस्टर ने कैसे कहा कि दो लाख रुपए लाओ तो कॉलेज खुलगा, नहीं तो नहीं। मैं उनसे विनीत भाव से निवेदन करूंगा कि यह सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को शिक्षित बनाए। यदि शिक्षा नहीं है तो हमारा प्रजातंत्र का ढांचा कोलैप्स होता है और प्रजातांत्रिक ढांचा क्रियान्वित हो इसके लिए आवश्यक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही नहीं उच्च कोटि की शिक्षा हमारे नागरिकों को मिले। दो तीन बातें मैं आपके द्वारा मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा आता है धनी लोगों से और उन धनी लोगों के बालक, यदि जिले में कॉलेज नहीं है तो वे अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते हैं। यदि धनी लोग कहें कि हम पैसा नहीं देते। तो आप क्या उन लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको उच्च शिक्षा देना आपका परम कर्त्तव्य है ?

यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरी धारणा है कि जो पश्चिमी मुल्क हैं, बढ़े-चढ़े हैं; जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, वहां पर विद्यार्थियों पर आंख रखी जाती है कि किस हद तक उसका टैलेंट है, किस तरफ उसकी रुचि है और किस तरफ उसको प्रेरणा देने से वह देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आप सोशयलिज्म की डींग मारते हैं। यदि आप इस चीज से इन्कार करते हैं कि यह जो हमारी निधि है उनको मनुष्य बनाना और उसका दिमाग डेवलप करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि कर्तव्य से हाथ धोना है, ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए।

(श्री अमरसिंह)

दूसरी बात, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर शहरों के अंदर आप कॉलेज खोलते हैं । जहां करोड़पति रहते हैं वहां आपने कितने करोड़पतियों से धन के लिए कहा है और प्राप्त किया है ? अगर शहरों के अंदर आप सब साधन उपलब्ध करते हैं और बगैर कन्ट्रीब्यूशन के सहकारी एक्सचेकर से खोलते हैं तो क्या कारण है कि ग्रामीण जनता के साथ आप इतनी पक्षपात-पूर्ण नीति अपना रहे हैं । मैं प्लानिंग मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि कृपा करके जो आपने आज सदन में बात कही उस पर पुनः विचार करें और भूल सुधार करने की कोशिश करें ।

(घंटी)

Very short time, Sir.

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है ।

श्री अमरसिंह : I am not in the habit, Sir, to go on against your orders.

श्री अध्यक्ष : दूसरों से आप ज्यादा समय ले चुके हैं ।

श्री अमरसिंह : दो-एक लोकल समस्याएं हैं ।

श्री अध्यक्ष : लोकल समस्यायें अगर आप ग्रान्ट्स के समय उठाएं तो अच्छा होगा आपकी विशेष तौर से कोई कठिनाइयां हों तो जब ग्रान्ट्स की डिमांड्स पर बहस चले उस दिन बताएं। अब आपको पांच मिनट और हैं ।

श्री अमरसिंह : इस क्षेत्र के अंदर दो साल लगातार अकाल पड़ा । लोगों के पास अन्न खरीदने को साधन नहीं था । अगर अमेरीकन एड नहीं आती तो परिस्थिति गंभीर होती । इस समस्या को मद्दे नजर रखते हुए मैंने राजस्व मंत्री से निवेदन किया कि दो साल की रेन्टल को सस्पेन्शन के बजाय रेमिशन करें । मुझे खेद है कि राजस्व मंत्री ने इसका मुझे जवाब तक नहीं दिया । एक-दो दिन पहले सेक्रेटरी साहब से मुझे एक पत्र मिला । आपके द्वारा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद वे अनुभव नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें अनुभव कराना चाहता हूं कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के पत्र का उत्तर न देना उसका अपमान करना है । और उसके मायने यह हैं कि ये मंत्रिगण विधान सभाई सदस्यों को अपमानित करने के आदी हो गए हैं और विथ इम्यूनिटी हाउएवर मुझे इसके अंदर कटुता नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि वे इस कथन से नाराज न हो जायं । यह सरकार जल्दी से जल्दी बीघोड़ी के रेमिशन के ऑर्डर्स करे ताकि लोगों को राहत मिले ।

श्री विजयसिंह झाला : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उन्हें पहले खतम करने दो ।

श्री अमरसिंह : मुख्य मंत्री से मैं एक पुरानी प्रार्थना और करूंगा । ८ वर्ष पहले मैंने निवेदन किया था कि मारवाड़ के घोड़ों की नस्ल भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध थी, वे आज मर रहे हैं । मुख्यमंत्रीजी ने कहा था कि मैं खुद घोड़ों का शौकीन हूँ मैं कुछ करूंगा, लेकिन उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया । मैं अपील करता हूं कि देश के हित के लिए, इस नस्ल को आबाद रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे घोड़ों की नस्ल कायम रहे । इस तरह ऐसे मवेशियों की नस्ल में भी सुधार होना चाहिए । इसके अन्दर जो त्रुटियां हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार की सर्वतोमुखी नेग्लीजेन्स रही है । इस आधार पर मैं धन्यवाद का मोशन पास होने के पक्ष में नहीं हूं जो फेल होना चाहिए ।

अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार विधायकों द्वारा सरकार को प्रेषित पत्र के उत्तर न मिलने विषयक पुनः अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने इस सदन के अन्दर व्यवस्था दी थी कि कोई विधायक यदि किसी मंत्री को खत लिखे तो उसका उत्तर उन्हें समय पर मिले, ताकि बहुत सी समस्याओं पर सदन के अन्दर समय बच सकता है । तो माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण में कहा कि उन्होंने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला । हम इस बारे में आपसे व्यवस्था चाहते हैं । इस तरह से और भी बहुत से विधायकों ने पत्र लिखे, उनको भी यही शिकायत है कि मंत्री लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर उनको प्रश्नों के जरिए या दूसरे किसी जरिए से सदन में उन सवालों को उठाना पड़ता है तो मंत्रियों को पत्र का उत्तर देना चाहिए या नहीं, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न व्यवस्था का इतना नहीं है जितना कि परम्परा का । इसमें दो राय नहीं है कि चाहे माननीय सदस्य हों चाहे नागरिक हों, सामान्य तौर से सरकार के विभाग और मंत्रिगण जवाब देते हैं, विभाग को भी आदेश हैं कि निर्णय भले ही बाद में दें, लेकिन पत्र की पहुंच जरूर भेजी जाय, ऐसी व्यवस्था सरकार के नियमों में भी है । विशेष तौर से यदि माननीय सदस्य का पत्र हो तो सिर्फ उत्तर ही नहीं, बल्कि जो समस्या उठाई गई है उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जाय और माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संतोष दिया जाय । जिस पत्र का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे, ऐसी बात है तो मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि क्यों इनके पत्र का जवाब नहीं गया । लेकिन इसको सब स्वीकार करते हैं कि कोई पत्र भेजा जाय तो केवल पहुंच ही नहीं, जवाब ही नहीं बल्कि माननीय सदस्यों को पूरा संतोष हो इस बात की कोशिश की जाय ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही इस सदन की बहस कल समाप्त होने जा रही है । इस सदन में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कई मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। मैं एक मंत्री की हैसियत से उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करूं, वह काम तो मुझे करना ही है पर उसके साथ साथ मैं मेरे कुछ विचार, जो मुद्दे माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रखे हैं उनको और स्पष्ट करने के रूप में भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में हमारे प्रान्त की आज जो स्थिति है उसके बारे में एक सही चित्रण सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भाषण में जो देश की आज परिस्थितियां हैं, उन देश की परिस्थितियों में हमारे प्रान्त की क्या स्थिति है और हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सदस्य महोदयों का राज्यपाल महोदय ने आह्वान किया है कि लगातार आपको सतर्क होकर जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको आने वाले कई दिनों तक लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से काम करने को आवश्यकता रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों की लगातार पिछले दस पन्द्रह वर्षों में देश की आजादी के बाद एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश रही है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है। हम देश में वह समाजवाद कायम करना चाहते हैं। अभी जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह कल्पना उनको ठीक से समझ में नहीं आती, क्या समाजवाद है, किस समाजवाद में पहुंचना चाहते हैं किस तरह से उस समाजवाद में जावेंगे ? तो उसके लिए मैं ज्यादा न कह कर संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवाद के बारे में समय समय पर कांग्रेस की ओर से इस देश की जनता के सामने प्रस्ताव रखे गये हैं और उन प्रस्तावों में आखरी प्रस्ताव समाजवादी समाज की रचना का है जिसकी शुरूआत आवड़ी में हुई और जिसके बारे में भुवनेश्वर में और क्लैरीफिकेशन के साथ कहा गया कि वह कैसा समाज है जो हम इसमें बनाना चाहते हैं। उसमें कहा गया है कि इस देश में, देश में बसने वाले समूचे परिवारों, ४५ करोड़ जनता की बुनियादी जरूरतों, खास तौर से खाने-पीने की चीजों के दृष्टिकोण से, मौसम के अनुसार वस्त्रों के दृष्टिकोण से, पीने के पानी को सुचारु रूप से इन्तजाम करने के दृष्टिकोण से, हमारे देश के नवयुवक, नवयुवतियां, लड़के और लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से, देश के अन्दर लोगों को पूरा खाना, जैसा पौष्टिक चाहिए वैसा न मिलने के कारण और उसमें कमी रहने के कारण से उनके स्वास्थ्य में कमी रहती है उनको बीमारियों से बचाने के दृष्टिकोण से, हम इस देश में इस प्रकार बुनियादी जरूरतें देश के सभी लोगों को मुहैया कराना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इस देश में कोई बड़ा अमीर न हो, बहुत बड़ा गरीब न हो, देश के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करने के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिए हमारा जो माध्यम होगा वह देश के अन्दर।

(२. २५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उत्पादन बढ़ा कर, सही रूप में उसका वितरण किया जाय और उसके वितरण के सिलसिले में हमारी जो पुरानी परम्परायें रही हैं, उनमें परिवर्तन किया जाय, उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिए देश के अन्दर नये ज्ञान, विज्ञान और साइन्स के आधार पर नये शस्त्रों से उनको सुसज्जित कर जिन साधनों से देश के उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रख कर इस प्रकार के साधन देकर, नये नये ज्ञान विज्ञान देकर इस देश के जितने उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि की जाय। मैं सोचता हूं, प्रजातन्त्र के जरिये जिस देश में इस प्रकार की रचना और कल्पना को साकार रूप देना चाहते हैं उस प्रजातन्त्र में इन सारी चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इसका हल आज नहीं, आज से कई वर्षों पहले से, देश की जनता ने जनतन्त्र की पद्धति के जरिये देश की कांग्रेस की संस्था के कन्धों पर रखा, उस कांग्रेस संस्था के द्वारा संचालित राज्य के हाथों में रखा, उसने इस भार को सम्हाला और उसको स्वीकार किया, उस समय भी उसका बहुत साफ दृष्टिकोण था कि इस देश में किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाय और बढ़े हुए उत्पादन का नये रूप से वितरण किया जाय, इसके लिए योजनाओं का सहारा लिया गया। हम हमारे इस समाजवाद के स्वरूप को सही रूप में लाना चाहते हैं, जिसकी मंजिल अभी काफी दूर है। हम इन योजनाओं के जरिये से उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह मंजिल कितनी दूर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत दूर। आपको अभी सब्र रखना पड़ेगा।

इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले कई वर्षों तक कई योजनाओं के जरिये इस देश को इस प्रकार आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): समाजवाद कब्रिस्तान में आवेगा या इंग्लिस्तान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सब्र रखिये। मैंने आपको शान्ति से सुना, आप भी शान्ति से मुझे सुनिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी गौर से सुन रहा था और मुझे चिन्ता हुई सुनते सुनते।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने योजनाओं का निर्माण किया। पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना का चौथा वर्ष समाप्त होने जा रहा है और पांचवां वर्ष अभी इसमें बाकी है। हमने इन योजनाओं में लगातार, जैसा सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, देश में जो कुछ सीमित साधन हैं उन सीमित साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जाकर जिस प्रकार दूसरे देशों से सहायता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ली जाकर और देश के दूसरे साधनों को जुटा करके जितने भी साधन इस देश में उपलब्ध हैं उनके जरिये से किन चीजों को प्रायोरिटीज़ देकर, उन योजनाओं को बनायें इसका एक लक्ष्य शुरू से हमारे सामने रहा है। हमारे देश की और प्रान्तों की इन तीनों योजनाओं में, खास तौर से देश की जरूरतों की चीजें हैं उन्हें बढ़ाने की दृष्टि से, हमारी योजनाओं के द्वारा खास तौर से खेती-बाड़ी के उत्पादन की दृष्टि से, खास तौर से औद्योगीकरण की दृष्टि से, खास तौर से पॉवर को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, हमने हमारी योजनाओं में प्रावधान किया है। मैं आपके सामने, सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह कहना चाहूंगा कि देश की इन योजनाओं के जरिये से देश के उत्पादन पर असर हुआ है। खास तौर से एक ज्वलन्त समस्या है जिस पर सदन के माननीय सदस्यों ने पिछले कई सेशन्स में इस बारे में चर्चा की है, इस बार भी चर्चा खड़ी हुई कि देश की आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर के द्वारा पैदा होने वाली इन चीजों में कमी है और इस कारण मंहगाई बढ़ी है और लोगों को कष्ट उठाना पड़ा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह बात ठीक है कि देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें कुछ में थोड़ी कमी है, तो कुछ में ज्यादा है। उस कमी को पूरा करने के लिए चौथी योजना में इन चीजों के उत्पादन की दृष्टि से उन पर विचार करना है, उनको देखना है। पिछले १३–१४ वर्ष में देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। मैंने पहले भी यह बात कही है और माननीय सदस्य भी उसको स्वीकार करते हैं। सन् ५०-५१ में जहां खाद्य का उत्पादन ५० मीलियन टन था वहां इस साल खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर करीब करीब ६६ : ६७ लाख टन के लगभग होने की आशा है। उस कन्टेक्स्ट में यदि हम अपने प्रान्त की कुछ हालतों का खयाल करें तो भी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि जब राजस्थान का निर्माण और पुनर्गठन हुआ उस समय राजस्थान की अलग अलग रियासतें थीं और उस समय सन् ४६-५० का जो कुछ भी रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फीगर्स के रूप में उपलब्ध है उनकी जानकारी को लेकर देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कुल उत्पादन और खासतौर से खाद्यान्न का २८-२६ के लगभग था राजस्थान की इन योजनाओं के बाद जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राजस्थान ने किया उसका ब्योरा मैं आपके सामने रख रहा हूं।

हमने पहली योजना में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की योजना बनायी, आप सब जानते हैं पहली योजना बनी उस समय राजस्थान का एकीकरण होने जा रहा था। जिस प्रकार की व्यवस्था दूसरी और तीसरी योजनाओं में थी वह स्थिति पहली योजना में नहीं थी। पहला प्लान हमारा ५५ करोड़ रुपये का था उसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये ६.७५ धनराशि रखी थी। जो कुछ भी लेन्ड सिस्टम में परिवर्तन हुए उसका परिणाम राजस्थान में आया, ज्यादा

श्री नाथूराम मिर्धा]

जमीन काश्त के अन्दर आयी। पहली योजना के अन्त तक टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ३.५ टन ज्यादा खाद्यान्न का बढ़ा सके। इस प्रकार से प्रथम योजना के अन्त तक खाद्यान्न का उत्पादन ३२.३३ लाख टन था। इस उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दूसरा प्लान जो १०५ करोड़ का बनाया उसमें से लगभग १०३ करोड़ रुपया खर्च किया है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये शुरू शुरू में ४।। करोड़ रुपये का प्रावधान लेकर चले थे। उसके बाद कुछ धन ज्यादा मिल सका इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुल मिलाकर ५।। करोड़ का इम्प्यूट किया, उसका परिणाम राजस्थान के अन्दर जो खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा वह दूसरी योजना के अन्दर एडीश्नल ८ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने का था, माननीय सदस्यों को पता है दूसरी योजना का टार्गेट जो हमने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का रखा था उसका परिणाम अच्छा आया। कुल मिलाकर १०।। लाख टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया। इस प्रकार हमने दूसरी योजना के अन्त तक ४४ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जो राजस्थान पोटेन्शियल का एक्चुअल एवरेज लेकर चलते हैं वे दूसरी योजना को बेस मानकर चलते हैं।

तीसरी योजना में लगातार हम सतर्क थे; हमारी कोशिश रही खाद्यान्न का उत्पादन राज्य के लोगों के लिए करने हेतु। हालांकि राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की भी बढ़ रही है उत्पादन भी बढ़ रहा है, लोगों की पर्चेजिंग पॉवर भी बढ़ रही है, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, लोग खाने, पीने, कपड़ा आदि में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, राजस्थान के सरप्लस होने से देश की समस्या का हल नहीं निकलता। इसलिये राजस्थान ने तीसरी योजना के काल में उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में १०।। करोड़ का प्रावधान रखा। यह जो लक्ष्य रखा इस इम्प्यूट के जरिये आने वाले पांच सालों में राजस्थान के अन्दर राजस्थान १५ लाख टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन कर सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप जो फूड ग्रेन इम्पोर्ट कर रहे हैं वह कब तक बन्द कर देंगे ? आप कब तक स्वावलम्बी बन जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं सारे देश के लिये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुला हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन्टीग्रेटेड पिक्चर के अन्दर राजस्थान को बाहर नहीं निकाल सकते हैं यह ठीक है; लेकिन खाद्यान्न अब भी बाहर से आ रहा है। उसको आप कब तक बन्द कर पायेंगे ?

श्री विजयसिंह कटारा : वह मंजिल दूर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह खूब अच्छी तरह सोच रहे हैं कोई नया तरीका आप बना दें। आपको अवसर देने के लिये तैयार हूं। ये सारी चीजें आ रही हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हम चाहते हैं, देश में न आवें लेकिन जो तरीका प्रजातंत्र का है, जिस तरीके से काम चल रहा है उसी तरीके का तो हमें सहारा लेना पड़ेगा ।

राजस्थान में तीसरी योजना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लक्ष्य १५ लाख टन रखने का सोचते हैं और उसके लिये १०॥ करोड़ की धनराशि रखी है । तीसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया; सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, इस योजना के अन्त तक १३॥ लाख टन अधिक का उत्पादन होगा । उपाध्यक्ष महोदय, जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लक्ष्य ४५ लाख टन का था उसको बेस मानकर चले थे, तीसरी योजना के अन्त तक आंकड़े उत्पादन का लक्ष्य ६० लाख टन के लगभग पहुंचाना चाहते थे । हमारे राजस्थान में तीसरी योजना के सिवाय पहले साल को छोड़कर योजना के दो साल काफी मुसीबत के रहे हैं । इन सालों में राजस्थान के कई हिस्सों में अकाल की स्थिति रही है । पांच हजार गांवों में अकाल रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पिछले सेशन में आपने बताया था कि ८ लाख टन उत्पादन कम होगा, यह भी तीस लाख टन में से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछली दफा जो आंकड़े मैंने बताये उसके अनुसार हमें आशा थी कि हम ३२-३३ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन कर पायेंगे लेकिन जो रिवाईज्ड आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार हमारा उत्पादन ३८ लाख टन के लगभग रहा है ।

तीसरी और दूसरी योजना के हमारे जो लक्ष्य थे उसको देखते हुए, मैं समझता हूं, इस साल का हमारा खाद्यान्न का उत्पादन खरीफ ओर रबी दोनों का टोटल फीगर्स आने में अभी तीन चार महिने लगेंगे । मेरा ख्याल है कि तीसरी योजना के पिछले तीन साल जो गये हैं उनसे यह प्रोडक्शन का वर्ष सब से अच्छा होगा । इस साल का उत्पादन कम से कम ५८-५६ लाख टन लगभग होना चाहिये । जिस प्रकार की खरीफ की, रबी की फसल के समाचार आ रहे हैं उसके हिसाब से यह अन्दाज लगता है ।

राजस्थान के इन चार सालों के एवरेजेज को शरीक करें तो टोटल प्रोडक्शन के बेस को जो हम मान कर चलते हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि १५ लाख टन के बजाय १३ लाख टन एडीशनल उत्पादन की औसत आये । चार वर्ष के एवरेज का जो रुख रहा है उसके हिसाब से ६० लाख टन खाद्यान्न उत्पादन को बेस मानकर चलने का था इस बेस में ५७-५८ लाख तक मान कर चले ।

जो परिस्थितियां हमारे सामने है वे मैंने सदन के सामने रखने की कोशिश की है । खास तौर से विरोधी दल के नेता जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अब भी हमारे देश को खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता है,

Page No 76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसके बारे में पिछले सदन की मीटिंग में मैंने काफी डिटेल में कहा था। पर माननीय सदस्य अनुपस्थित रहने से उसको सुन नहीं पाते हैं तो उनको शिकायत रह जाती है। फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ देश का खाद्यान्न उत्पादन का सिलसिला रहा है वह निस्सन्देह देश की जरूरत को पूरा करने के लायक नहीं हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप सब भी जानते हैं। श्रौर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे निराश भी होने की जरूरत नहीं है।

हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को दुनिया के अन्य डेवलपिंग देशों के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अचीवमेन्ट के इतिहास से तुलना करके देखा जावे तो हमारे देश की रफ्तार और जो गति रही है, परसेन्टेज का इन्क्रीज रहा है और तीसरी योजना के आंकड़े जो संकलित किए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की औसत उत्पादन की रफ्तार हर साल तीन परसेन्ट के लगभग रही है। मैं दुनिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में जो कुछ भी पढ़ने और सोचने-विचारने के साधन मिल सकते हैं उनके आधार पर कह सकता हूं कि कुछ भी पढ़ने और सोचने–विचारने के साधन मिल सकते हैं उनके आधार पर कह सकता हूं कि दो–एक देशों को छोड़कर जिनका रिकॉर्ड हमारे देश के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड से ऊंचा रहा है हिन्दुस्तान का रिकॉर्ड बाकी देशों से आगे रहा है। इन दो देशों में एक है साउथ अमेरिका का ब्राजील और दूसरा स्वीडन, जिसका प्रोडक्शन का एवरेज तीन परसेन्ट, साढ़े तीन परसेन्ट और चार तक रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल–जयपुर) : इजराइल ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका तो दो परसेन्ट भी नहीं रहा है। यह मैं इसके पिछले आठ साल के रिकॉर्ड पर कह सकता हूं।

फिर हिन्दुस्तान के साथ और भी समस्यायें इसके साथ साथ जुड़ी हुई हैं और उनमें सबसे प्रमुख है जनसंख्या की वृद्धि। इसमें सिवाय एक मुल्क के, जो चीन है, की वर्थ रेट सबसे ज्यादा है जिसकी बढ़ोत्तरी का आंकड़ा २॥ परसेन्ट आता है, हिन्दुस्तान का भी करीब करीब यही आता है। हमारा वर्थ रेट भी २.४ के लगभग है हालांकि खाद्यान्न का हमारा रिकॉर्ड उत्पादन दुनिया में सिर ऊंचा करके चल सकें ऐसा है। इतनी देश की विभिन्नताओं के विभिन्न वातावरण के और जनतन्त्र के बावजूद भी हमारा यह रिकॉर्ड है ओर जो कुछ है, वह आपके सामने है। तो इन परिस्थितियों में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या हमारे सामने है जिसके बारे में विरोधी दल के नेता ने भी चिन्ता जाहिर की और जो विचारशील विद्वान् पुरुष हैं सदन के उन्होंने भी की।

श्री भैरोंसिंह : इस उम्र में सभी करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको-हमको सबको करना चाहिये। किसी भी देश के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इतिहास को देख लें, जिसने प्रगति की है उसने परिवार नियोजन को अहमियत दी है और आज तक लगातार देते जा रहे हैं। अमेरिका ने जिसने आर्थिक क्षेत्र में इतनी बड़ी तरक्की की है फेमिली प्लानिंग में दो बच्चों और तीन बच्चों को एक परिवार का सही आधार मानकर चलते हैं और बराबर प्लानिंग आज भी कर रहा है।

तो इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से आपके जरिये यही अपील करूंगा कि हम भी लगातार इस तरफ प्रयत्नशील हों। इसके लिये क्या करने की आवश्यकता है इसके बारे में आप सब जानते हैं। इसके लिए कानून के जरिये कोई वातावरण देश में बनाया जाय तो इससे ठोस लाभ नहीं मिल सकता बल्कि उल्टे रिएक्शन हो सकते हैं और प्रजातन्त्र के लिये यह रिएक्शन ठीक नहीं होगा। इसलिये इसके लिए देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाय। विचार पैदा करें हम, कि अगर देश में जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर सोचें। तो परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की आवश्यकता होगी। और इसके बारे में जो साधन जुटाने की आवश्यकता है उन सारी चीजों को हम हमारे देश और समाज में करें तभी जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।

इस दृष्टिकोण से जो कुछ खाद्यान्न उत्पादन के बारे में देश की तस्वीर है और जिसके साथ साथ राजस्थान की तस्वीर भी जुड़ी हुई है, उसका मैंने थोड़ा लेखा-जोखा किया।

इसके अलावा बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने पंचायत समिति के बारे में एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर के बारे में जिक्र किया। उनके काम से उनको सन्तोष नहीं है, वे देहातों में जाते नहीं हैं, जाते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सटेन्शन के बारे में जानते नहीं हैं और ज्यादातर अपने दौरे राजनैतिक दृष्टिकोण से रखते हैं, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से रख कर कोआर्डिनेट करें तो अच्छा है। और तो मैं इतना ही कह सकता हूं राजनीति तो जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। मैं राजनीति से परे होकर या इस सदन के माननीय सदस्य परे होकर सोचें या करें यह सम्भव नहीं है, जरूर राजनीति हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है; पर राजनीति ही हमारा सब कुछ मकसद हो मैं इस बात को कभी मानने वालों में से नहीं हूं यह मंजिल पर पहुंचने का माध्यम है जो कर्त्तव्य के दृष्टिकोण से आवश्यक है। मैं कर्त्तव्य को मानता हूं और इसे सबसे पहले करने की कोशिश करता हूं। जहां कहीं जाता हूं इरिगेशन, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू के अफसरों को प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से समझाता हूं, कलेक्टर, चैयरमैन है, उनको जोइन्टली मिलाता हूं कोऑर्डिनेशन करवाने के लिये। अब हो सकता है दुनिया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में सभी आदमी, सभी सरकार के अधिकारी लोग एक कैलीवर के नहीं होते; कई कम कैलिबर के भी हैं, कई ज्यादा के हैं। कइयों की तारीफ भी की गई है गांव के थे, अच्छी भाषा में बोलते थे। अच्छी सलाह भी देते थे। तो मैं दावा नहीं करता कि हमारे सभी अधिकारी एक ही तरह का ज्ञान रखने वाले हैं। ज्ञान में सब के अन्तर है। फिर भी आपने इस अधिकारी की शिकायत पहले कभी मुझे नहीं बताई, बताते तो मैं सोचता। पर जो बात कही कि व्यक्तिगत वैमनस्य न मेरा उससे है, न उसका मेरे से है। पर साथ ही फैक्ट्स लाते तो जरा अच्छा रहता। फिर भी मैं इस पर ध्यान दूंगा और एग्रीकल्चर के अपने टार्गेट को अचीव करने के लिये जिन जिन साधनों की अच्छा खाद, रासायनिक फर्टीलाइजर, सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में सही राय ऑर्गेनिक मेन्योर आदि सप्लाई की जावेगी जैसा आपने इन सब के बारे में कहा। ये बुनियादी जरूरत की चीजें हैं। किस खाद को किस खेत में कितनी तादाद में किस मौसम में कितना कितना दिया जावे; सोइल में किन किन तत्वों की कमी है हर खेत में यह डिफरेन्ट है और हर खेत की सोइल का अनेलिसिस करने की क्षमता आज विभाग के पास नहीं है। न इतने साधन हैं। न टेक्निशियन हैं। खाद की रिकमन्डेशन के बारे में जनरली जो हमारे इलाके की सोइल का क्लासिफिकेशन है उसके ब्रॉड दृष्टिकोण से वर्गीकरण करके उसको ध्यान में रखकर उन इलाकों को देने का हमारा दृष्टिकोण है। इन इलाकों में नाइट्रोजन है; कम है, इतनी मात्रा में है, फलां में फोस्फेट की कमी है तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। फिर विशेष तौर से रुचि रखने वाला किसान अगर चाहता है कि सोइल का उसकी खेत का टेस्ट होकर फिर खाद उसमें एप्लाई किया जावे तो ऐसे लोगों के लिये लेबोरेटरी का हमारे पास प्रबन्ध है। वे अपने सोइल के नमूने वहां भेजें। जोधपुर में है, जयपुर में है, कोटा और उदयपुर में है, बीकानेर में भी है। इन लेबोरेटरियों में सोइल के सेम्पल का अनेलिसिस किया जा सकता है।

अब राजस्थान में हर खेत का सोइल क्लासिफिकेशन हो, एब्सोल्यूटली हर सीजन के अनुसार उनमें वेरिएशन्स भी होते हैं, इनग्रेडिएन्ट्स भी होते रहते हैं और यह बहुत ही टैक्निकल विषय है। आप और कोई टैक्निकल लाइन ले लीजिये, इन्जीनियरी है, डाक्टरी है, पशु पालन है, इनके मुकाबले में एग्रीकल्चर के जितने प्रोब्लेम्स हैं, दुनियां में हैं, हिन्दुस्तान में हैं, और फिर राजस्थान में हैं उन सारे प्रोब्लेम्स का सही प्रकार से हल निकाल कर वैज्ञानिक तरीकों से निवारण कर लें और खास कर राजस्थान जैसे प्रांत में जहां अनुसन्धान की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और भी कठिन काम है। जहां है वहां अनुसन्धान इस क्षेत्र में करने वाले व्यक्ति नये नये हैं। तो ये कई सारी कमजोरियां और समस्याएं हैं जो मेरे अकेले के एक दिन में चाहने से हल नहीं हो सकतीं। इसको तो ठीक करने के लिये लम्बे समय तक हमें उन लोगों को अवसर देना होगा। थोड़े से एक रिसर्च करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, दस-बीस साल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लग जाते है और उसमें से एक ऐसी चीज निकल जाती है जो कि देश के भाग्य को बदल सकती है। कहने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्य कोशिश करें तो इसमें भी ज्यादा काम हो सकता है। प्रोडक्शन के बारे में मेरे अकेले के बात करने से काम नहीं हो जाता। राज्यपाल महोदय ने इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मांगा है और इसके लिए हमें सही प्रचार करने के लिए, सही दृष्टिकोण लोगों को देने के लिए सब लोगों को प्रेरणा देने की आवश्यकता रहेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में जो कुछ मैंने कहा वह वास्तविक स्थिति है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बातें और कहनी हैं, इसलिए एक ही सब्जेक्ट पर कहता जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा।

अब मैं खास तौर से जैसा मैंने कहा कि समाजवाद की मन्जिल पर पहुंचने के लिए कई साधनों की आवश्यकता रहती है। वे साधन जुटाने के लिए हमारे पास जो पब्लिक फाइनेन्स के बेसिक प्रिन्सिपल्स हैं उनको ध्यान में रखें तो साधनों को जुटाने के लिए देश के लोगों में जितना इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है उसके लिए हमें कर्ज के रूप में धन लेना पड़ेगा और साथ ही जिन चीजों पर हम टैक्स लगा सकते हैं और जिस वर्ग पर टैक्स लगा सकते हैं जो टैक्स देने की क्षमता रखता है उनसे टैक्स के रूप में हमें पैसा लेना पड़ेगा। दुनिया के दूसरे देश जो हमारे प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जो हमारे प्रजातंत्र के जरिये देश के लोगों के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए मदद देना चाहते हैं उन लोगों से जितना कर्ज लेना चाहते हैं वह कर्ज लेते हैं और हमारी योजनाओं को पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस सदन में बैठकर सुनते हैं वह तो सुनते ही हैं लेकिन बाहर का जब हम वातावरण सुनते हैं और खास तौर से विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से वे इस प्रकार के प्रचार करते हैं कि जो कर्जा लिया जाता है तो उससे देश को दिवालिया बना दिया जाता है। हम लोग टैक्स की बात करते हैं तो उसकी हिमायत बाहर इस तरह से की जाती है कि लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। जिस प्रकार के नारे आज देश में विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से उठाये जाते हैं; जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है कि क्या जनता के ऊपर टैक्स का बोझा नहीं डाला जाये या कर्ज लेकर क्या भारत सरकार अपनी योजनाओं को नहीं चलाये? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। इस सदन को पूरी छुट्टी है कि किन लोगों के ऊपर कितना टैक्स का बोझा डाला जाये, यह सदन के फैसला करने की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि योजनाओं के जरिये प्रजातंत्र के माध्यम से हम लोगों का स्तर ऊंचा उठायें। सिवाय विकास के कोई और दूसरा दृष्टिकोण इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। हमें यह दृष्टिकोण अपना कर चलना पड़ेगा कि देश के लोगों की और हमारे राज्य के लोगों की जैसी क्षमता है मैं नहीं कहता कि हम सारी समस्याओं को हल कर लेंगे। आज हम नहीं कह सकते कि

Page No 80

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राज्य में बेकारी नहीं है और सब लोगों को जितनी चीजों की आवश्यकता है वह सब को मिल गई हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों के सामने खुले रूप से कहकर चलना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने दिलों को टटोलें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस देश के अन्दर इस बात को कह सकते हैं आप कि इन योजनाओं के चालू हो जाने के बाद और जो कुछ व्यवस्था वितरण के बारे में रही है उसके बाद लोगों का बहुत आर्थिक विकास हुआ है। कुछ क्लासेज़ जो कि हजारों में थीं उनकी लाखों में बात गयी और जो लाखों के थे वे करोड़ों पर पहुंच गये। मैं इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं कि गरीब गरीब हो गए। मैं सोचता हूं कि मैं भी राजस्थान में काफी घूमता हूं, मैंने गरीबों को भी देखा है, मैं भी उनके बीच में जाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं। चाहे आप मजदूरी करने वालों को ले लें, लेण्डलैस लोगों को ले लें, किसानों को ले लें या किसी भी आदमी को ले लें जब तक कि ईश्वर ने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेन्ट नहीं कर दिया हो, चाहे वह एक्सीडेन्ट आग का हो, डाके का हो या चोरी का हो या असामयिक मृत्यु का हो, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप मानेंगे कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसके बाद जो कुछ वह पहले खाते थे, दस–बारह वर्ष पहले जो कुछ वे पहिनते थे, जो सुविधायें उनको पहले थीं उनमें लगातार सुधार हुआ है। खाने के दृष्टिकोण से, पहिनने के दृष्टिकोण से, मकान के दृष्टिकोण से जो कुछ साधन उपलब्ध थे उनको देखते हुए मुझे अच्छी तरह याद है कि दस–पन्द्रह साल पहले जब मैं गांवों में घूमता था तो मैंने किसी भी गांव में सिवाय पांच सात परसेन्ट लोगों के पास कांसी पीतल के बरतन नहीं देखे, किसी के पास पहनने को एक कपड़ा और किसी के पास दो कपड़े। आज कम से कम दो तीन वस्त्र पहिनने को मिलते हैं, पानी पीने के लिए पीतल का लोटा मिलता है, खाने को कांसी की बाटकी और कटोरा भी मिलता है। आज उनको ओढ़ने को, पहिनने को और खाने को अच्छी तरह मिलता है। मैं समझता हूं कि उनमें परिवर्तन जरूर आया है, चाहे रुपये में आना भर ही परिवर्तन आया हो। इसलिए मुझे आशा बंधती है और सदन के माननीय सदस्यों को भी आशा बंधनी चाहिए कि हमारी जो दिशा और लक्ष्य है वह सही है। हो सकता है इसमें और सुधार किया जा सकता है, तेजी लाई जा सकती है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का विश्वास तो माननीय सदस्यों को बढ़ाना ही चाहिए कि लक्ष्य और कदम हमारा एक दिशा की ओर बढ़ा है, उठा है वह सही है और मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। खास तौर से जो नीचे के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए हमें और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और हम चाहें तो अपने तरीकों में और भी विशेष परिवर्तन कर सकते हैं।

मैं जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और बढ़ाने की बात को कह रहा था और देश के

Page No 81

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सब लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े। तो उस सम्बन्ध में जिस किसान को आज तक परम्परागत पीढ़ियों के डिमाण्ड और सप्लाई के नारे पर छोड़ रखा था अब हमने उसको एक नया मोड़ दिया है और हमारे भाव वही होंगे कि जो कि भाव राज्य के हों। उसको किस भाव पर चीजें खरीदनी पड़ेंगी और बेचनी पड़ेंगी, इसका मतलब डिमाण्ड और सप्लाई से था। भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने और देश की दूसरी सरकारों ने जो इस साल में नया मोड़ लिया है और जिसके लिए राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया वह यह है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और देश ने सबसे पहले एक नीति का ऐलान किया कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की खास तौर से कुछ कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ को अमुक कीमत से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर वे उस प्राइस से नीचे बिकेंगी तो उन सारी चीजों को सरकार स्वयं खरीदने की व्यवस्था करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा बुनियादी मोड़ देश की भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने लिया है जो कि हिन्दुस्तान की ७५ प्रतिशत किसान जनता के लिए है। आप इस प्रकार का सिद्धांत दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ देशों में भी पायेंगे। अमेरिका में जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा तरक्की हुई वहां इस प्रकार की व्यवस्था है कि सिर्फ १३ चीजों के ऊपर गारन्टी दे रखी है कि अमुक कीमतों से यदि किसान के भाव नीचे जायेंगे तो उसको अमेरिका की सरकार चाहे उसे उस चीज को दुनियां के दूसरे देशों को भेजना पड़े या समुद्र में डुबाना पड़े; लेकिन किसान के माल को उस कीमत पर खरीदेगी। हमने पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर इस नीति को अख्तियार किया है और मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य क्योंकि इधर भी किसान हैं तो उधर भी किसान हैं। किसानों के लिए नया परिवर्तन और नया मोड़ हमारे देश के सामने आया है उसके लिए हमें राज्यपाल महोदय का सचमुच तौर से कृतज्ञ होना चाहिए और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सिलसिले में जहां बढ़ोतरी की बात करते हैं, जहां समाजवाद की मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं राजस्थान सरकार लगातार जिन विभागों का जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं समझता हू कि सिंचाई का विभाग भी ऐसा विभाग है जो कि किसानों के दृष्टिकोण से बहुत अहमियत रखता है। हम हमारी सिंचाई की योजनाओं के लिए लगातार जागरूक रहे हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना का जैसा कि मैंने जिक्र किया, जिसका करीब ५५-६० करोड़ के लगभग उस योजना का आकार था उसमें से २३ करोड़ पहली पंचवर्षीय योजना पर सिंचाई के साधनों पर खर्च किया गया, भाखरा योजना की शुरुआत की गई। उसके साथ साथ मीडियम और माइनर इरिगेशन के कई काम अपने हाथ में लिए और उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के अन्दर जिन योजनाओं को हमने पहली बार पंचव-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

र्षीय योजना शुरू की उसमें २३ करोड़ की धनराशि को खर्च करके योजना के अन्दर सिर्फ उतने ही काम को पूरा कर सके कि हमने पहली योजना में १-८ लाख एकड़ एडीशनल इरिगेशन पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर और बढ़ोतरी की ।

(३. ०० म० प०)

इसके साथ साथ हमारे राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर सिंचाई के साधनों के अन्दर विस्तार की गुन्जाइश को हमेशा सामने रखा और राजस्थान में हमने दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्दर मीडियम और माइनर इरिगेशन पर करीब करीब २१ करोड़ की धनराशि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्दर खर्च की । उन योजनाओं का भी परिणाम आया और पहली पंचवर्षीय योजना की बहुत सी योजनाएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी की गई । उसके जरिये मेजर इरिगेशन की स्कीम और मीडियम इरिगेशन की स्कीम्स की सिंचाई के परिणाम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने करीब करीब साढ़े सात लाख एकड़ एडीशनल की वृद्धि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर की । और माननीय उपाध्यक्ष, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी हमने करीब १७-१८ करोड़ की व्यवस्था की थी । उस आकार के अन्दर जितना खर्च किया जा रहा है उस हिसाब से तीसरी पंचवर्षीय योजना में करीब १७ करोड़ हमारी इस योजना के अन्त तक खर्च होगा और पहली पंचवर्षीय योजना के जो काम ग्रधूरे रह गये और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो काम रह गये थे वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरा किया जा रहा है और मीडियम और माइनर इरिगेशन की व्यवस्था के जरिये इस योजना के अन्दर हम करीब करीब १० लाख एकड़ की सिंचाई की योजना राजस्थान के अन्दर इस योजना के अन्त तक लागू कर सकेंगे । इस प्रकार मेजर मीडियम और माइनर इरिगेशन के जरिये हमने तीन योजनाओं के अन्दर कुल मिलाकर १७-१८ लाख एकड़ के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था की, किसानों के खेतों पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन के माननीय सदस्यों की उन योजनाओं के बारे में आलोचनाएं सामने आती हैं, मैं नहीं कहता कि आलोचनाओं में तथ्य नहीं है । आलोचनाओं में तथ्य भी हैं ग्रौर खास तौर से चम्बल के बारे में सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि चम्बल के अन्दर जिस योजना के जरिये हमने पूरा किया उस योजना में चम्बल के लिए करीब ८५-९० करोड़ की धनराशि कोटा बैरेज के ऊपर, गांधी सागर के निर्माण के ऊपर और नहरों के निर्माण के ऊपर आज तक खर्च कर चुके हैं । और माननीय उपाध्यक्ष, ९० करोड़ की धनराशि काफी बड़ी धनराशि है । उस धनराशि को खर्च करने के कारण ३ करोड़ के करीब का इन्ट्रेस्ट पिछले साल से राजस्थान सरकार को चुकाना पड़ रहा है । राजस्थान में चम्बल योजना पर इतने बड़े आकार पर रुपया खर्च करके ५ या ६ लाख एकड़ का जो चम्बल का इलाका है— कोटा जिला और बूंदी जिला है उनमें इस रकबे की सिंचाई को जल्दी से जल्दी फैल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जाय, लेकिन उस सिलसिले में वहां की पृष्ठभूमि है, जिसके बारे में इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते है कि उस इलाके में ४०-५० इंच बरसात होती है ग्रौर वहां के किसान की आदत उस बरसात के अन्दर उस तरह की है । राजस्थान के अन्दर हाड़ौती का इलाका अकाल पड़ने वाले इलाके के लिए परम्परागत आश्रय देने वाला इलाका है । कैसा भी रद्दी साल हो जब कि हमारे राजस्थान के कई इलाकों में अकाल होता है तो चम्बल के एरिया में, कोटा में, खास तौर से २५-३० इंच बरसात होती है तो वहां पर खरीफ की फसल में ज्वार-मक्का बोने की उनकी आदत रही है । उसको बदल कर दूसरी फसल बुआने का काम आसान नहीं है । वहां उस चम्बल के इलाके में वाटर लोगिंग का प्रोब्लेम सिरियस है । वह प्रोब्लेम अब सरकार के सामने आया है और ५ करोड़ की धनराशि से उस योजना का समाधान करना चाहते हैं । यह कहा गया है कि पहले इस बात को क्यों नहीं सोचा गया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस बात को सोचा गया था' लेकिन वह प्रोजेक्ट जिस समय निर्माण करवाने की बात थी उस समय ऑलरेडी इतना हैवी खर्चा हो गया था और उसका रिटर्न जो कुछ आ रहा था मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से खास तौर से कुछ इधर के और कुछ उधर के बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि किसानों को कहना चाहिए कि वे बेटरमेंट लेवी दें, जो कि चम्बल में हमने बहुत थोड़ी रखी है और तीन साल से उसकी मैच्योरिटी हो गई है । लेवी के इन्स्टालमेंट देने की बात कही जाती है तो वहां के लोग कहते हैं कि बेटरमेंट लेवी नहीं दे सकते हैं, नहरों में सीपेज हो रहा है, वाटर-लोगिंग हो रहा है और फसल पूरी पैदा नहीं हो रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बेटरमेंट की एक इन्स्टालमेंट १०-१२ साल में ढाई-तीन रुपया पर एकड़ का नहीं देना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ६० करोड़ का खर्च करके ३ करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट को पिछले साल से ब्याज चुकाना पड़े । एक साल में जितनी सिंचाई चम्बल के अन्दर डेवलप की है वह इस साल में खर्च करने पर २ लाख एकड़ सिंचाई होगी जिसका रिटर्न राजस्थान के अन्दर ११५ लाख या ११६ लाख मिलेगा । ११५ या ११६ लाख इस साल वाटर रेट्स के इकट्ठा करके विभाग के मेन्टीनेन्स के सिलसिले में चम्बल के एरिया के अन्दर करीब ६०-६५ लाख का खर्चा करना पड़ेगा । जहां कुल वाटर रेट मिला कर ३०-४० लाख की बचत एक साल में है, जस योजना पर ३ करोड़ रुपया ब्याज का चुकाना पड़ता है, उस योजना के बारे में इस सदन के माननीय सदस्य कहने लगें कि बेटरमेंट लेवी नहीं देनी चाहिए । कैसे दे ? देना वाजिब नहीं है । दें तभी कि जब कि सारी पुलियां बन जायं, वाटर कोर्स न बन जायं । जनरली वाटर कोर्सेज़ के बनाने का जिम्मा इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि किसानों का है । अगर किसान नहीं बनायें तो वाटर कोर्स बनाने के लिए राज्य सरकार को करना पड़ेगा और उसकी कीमत उनसे राजस्थान सरकार इन्स्टालमेंट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में वसूल करेगी। वह वाटर कोर्स चम्बल के पूरा एरिया में पानी पहुंचाने के लिए ६ हजार मील लम्बे बनाने हैं जिसमें साढ़े चार-पांच हजार मील का काम पूरा कर दिया है। उसकी वसूली के लिए कहते हैं तो उनको एतराज होता है। एक तरफ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों का ब्याज दिया जाय और उससे पैदावार बढ़ती है तो वाजिब तौर से किसान को इन्स्टालमेंट का बोझ उठाना पड़ता है तो उसको उठाने के लिए तैयार करने के लिए वातावरण नहीं बनायें तो मैं सोचता हूं कि इस देश को समाजवाद की मन्जिल तक पहुंचाने के अन्दर बहुत ज्यादा वर्ष लग जायेंगे और आगे का काम ठप्प हो जायेगा। योजनाओं के बड़े बड़े काम काफी कर चुके हैं और जो कुछ कम रिटर्न वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें अगर और रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो कुछ भी खर्च किया है उसके लिए वाजिब बात यह है कि वाजिब रुपया अपने हिस्से का किसान चुकाये, इस प्रकार का एक वाजिब वातावरण बनायें। और जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं हम उन समस्याओं के बारे में जागरूक हैं। हम जानते हैं कि वहां पर वाटरलॉगिंग की स्थिति है वह ० से ५ फुट और ५ फुट से १० फुट तक की है। अगर ० से ५ फुट तक का करेंगे तो एक लाख एकड़ से साढ़े पांच लाख एकड़ में वह रकबा बनता है। उसकी वाटरलॉगिंग कन्डीशन को मिटाना है। जैसा कि हमने कहा है कि उसको मिटाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में जिसका कि आकार सदन के सामने गवर्नर साहब ने थोड़े रूप में रखा है, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में ड्रेनेज की प्रोब्लम को हल करने के लिए दो करोड़ की धनराशि का प्रावधान चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा है। वह काफी बड़ा है उसको फेजेज़ में पूरा कर सकते हैं। अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि १३-१४ लाख वाटर टेबल ० से ५ फुट के बीच में है वहां ऐसे ६ प्रोजेक्ट करीब १८,००० एकड़ के लगभग हैं। वहां पर इस प्रोब्लम को टेक-अप करने के लिए चम्बल कार्ड की गत मीटिंग में १३-१४ लाख की स्कीम को मैंने तय करवाया है। हम चाहते हैं कि अगली बरसात से पहले जहां कि इस प्रकार का प्रोब्लेमेटिक एरिया है और जहां इस प्रकार का पानी इकट्ठा होकर किसान की ज़मीन पर जो कुछ पैदा होता था वह पैदावार भी न हो; सर्व प्रथम इस प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद में पुलियों की समस्या को लेंगे। उनको पक्का हम करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन यह सीज़न ऐसा है कि नहर को बन्द नहीं कर सकते क्योंकि जैसा वहां का क्रोप पैटर्न है उसमें हम वह नहीं कर सकते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन चीजों को हमें हल करना है। उनका सामना हमको करना पड़ता है।

इन सारी चीजों के बीच का रास्ता निकाल कर जिन इलाकों में नहरी सीपेज हो रहा है, लाईनिंग किया जाय, वाटर लोगिंग की प्रोब्लम ठीक की जाय, इसके लिए हम जागरूक हैं। किसानों की प्रोब्लम कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा उनकी शिकायत न हो, इस बात का प्रयत्न सरकार की ओर से किया जाता है। मैं उधर ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करता हूं। उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इलाके में गन्ने की बुवाई की जाय, चावल का रकबा बढ़ाया जाय, खास तौर से खरीफ का रकबा अभी १६००० एकड़ के करीब पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि इसका रकबा आने वाली फसल तक कम से कम १ लाख एकड़ पहुंचे ताकि इस पानी को यूज़ कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। हमें गन्ने की जरूरत है, चावल की बहुत जरूरत है। बाहर से चावल मंगाने में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। चंबल के बारे में चर्चा इस सदन में माननीय सदस्य समय समय पर करते रहते हैं, उस तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। सरकार सब प्रोब्लम्स की तरफ सजग है और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रही है। इरिगेशन के युटिलाइजेशन के बारे में मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र योजना के अनुसार करूं, राजस्थान में जो पोटेन्शियल बना है जो उसका हमारे यहां यूज़ है, भारत सरकार के अनुसार ७०-७२ पर्सेन्ट आता है और जगह का, लेकिन राजस्थान का पर्सेन्टेज ९० आता है.......

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, आपने फरमाया कि गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे क्या वाटर लोगिंग नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन स्कीम्स को हाथ में लेकर उनके साथ गन्ने का कल्टीवेशन करेंगे तो वाटर लोगिंग नहीं बढ़ेगा। इस पर हमने काफी चर्चा की है। टैक्निकल लेवल पर विचार किया है, इससे ज्यादा गन्ना पैदा होगा। मैं यह भी सूचना सदन को देना चाहता हूं कि हम एक मिल भी वहां पर डालना चाहते हैं ताकि चीनी पैदा होने में गन्ने की ज्यादा से ज्यादा खपत हो। मैं वहां पर कह कर आया हूं कि सहकारिता क्षेत्र में किसान लोग २५ लाख रुपया इकठ्ठा करें तो हम वहां पर चीनी की मिल खोल सकते हैं। चीनी की मिल खोलने में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होते हैं उनमें से १ करोड़ रुपये भारत सरकार देगी, २५ लाख रुपये राजस्थान सरकार देगी और २५ लाख रुपये वहां की जिला समितियां और पंचायत समितियां से मैं मिला था तब उनसे कहा था कि वे यदि चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र में यह मिल लगे तो वे २५ लाख रुपये इकट्ठा करें। मैंने यह आश्वासन दिया है कि लाइसेन्स दिलाने के सिलसिले में और जो हिस्सा सरकार को देना है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसकी तैयारी वे दो-तीन महीनों से कर लें तो हम जल्दी से जल्दी खोल सकते हैं।

इस तरह चंबल के बारे में मैंने दो-तीन बातें कहीं। राजस्थान में वाटर के बारे में, कृषि और सिंचाई के बारे में लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दोनों महकमों का समन्वय, कोओर्डिनेशन इस प्रकार कराया जाय कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो इरिगेशन पोटेन्शियल मिल रहा है उसका अच्छी तरह से उपयोग हो सके। चंबल एरिया के बारे में जो बातें हैं वे मैंने आपके सामने रखीं इसको छोड़ कर दो तीन प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके जमीन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का एस्टीमेट नहीं होने से या नहर की प्रोब्लम ठीक नहीं होने से पहले यूज़ नहीं हो रहे थे। मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना के अंत तक मेरे विभाग के अन्तर्गत राजस्थान में जितना पानी अवेलेबल है उसका ठीक से उपयोग किया जाय। चंबल में हम इसको ४ लाख एकड़ पहुंचाना चाहते हैं, अगले साल के आखिर तक यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो जितने सीड की आवश्यकता होगी, जितने फार्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार के इन विभागों की तरफ से पूरा करने की आवश्यकता होगी, बराबर मैं पूरा करूंगा और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में वाटर पोटेन्शियल का युटिलाइज़ेशन सेन्ट पर्सेन्ट तीसरी योजना के अंत तक हो और उसमें कमी न रहे, क्योंकि आज देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एक एक दाने की, उसकी कीमत है। जहां जमीन और वाटर उपयोग करने को है वहां उसका उपयोग हम यदि नहीं कर सकें तो यह हमारी ही कमजोरी है।......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह बता दें कि इस समय टोटल प्रोडक्शन कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीनों योजनाओं का खरीफ का १८ लाख एकड़ बताया और इस साल तीसरी योजना में हम ७।। लाख एकड़ तक पहुंच चुके हैं......

श्री भैरोंसिंह : आउट ऑफ १८ लाख ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने मेजर और मीडियम का बताया है। मेन काम है पोटेन्शियल यूज़ करने का, जो २.५ एकड़ पहुँचना था; उसके बजाय २.२ लाख एकड़ तक पहुंचा है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ७।। लाख एकड़ तो आपके कहने के अनुसार आपने सेकन्ड प्लान में कर डाला और १० लाख थर्ड में कर डाला और १.३ लाख पहली योजना में कर डाला। कुल मिलाकर सब सिंचाई में १७-१८ लाख एकड़ का युटिलाइज़ेशन आपके अनुसार हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि ६० पर्सेन्ट हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : १८ लाख तो हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना यूज़ हमको करना था या जो सेन्ट पर्सेन्ट हमारा लक्ष्य था उसमें से हमारा ६० पर्सेन्ट युटिलाइज़ेशन है।......

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में इस समय टोटल इर्रिगेशन प्रोडक्शन कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था। माइनर इर्रिगेशन की बात अब करूंगा। माइनर इर्रिगेशन हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में १.२ या १.३ लाख एकड़ किया था। सेकन्ड प्लान में कुल मिलाकर ५ लाख एकड़ माइनर इर्रिगेशन किया था जिसमें कुओं कों रिपेयर्स, नये कुएं और टैंक्स

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बनाना जिनको माइनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स कहते हैं उनको सेन्ट परसेन्ट किया है, एक भी एकड़ की कमी नहीं रही । इसलिए राजस्थान में माइनर ईरिगेशन में जितने ५-६ लाख के आंकड़े तीनों योजनाओं में मिलाकर बनते हैं और जितना पैसा उसके लिए प्रोवाइड किया था उससे दुगुना हमने खर्च किया है । माइनर ईरिगेशन का जितना पोटेन्शियल बनना था उसको पूरा किया है। मेजर के सिलसिले में मैंने चंबल का जिक्र किया । इसी प्रकार दो-तीन प्रोजेक्ट्स और हैं चित्तोड़ में गंभीरी-जिसमें थोड़े हजारों में प्रोडक्शन में कमी रहती है........

श्री भैरोंसिंह : आप क्षमा करेंगे । मैं समझता हूं, आपकी योजना की रिपोर्ट्स निकली है और बार बार आपके स्टेटमेन्ट्स निकले हैं, उनमें एक चीज क्लेरिफाइड नहीं है कि टोटल एलॉटमेन्ट और ईरिगेशन प्रोडक्शन कितना था, टोटल परसन्टेज कितना कवर अप कर पाये और कितना युटिलाइज़ेशन कर पाये.......

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास हरेक के आंकड़े प्रोजेक्टवाइज़ मौजूद है, काफी लंबा है, इसलिए यहां पढ़ कर नहीं सुना सकता । बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बिना रिकॉर्ड देखे जितना याद रख सकता हूं उतना बोलता हूं एक एक के डिटेल्स मौजूद हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक एक का नहीं चाहता, टोटल चाहता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी योजना का कितना बना, कितना यूज़ हो रहा है, यह बता देता हूं । भाखरा का कुल मिलाकर ५।। लाख एकड़ इस योजना के आखिरी साल तक यानी थर्ड योजना के फोर्थ ईयर के अन्त तक यूज़ करना था, उसमें से ५ लाख एकड़ हम एक्च्युअली यूज़ कर चुके हैं और एक साल जो अभी बाकी रहा है उसमें ५ लाख एकड़ जो बाकी रह गया है वह पूरा कर देंगे । इस तरह से एक साल जो बाकी बचा है उसके पूरा होने तक भाखरा का पूरा पोटेन्शियल यूज कर सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और एग्रीकल्चर जो काफी एक दूसरे से सम्बन्धित महकमें हैं उनका कोऑर्डिनेशन करके जो कुछ किया जा सकता था, उसके बारे में मैंने माननीय सदस्यों के सामने तस्वीर रखी । आखिर मैं ज्यादा समय न लेकर एक जो खास महत्वपूर्ण विषय है जिसमें माननीय सदस्यों की रुचि है । जैसी जैसी स्थिति रही है उतनी आलोचनात्मक और व्यंगात्मक जो रही है, वह है खाद्यान्न के वितरण की समस्या । खाद्यान्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की आलोचना इतनी रही कि महंगाई चल रही है । मैं मानता हूं कि महंगाई के बारे में हमको सोचना पड़ेगा ।

जब देश की योजनायें बढ़ रही हैं, देश के अन्दर योजनाओं के जरिये पैसे का फैलाव हो रहा है, देश के अन्दर योजनाओं के जरिये पैसे के फैलाव के साथ जिन चीजों की मांग है, उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, तो निश्चित तौर से ज्यादा पैसे का फैलाव होने से, लोगों को वितरित होने वाली चीजों की ज्यादा मांग होने से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और उचित मात्रा में वे चीजें उपलब्ध नहीं होने से इन्डैक्स में बढ़ावा आया है। हम यह नहीं मान सकते कि हमारे इन्डैक्स के आंकड़े जो १९५१-५२ में थे, उसके अन्दर किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं है, उसमें किसी प्रकार की तेजी नहीं है। लेकिन तेज गति से पिछले महीनों में बढ़ावा आया है। अगर १०० का आंकड़ा १९५१-५२ का मान कर चलें तो कुछ चीजों में वह आंकड़ा १३२ से १३६ तक पहुंच गया है और जो पिछले दो साल पहले १२२ और ११९ के अन्दर चल रहा था उसके अन्दर कुछ महीनों में चढ़ाव आया है और उस तेजी से आने से चढ़ाव को हम मंहगाई कहते हैं। मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस आंकड़े के अन्दर पिछले कुछ दिनों से गिरावट आई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का इस वर्ष उत्पादन रहा है, इसी मुकाबले का अगर आगे वाले वर्ष में रहा तो आपका यह इन्डैक्स का आंकड़ा कुछ नीचे उतर कर कुछ ठीक जगह पर टिक जायगा और आगे आने वाले दो-तीन साल के लिए अच्छी तरह चल सकता है, बशर्ते कि आने वाले साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक हो क्यों कि टोटल प्रोडक्शन के अन्दर यह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और टोटल प्रोडक्शन का यह एग्रीकलचर प्रोडक्शन करीब पचास प्रतिशत हिस्सा बनता है। और इस दृष्टि से राज्य में, प्रान्त में और देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, अकाल की, अतिवृष्टि की और शीत लहर की, उनसे हमारे प्रोडक्शन के ऊपर और पर-कैपिटा प्रोडक्शन के अन्दर खास असर पड़ता है। खैर, इन बारीकियों में हमारे मुख्य मंत्री और योजना मंत्री जायेंगे, इस इन्डैक्स के, प्रोडक्शन के उतार-चढ़ाव और पोटेंशियलिटी वगैरह की डिटेल्स में वे जायेंगे...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बहुत बड़ी जगलरी है, इसलिए नहीं पड़ना चाहते।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, जगलरी है तो वह हर तरफ ही है। इसी तरह का नाप-तोल का तरीका होता है आजाद देश के अन्दर।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था उन बारीकियों में हमारे मुख्य मंत्री और योजना मंत्री जायेंगे।

मैं तो अर्ज कर रहा हूं खाद्यान्न के मामले में। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कानून-कायदों में परिवर्तन तेजी से किये गये। जब राजस्थान में धान मिल नहीं रहा था तो महाराष्ट्र और गुजरात में मिल गया, इस तरह की बातें कहीं गई। मैं सोचता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, सारी परिस्थितियों को एक तरह से देखने और सारे देश को एक तरह से देखने की कोशिश करें क्योंकि राजस्थान में जिस नीति का निर्माण किया खास तौर से मार्च, १९६४ के पहले सिवाय राजस्थान के सब जगह चावल के निर्यात और आयात के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे, हमारे यहां कोई नहीं था। उस समय को छोड़ दीजिये। उसके बाद राजस्थान में मार्च १९६४ के अन्दर हमने फसला किया, राजस्थान व्हीट का जोन नहीं है इसलिए राज-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्थान के बाहर न गेहूं जा सकेगा और न आ सकेगा। उस वक्त फैसला किया मार्च १९६४ में। उसके बाद में हमने सिर्फ दो बार फैसले किये। उनके अन्दर परिवर्तन, जहां तक बाहर एक्सपोर्ट और बाहर से इम्पोर्ट करने का सम्बन्ध है, वह किये एक दफा तो मेरे ख्याल में १८...

श्री भैरोंसिंह : १८ अप्रैल !

श्री नाथूराम मिर्धा : १८ अप्रैल का है, एक फैसला उस समय किया जिसमें कहा कि राजस्थान के बाहर कोर्स ग्रेन नहीं जायगा। वह इसलिए किया कि हमारे यहां परिस्थिति काफी बिगड़ रही थी। भारत सरकार से जितने गेहूं के मिलने की आशा करके चल रहे थे, वह नहीं मिल रहा था। उस समय गेहूं की आवश्यकता थी और अकाल की परिस्थिति बनी हुई थी, उस समय हमारे यहां से कोर्स ग्रेन बाहर चला जाय और जो गेहूं हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिले तो मजबूर होकर कलैक्टर्स ने आज्ञायें जारी कीं अपने अपने जिलों के अन्दर। उन्होंने देखा कि हमारे यहां अकाल की स्थिति हो जायगी तो राज्य सरकार और ग्रेन देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना निर्णय लिया और कुछ किया। उसके बाद भारत सरकार से बात हुई, देश के लोग मिले और उन्होंने कहा, इस तरह रोक लगाना ठीक नहीं है। तब भारत सरकार ने कहा कि हम गेहूं ज्यादा देंगे, इस स्थिति को ठीक करो। इसलिए उस रोक को हटाना पड़ा और उस फैसले के सिवाय दूसरा फैसला बदला नहीं। इसके बाद में खास तौर से चने के फैसले को बदला तो उसकी भूमिका तो सबको मालूम ही है। बीज के वक्त में चना ९० रुपया तक पहुंच गया था और लोगों ने कहा कि चना नहीं निकालेंगे तो आगे की फसल तक वह सड़ जायगा ओर हम मर जायेंगे। इसलिए हमने भारत सरकार से कहा कि आधा हम रखेंगे और आधा दूसरी राज्य सरकारों को जितना दे सकेंगे उतना देंगे और शहरों में वितरण की दृष्टि से बांट देंगे। बीज के समय, जैसा कि मैंने बयान किया था...

श्री भैरोंसिंह : जिस समय चना ९० के भाव मिल रहा था उस समय एक्सपोर्ट हो रहा था और बीज के समय हमारा एक्सपोर्ट किस सीमा तक पहुंच गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हमारे हाथ की बात नहीं है। जिस पॉइन्ट को जिस ट्रेन्ड को रखवाने की कोशिश कर रहे थे, जो हम रखवाना चाहते थे भारत सरकार ने उसे देर से एग्री किया। उसे देरी हुई, यह स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रयत्न शुरू से चल रहा था। चने का डिसिज़न इसलिए लिया कि एक तरफ तो देश के अन्दर तीन रुपये के भाव से लोग चना खरीद कर खायें, चने की दाल खायें और दूसरी तरफ राजस्थान में तीन, चार लाख क्विन्टल चना अवेलेबल हो। तो हमने दूसरे राज्यों को दस हजार टन चना दिया है गुजरात को कोर्स ग्रेन दिया है। वैसे भी राजस्थान का कोर्स ग्रेन गुजरात को जाता रहा है और राजस्थान को कोर्स ग्रेन का प्रदेश मान

(श्री नाथूराम मिर्धा ।)

लिया है हमने। इस साल अच्छा प्रोडक्शन ईयर है। मैं यह सूचना सदन को देना चाहता हूं कि वह स्थिति हमारे कुछ जिलों में आ रही है, जिसमें जो किसानों के लिए मिनिमम प्राइस मुकर्रर की है, उसके नीचे की प्राइस जाय; जैसा जालौर और बाड़मेर के इलाके में हो रहा है। इसलिए हमने वहां पर खरीदने की उचित व्यवस्था कर दी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की कोर्स ग्रेन प्राइस के अन्दर आने वाले कुछ दिनों से गिरावट का ट्रेन्ड है, उससे हमने किसानों को बचा लिया है, नोर्मल मार्केट की दृष्टि से और जो राजस्थान में कोर्स ग्रेन सरप्लस है उससे हम देश के दूसरे राज्यों की मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मूंगफली के तेल और तेल के ऊपर उन्होंने रोक लगाई है, उसके लिए क्या कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई राज्य निश्चित नीति के बाद गलती करता है तो एक दुर्भावना से हम कदम उठायें, यह उचित नहीं है। हमारे देश की नीति तय हो चुकी है कि ऑइल सीड और ओइल के मूवमेंट में और खास तौर से पल्सेज और पल्सेज के मूवमेंट में किसी प्रकार देश के अन्दर इधर उधर जाने आने में पाबन्दियां नहीं हों। अगर गुजरात इस प्रकार की गलती करता है तो हमने भारत सरकार को लिखा है और चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक तरफ उनके यहां कोर्स ग्रेन की कमी हो तो हम उनको दें और दूसरी तरफ वह इस तरह रोक लगायें, यह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में चाहे जितनी शक्कर मिल सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : शक्कर की बात आपने उठा दी। शक्कर गुजरात को ज्यादा मिलती है, उनका कोटा ज्यादा है। इस बात को मैं सदन में समझा चुका हूं और उसी बात को मैं बार बार कहूं तो सदन का समय जाता है। इसलिए एक बात को दुबारा कहलवायें तो उससे लाभ नहीं होगा। मैं कह चुका हूं कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब का कोटा तय किया गया कि कितने टन कोटा दिया जाय उस उक्त गुजरात का कन्जम्प्शन वेशी मानकर, ऊंचा मान कर उनको ज्यादा कोटा मिल गया। राजस्थान का पहला कोटा १९६१ का था, उस समय कोटा मुकर्रर हुआ ९ हजार टन लेकिन हमारे यहां के व्यापारियों ने किसी महीने में पांच, पौने पांच हजार टन से ज्यादा नहीं लिया। इसलिए पांच के बजाय छः हजार कर दिया। उनका तेरह-चौदह हजार टन का कोटा हो गया। जो फिक्सेशन का बेसिस था वह कन्जम्प्शन बेसिस दूसरे प्रान्तों का ऊंचा था इसलिए ऊंचा फिक्स हो गया। इस स्थिति में हम दुबारा गये और हमने फिर कहा, तब यह माल ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा, छः हजार नहीं तो सात हजार टन ले लो। लेकिन अब चीनी का उत्पादन काफी अच्छा है, देश में करीब ३० लाख टन पैदा होगी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और इस साल एक्सपोर्ट में भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कमी करने की बात कह रहे थे, तब हमें कोटा पिछले साल से ज्यादा मिलेगा और राजस्थान का कोटा बढ़ेगा और चीनी खाने वालों को सहूलियत हो सकेगी, उनको भी ज्यादा चीनी मिलेगी। यह बीच में बात आई वह मैंने कह दी.......

श्री दलपतसिंह (आबू) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, बोर्डर एरिया में दस मील के रेडियस में बन्द कर दिया था !

श्री नाथूराम मिर्धा : दस मील के रेडियस में अभी भी बन्द है। वह इसलिए किया था कि हमारे यहां स्मगलिंग की व्यवस्थायें लोगों ने जमा ली थीं, ऐसी मंडियों में जहां पर जिन चीजों की खपत नहीं होती है वहां काफी खपत होने लगी थी। अलवर में मक्का खाई नहीं जाती लेकिन वहां की मंडियों में जाकर हजारों मन मक्का इकट्ठी हो गई। जहां पर जौ की खपत नहीं होती थी वहां जौ हजारों मन इकट्ठा हो गया। बोर्डर एरिया के बारे में कोर्स ग्रेन के बारे में स्पष्टीकरण आ चुका है और ऐसी व्यवस्था कर दी है, जो राजस्थान का सरप्लस है उसको और लोग खरीद सकें......

श्री दलपतसिंह : आबू रोड की ऐसी स्थिति है, वहां की मण्डी में चालीस पचास.......

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी चिट्ठी आने पर इस बात की माकूल व्यवस्था कर दी गई है।

श्री दलपतसिंह : मेरी चिट्ठी आने के बाद ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके बोर्डर एरिया में मंडी में अनाज आये तो उस पर रोक-टोक नहीं कर सकें और कानून के अनुसार लोग हैड लोड पर बीस सेर ले जायं तो उनको तङ्ग नहीं किया जाय। इस बात का फैसला बहुत केयरफुलनेस से किया है।

श्री दलपतसिंह : आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कह दूं कि सांचोर की मंडी पचास मील है और आबू रेडियस में आता है तो धान लेकर कैसे आयेंगे ? और दूसरे गांवों में रहते हैं वह बीस साल के रेडियस में आबू मण्डी से धान नहीं ले जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखें कि उन गाड़ियों की मुंह की दिशा किधर है अगर उनकी गाड़ियों की दिशा मंडियों की तरफ होगी तो ....

श्री दलपतसिंह : उनका मुंह तो गुजरात की तरफ होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी तकलीफ को समझ गया हूं। आप यही चाहते हैं कि मंडियों की तरफ किसान अनाज लाएं तो उनको पुलिस और दूसरे अधिकारी परेशान न करें। इसके लिये जितनी भी व्यव–

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्था हो सकेगी करूंगा और आपके किसान लोगों को हमारे अफसर और पुलिस के अधिकारी परेशान नहीं करेंगे. इसकी व्यवस्था कर दूंगा बशर्ते कि स्मगलिंग के बारे में आप किसी तरह का हाथ नहीं मिलावें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाथ मिलाने की भी आशंका है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं व्यापारियों की बात कहता हूं ।

श्री दलपतसिंह : मैंने आपके सेक्रेट्री को, दो महीने हो गये, पत्र लिखा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो महीने हुए आपने पत्र लिखा था वह मिल गया । मैंने उस पत्र को पढ़ लिया है । पांच-सात दिन में हमारे लोग उनकी गतिविधियों का पता लगा लेंगे । हमने हमारे पुलिस के अधिकारियों को और एन्फोर्समेंट अधिकारियों को हिदायत दे दी है कि गांवों की तरफ से मंडियों में माल आ रहा हो उसको आने दिया जाए और किसानों को १० मील में तंग नहीं किया जावे । अगर इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत मेरे पास आवेगी तो मैं उस पर एक्शन लूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं सब दे दूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न है । बाहर व्यापारी माल ले जाते थे उन पर किस प्रकार की कन्डीशन थी और क्या कुछ व्यापारियों को उन कन्डीशन्स से रिलेक्स किया गया है और किया गया है तो क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो प्रश्न उठाया उस पर मैं आ रहा हूं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि एक बार परिवर्तन किया और ग्राम पर एक बार और किया उसके अलावा नीति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । हालांकि कई लोगों को एतराज है कि हम लोग महंगा भी लाकर खा लेंगे । लेकिन सरकार ने कहा कि जो भाव ६४) का हमने निर्धारित किया है उसका उल्लंघन करेंगे उनको हम सजा देंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जो ६५ रु० २८ पैसे बेचे उसको आप क्या करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ढाबरिया साहब, उनको तो आप लाये नहीं । आप लावें । सजा देंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन आदमियों को एक ही दिन एक साथ पकड़ा । दो आदमियों को हथकड़ियां डाल दीं और एक को माफ कर दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ढाबरिया जी आप शिकायत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन व्यक्तियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। मगर उनमें से दो के हथकड़ियां डाली गईं और एक को माफ कर दिया गया। उसके हथ-कड़ियां नहीं डाली गईं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रश्न का घन्टा नहीं बनाया जावे तो उचित होगा। क्योंकि सदन का समय बहुत उपयोगी समय है, आपको और हमें सारे समय का सदुपयोग करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सब के प्रति न्याय हो। बहुत से माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।

मैं यह कह रहा था कि जैसा मैंने निवेदन किया कि स्मगलर्स की गाड़ियों को जरूर पकड़ रहे हैं। कुछ लोग बोर्डर पर अनाज इकट्ठा करके वहां से पार करते हैं। हमने इन्टेलिजेन्स की व्यवस्था लगाई और यह पता लगाया कि किस तरह से वहां से माल पार होता है और किस तरह से वहां पर माल इकट्ठा होता है और हमने कुछ लोगों के खिलाफ कदम भी उठाये और मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से राजस्थान में.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर में कोई कदम नहीं उठाया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में स्मगलर्स को रोकने के सिलसिले में और प्राइसेज ठीक चार्ज करने व बाहर जाने की जो व्यवस्था थी उसको रोकने के लिये काफी बड़ा कदम पुलिस और एन्फोर्समेंट के सभी लोगों ने मिलकर उठाया और इस समय तक १४८ केसेज अदालत में पेश किये गये है, समेरी ट्रायल के। उसमें करीब ८० को सजा हुई है और २२ आदमी छूटे हैं और बाकी जेर तजवीज हैं। प्रोसीक्युशन की संख्या ३३७ है। इसके साथ साथ दर्ज करने की संख्या भी मेरे पास थी।

खास कर एक सूचना मैं और देना चाहता हूं। फिर आपकी सूचना होगी तो और सख्तियां करने को तैयार हूं। इसलिये पहले से ही एलान कर देता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ये केसेज १४८ आपने दिये हैं, उसमें कितने धान के थे और कितने दूसरे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसके संबंध में अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री मोतीलाल चौधरी : उसमें धान के कितने हैं, पार्टीज सस्पेन्ड हुए हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अधिवेशन डेढ़ महीने तक चलेगा। आप प्रश्न पूछ लें, हम आपको सूचना दे देंगे। आप जैसा कहेंगे, करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये पीछे से चोट मार रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो यह कि आपने मिनिमम प्राइसेज तय किये हैं उससे लो low जाने की स्थिति में पर्चेजेज का

(श्री भैरोंसिंह)

क्या प्रबन्ध किया है और दूसरा यह कि राजस्थान में चना और जौ की निकासी का तरीका है उसके बारे में कितना बफर स्टॉक आपने जमा किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा आपने पूछा कि मिनिमम प्राइसेज़ से लो जाने की स्थिति में आपने कितना खरीदा है, तो उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अभी तक ८० या ६० क्विन्टल खरीद किया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इतना बड़ा स्टॉक खरीद कर रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह स्थिति सिवाय दो रोज के नहीं बनी । जैसा मैंने पहले कहा कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मैंने वहां पर देखा कि खरीदने वाले नहीं थे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तुरन्त वहां पर खरीदने की व्यवस्था करा दी । जहां तक आपने एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है कि जो एक्सपोर्ट चना और जौ होता है उसका २५ प्रतिशत यहां स्टॉक होता है उसमें ५० हजार क्विन्टल है जिसमें बाजरा मक्का, जौ आदि है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपने पर्चेजिंग ऑफिसर किनको मुकर्रर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलदार हो हैं ।

इसके अलावा रबी के बारे में जब तक कोई नये निर्णय समूचे देश की लेवल पर खाद्यान्नों के बारे में मंत्रियों की बैठक में न हो जावे, हमने आज तक जो व्यवस्था की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते । मैं समझता हूं कि कुछ इलाकों में जहां पर फसल बहुत अच्छी होने से बफर स्टॉक है वहां पर जो रेट हमने मुकर्रर की है उनसे भी कम कीमतें हो सकती हैं । और जब चने और गेहूं कि फसल हमारे सामने आवेगी और जो भाव हमने निर्धारित किये हैं उनसे नीचे जावेंगे तो हम उनको खरीदेंगे । बकाया जो कुछ बाहर जाने का सिलसिला है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, न प्राइसेज़ में परिवर्तन करना चाहते हैं । जो हमारी मौजूदा नीति है उसी पर हम जम कर चलना चाहते हैं ।

स्टेट ट्रेडिंग पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग पर राज्य को काम करना चाहिये । यह भी देश की नीति का प्रश्न है, चाहे तो हम सारे अनाजों का व्यापार कर लें, चाहे योजनाएं चला लें । क्योंकि सदन में बैठने वाले और देश के लोग जानते हैं कि विकास के काम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पॉवर की बढ़ोत्तरी के काम हम करना चाहते हैं, योजनाओं को हम चलाना चाहते हैं, इन पर हमें खर्चा करना पड़ेगा । योजनाओं पर इन विकास के कार्यों पर खर्च न करके, जो पैदा हो समूचा व्यापार में डाल कर पहले इस काम को करना चाहिये, कम पैसों

Page No 95

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर, मुनाफा न करके इस व्यवस्था को तो इस पर सारे देश को विचार करना होगा और फिर निर्णय करना होगा। मेरी राय में यह निर्णय लेना उपयुक्त नहीं है, न हमारे पास इतना धन ही है, न व्यवस्था है और न हम इसे कर ही सकते हैं। फिर भी जो कुछ रास्ते कारप्रोरेशन के रूप में हाथ में लेने की आवश्यकता है, उनको हाथ में लेने की कोशिश की है, चावल की फसल हाथ में ली है, फसल हाथ में ली है, गेहूं की फसल हाथ में लेना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं गेहूं के स्टॉक्स बनाने के बारे में निर्णय करना होगा तो इसको कोर्पोरेशन करेगी, राज्य सरकार किस तरह से करेगी, यह सारे देश के लेवल पर तय किया जायगा। कोर्पोरेशन का क्या योगदान स्टॉक्स बनाने के लिए होगा, उसी के अनुसार निर्णय होने पर हमारे यहां निर्णय लिये जायेंगे। इसलिए खाद्यान्नों के बारे में स्टेट ट्रेडिंग की बात करना उचित नहीं होगा, आज वह जरूरी भ नहीं है इसकी अभी आवश्यता भी नहीं है क्यों कि देश के साधनों का उपयोग दूसरे कामों में करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : राजस्थान सरकार ने जितना चना खरीदा, किस भाव से खरीदा, कितना खरीदा, दूसरे प्रदेशों को दिया है वह कितना और किस भाव से दिया है, यह जरा बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : ८ हजार टन गुजरात को दिया है, १० हजार टन देने की बात कही है, ५१, ५२ रुपया टन के हिसाब से, सॉरी, क्विन्टल के भाव से दिया है। ४२।। रुपया क्विन्टल के भाव से हमने खरीदा है।

श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) : दूसरी रियासतों में बफर स्टॉक्स कायम किये है, महाराष्ट्र ने किया है। तो क्या राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाली खरीफ की फसल के समय में बफर स्टॉक कायम किया जाय!

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि २५ परसेन्ट के बेसिस पर बफर स्टॉक बनाने का किया है। आने वाली फसल के लिये सारे देश के लेवल पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : निर्धारित दर से नीचे किसानों का धान न बिके इसके लिए इन्टीरियर में मंडियां खोलने का विचार है क्या सरकार का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १३२ मंडियां हमने खोली हैं। किस प्रकार इन्टीरियर में जाकर खरीदें, यह राज्य सरकार के सोचने का विषय होगा; इस पर निर्णय करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सोचता हूं जो कुछ आधार गिलाए मैंने राजस्थान के बारे में, और देश के बारे में, जिस मंजिल पर पहुंचने के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान खींचा, मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्य इन पर गंभीरता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से विचार करेंगे। इस सदन के कई माननीय सदस्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और बहुत से तथ्यों को बढ़ा–चढ़ा कर कहने की सोचते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो सिंचाई की बातें हों, जो सही तथ्य हों वही इस सदन में रखें; तो इस ओर बैठने वालों पर भी उनका असर हो। कई बार देखते हैं कि इस ओर से जवाब दे देने के बाद भी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। आपको अगर सन्तोष नहीं हो तो जो तथ्यपूर्ण बात हैं वह आप पूछें मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं, जो आवश्यक मुद्दे हैं वह आप जरूर पूछें क्योंकि समाज का वातावरण ठीक रखने की आवश्यकता है। गांवों में, शहरों में वह वातावरण ठीक रहेगा तो हम सही दिशा में प्रगति कर सकेंगे। पंचायतों के इलेक्शन के बारे में बहुत सी बातें कही गईं, सरकारी कर्मचारियों ने मदद की, वोट दिलाये, हमारे खेमे में बैठे और वोट उधर जा कर दिये। खाना हमारे यहां खाया, वोट उधर जाकर दिये। वोट किधर दिये, किधर नहीं दिये, यह तो होशियारी का सवाल है, यह तो वोटर्स की इन्टेलिजेंस पर निर्भर करता है कि खाना किधर खाया, बोट किधर दिया, सतर्कता हमें वरतनी है। सतर्कता हमने नहीं बरती तो खतरा खा सकते हैं।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन पंचायतों के इलेक्शन्स में कांग्रेस की काफी अच्छी जीत हुई है, दो तीन जिलों को, जिला परिषदों में और आम तौर से पंचायतों में और पंचायत समितियों में बहुत बड़ा परसेंटेज कांग्रेस को मिला है। पर इससे हम कोई बहुत इतरा जायं, यह हमारी कतई मंशा नहीं है। इन जीतों से, यह सही है कि हमें बल मिला है, सहायता जरूर मिली है कि देश के लोग सही नीतियों का प्रतिपादन करते हैं, इससे हौसला बढ़ता है। कांग्रेस में आपसी मतभेद से कई दफा कुछ परिणाम अच्छे नहीं आये, पिछले चुनावों के परिणाम अच्छे नहीं आये। तो हम चाहते हैं कि आयन्दा सालों में अच्छे परिणाम आयें और समाजवाद की मंजिल पर पहुंचने के लिये जिसके लिये कि बहुत वर्षों की आवश्यकता है, हम चाहते है वह समय कम करें। उसमें सदन के उधर बैठने वाले लोग अपनी आलोचनाएं सही और सीमित रखें, वाजिब बात पर जोर देकर कहें और गलत बात को कभी नहीं कहें। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सैकड़ों बीघा जमीन ले ली। अरे! हमारे बाप-दादों ने जमीनें रखीं, आप भी जमीन रखें ; अंगूर लगायें, कुछ करें। तो उनका क्या यह मतलब है कि हम केवल भाषण ही देते रहें, काम करें नहीं और हमारी हालत खराब की खराब रहे। अगर ऐसी उनकी कल्पना है तो उनको मुबारिकबाद। हमको तो घरों में भी, खेतों में भी और समाज में भी काम करना है। इस भूमिका में सदन के माननीय सदस्य काम करेंगे तो....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने अंगूर लगाये हैं, उनके भाव क्या हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): अंगूर खट्टे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो अंगूर लगेंगे, दो-तीन वर्ष में लगेंगे तो आप भी आइये; अंगूर खाइये, आपका भी हिस्सा है।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा हिस्सा कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भी एक गुच्छा, दो गुच्छे खायेंगे।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हम इस वातावरण से ऊंचे उठें। मैं इस बात को सही मानता हूं कि आलोचना होनी चाहिए, पर सही आलोचना होनी चाहिए। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम सब माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बताया उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय ने अच्छा चित्र खींचा है, उसकी मंजिल नजदीक आयेगी जिसके भागीदार इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य दोनों तरफ के भागीदार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द डागा।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजनैतिक आजादी प्राप्त करने के बाद हमारा लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक दिशा में बढ़ने का था। हमने देश के लोगों को कहा था कि हम इस मुल्क से गरीबी को दूर कर के बाहर फेंक देंगे। हमने यह भी कहा था कि हमारे देश के लोगों को चाहे वे गरीब तबके के हों चाहे अमीर तबके के हों, उनको रहने को मकान देंगे, खाने को रोटी देंगे, पहिनने को कपड़ा देंगे। आजादी के बाद इन १७ सालों में बहुत उतार-चढ़ाव आये, हम आगे बढ़े, हमारा नेतृत्व एक सफल नेता के हाथ में था क्योंकि वह नेता आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है।

लेकिन उसके नेतृत्व में सारा देश आगे बढ़ा। एक प्रोग्राम पंचवर्षीय योजना का लोगों को दिया, जिसके जरिए वह चाहते थे कि हमारे इन योजनाओं को राजस्थान के ६ लाख गांवों में पहुंचाया जाय। सबसे पहले कुछ गांव चुने गए थे। विकास के जरिए कि हम किस तरह गांवों की उन्नति को पूरा करें, यह इरादा सारे राज्य के नेताओं का था। दो पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के जरिए किस तरह गांवों का उत्थान हुआ, यह हम लोगों और सब लोगों के दिमाग में था। पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठे और उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जो भी प्रोग्राम बना वह बहुत सुन्दर है लेकिन उस प्रोग्राम पर हम नहीं चल पाए। क्योंकि जितनी मदद हमारी सरकार को उन पंचायत समितियों से मिलती है उतनी मदद वह खुद उसको पूरा करने में नहीं लगाते हैं। जहां हमने एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक पंचायत को २० हजार रुपए दिये तो २० हजार जब तक गांव वालों ने नहीं लगाए तब तक वह योजना पूरी होने वाली नहीं है। तो

(श्री बालचन्द डागा)

आज जितना योजनाओं पर अमल करना चाहते हैं उतना उनमें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि आज वे स्वार्थ में फसे हुए हैं आज किशनगढ़ पंचायत समिति का ही उदाहरण लीजिए । जहां विकास का काम होना चाहिए था, जितना पैसा वहां मिला था उतना काम नहीं हुआ । १६५६ के तमाम के तमाम काम अधूरे पड़े हुए हैं, स्कूल की छत गायब हैं, कहीं सड़क अधूरी पड़ी है, इसलिए पूरी नहीं हुई कि पंचायत समितियों को जितना पैसा दिया जाय उतना गांव वालों से ले लिया जाता है और उसमें ओवरसीयर और प्रधान १०-१५ परसेंट खाना चाहते हैं । इसलिए पूरा काम नहीं होता है । आज की स्थिति देखी जाय । हमने इन्क्वायरी भी करवानी चाही हैं लेकिन यहां से दामोदर व्यास का फोन कलेक्टर के पास जाता है कि इस फाइल को रोक दिया जाय, तो वह रुक जाता है इसलिए हमारे काम करने के तरीकों में ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है ।

पंचायत समितियों के जरिए गांव का विकास करना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । एक बी ०डी० ओ० ५००) रु० पाने वाला मोटरों में बैठकर गांव का विकास नहीं कर सकता है । जितने सरपंच आते हैं वे स्वार्थ के वशीभूत चुन कर आते हैं कि ५०-५० हजार तकावी के नाम एक सरपंच ले गया और मांग के खाते में जमा कर दिए । इस तरह के तरीकों से गांव वालों का उपकार नहीं होता जैसा हमारी सरकार का इरादा है ।

जैसे उद्योग का मामला हैं । हमारे किशनगढ़ में एक बड़ी मिल थी, वह मिल राजनीति का शिकार हुई और बंद हुई । एक मिल बंद हुई और दूसरी चालू हुई । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो यह मिल बंद पड़ी हुई है १०-१२ साल से वह चालू होनी चाहिए जिससे मजदूरों को रोजगार मिले । वहां के मिल मजदूरों को मजदूरी आज तक आप नहीं दिला पाए हैं, उनका प्रोवीडेंट फंड, ग्रैचुइटी का पैसा भी तक्सीम नहीं हुआ है, वह पैसा जल्दी से जल्दी उनको मिले ।

सिंचाई के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी अजमेर स्टेट में एक कूंटरा बांध था उसमें ५-६ लाख लगे लेकिन उससे उस गांव को कोई फायदा नहीं हुआ ।

गांव में सिंचाई के साधन नहीं, रूपनगढ़ का इलाका सारा सूखा रह गया । इस बांध के लिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस एरिया में पानी का इंतजाम किया जाय ताकि लोगों को पीने का पानी मिले ।

तीन साल में लगातार संबंधित मंत्री महोदय से कहता आया हूं कि हमारे अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है और मौके पर हमने प्रभाजी को लेकर बताया था कि तमाम बेड्स खाली पड़े हैं, डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, वहां रमी खेलने में लगे रहते हैं । दवाइयां सब बाजार से लाते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि चिकित्सा की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हमारा अधिकांश बजट शिक्षा पर खर्च होता है और मौजूदा शिक्षा जन-जीवन को

(श्री बालचन्द डागा)

खोखला बना रही है। आज मैट्रिक पास लड़का भी कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए। बी०ए०, एम०ए० पास वालों के लिए भी हम नौकरी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। और जिन पांच परसेंट के लिए नौकरी का इंतजाम हो जाता है तो वे सिफारिश से लिए जाते हैं। जब तक हम इसका हल ढूंढ नहीं निकालेंगे तब तक हमारे सामने बेकारों का फोर्स खड़ा हो जायगा। आज स्कूल की शिक्षा में श्रम नहीं होता है, देश श्रम मांगता है, पांच सौ पाने वाला लेक्चरार एक घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, एक घंटे से ज्यादा दिमाग नहीं खर्च कर सकता। उस शिक्षा के देने से क्या लाभ, जिससे बेकारों का फोर्स खड़ा हो जाय ? इसलिए कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए।

परिवार नियोजन के बारे में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रश्न को लेकर यहां कुछ कहा गया है। मैं भी कहना चाहता हूं क यह बात सही है, हमारी बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए हमको कदम उठाने चाहिऐं। मनुष्य स्त्री से क्रूरता का व्यवहार करता है और बच्चे पैदा करता जाता है। जैसे पाकिस्तान बन गया उसी तरह से यहां भी नारीस्तान बन जायगा, तो फिर पुरुषों के लिए रसोई की मुसीबत आ जायगी। इसलिए परिवार नियोजन की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाय।

श्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ दिन पहले पीतल की फैक्टरी में भूख हड़ताल का आन्दोलन चला था, उसमें यह शिकायत थी कि जितना कोटा आता है आइरन और स्टील का उसका गलत ढंग से वितरण होता है और तमाम कोटा ब्लैक में बिक जाता है। इसलिए मैंने पहले भी चन्दनमलजी से बात की थी, उन्होंने कहा कि यह कोटा तो सेंटर से मिलता रहता है, हम इंतजाम नहीं कर सकते। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जो पांच रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी उसका पालन भी नहीं हुआ है।

(४.०० म. प.)

सहकारिता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से कैसी सहकारिता हमारे यहां चल रही है। मजदूर वस्त्र उत्पादन समिति का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समिति को १,८० हजार रुपया मजदूर कोलोनी बनाने के लिए मिला था। उसका आज तक असेसमेन्ट नहीं हुआ और वहां पर कुल करीब ६० हजार रुपया लगा और बाकी का रुपया जो समिति के व्यवस्थापक थे और काम करते थे वे हड़प गये। इस प्रकार से सहकारिता बदनाम होती है। इसी प्रकार एक गोटा फैक्टरी केसरीचन्द जी चौधरी ने लगायी। वे चार टन तांबे का कोटा लाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोई गोटा फैक्टरी नहीं लगी है और न जाने उस चार टन तांबे का क्या हुआ ? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

(घन्टी)

मुझे आज ही टाइम मिला है। दो मिनट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और ले लीजिये।

श्री बालचन्द डागा : इस प्रकार सहकारिता के सम्बन्ध में सरकार को सतर्क रह कर जांच करनी चाहिये। जिससे सहकारिता बदनाम न हो।

तमाम छोटे २ जंगल है, कोई १००-१५० बीघा के हैं, उनको खोल देना चाहिये ताकि मवेशी उनमें जा सकें। पांच छः लाख रुपया इन पर सरकार का लगता है, लेकिन आप देखिये कि किशनगढ़ में भी लगा है, वहां पर कोई दरखत नहीं है। आप इन्क्वायरी करके इसकी जांच करके देखिये।

सेल्स टैक्स के बारे में भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेल्स टैक्स का महकमा डकैती करता है, व्यापारियों के पास जाकर कागजों की छीना-झपटी करता है। जिस तरह से डकैत आते हैं, उसी प्रकार पुलिस फोर्स के साथ ये लोग आते हैं और दूकानों पर जाकर लूट-खसोट मचाते हैं। फिर वे कहते है कि केस कम्पाउन्ड करा लीजिये। व्यापारी नहीं करते हैं, तो वे सामान उठा कर ले जाते हैं। व्यापारी फिर क्या करते हैं कि दो-चार सौ रुपया देकर केस कम्पाउन्ड करा लेते हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और साथ ही साथ सरकार को आगाह भी करता हूं कि भारत की जो नयी तस्वीर बनने जा रही है उसमें आप और हम सब मिलकर मदद करें। तरीका सच्चाई और ईमानदारी का नहीं है। चतुराई और शुद्धता नहीं है, कार्यक्षमता और निपुणता नहीं है। तो देश के लिए ऐसा कमजोर संगठन बना डालेंगे जो हमारी आजादी को पुनः गुलामी में परिणत कर देगा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की जो तस्वीर बन रही है उसमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ मिल कर उसमें सहयोग दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय योजना मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (योजनामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन के अन्दर मुख्तलिफ दलों के मुख्तलिफ नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से विचार रखे हैं। श्रीमन् राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान में हमारे देश की स्थिति को और खास तौर से पं० जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद में हिन्दुस्तान के चुने हुए लोगों के कंधों पर जो जवाबदारी आयी है उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण में यह भी बताया गया कि हमारा लक्ष्य और ध्येय हल्के-हल्के समाजवादी समाज की ओर बढ़ने का है और इन वर्षों में लगातार यह राज्य सरकार इस बात का निरन्तर प्रयत्न करती रही है कि हमारे देश के अन्दर एक नये समाज की व्यवस्था कायम हो। हो सकता है कि उसको लेकर विरोधी दलों में बैठने वाली मुख्तलिफ पार्टियों के अलग अलग विचार हों, लेकिन इस देश के लोगों ने और

(श्री मथुरादास माथुर)

राजस्थान की सरकार और शासनारूढ़ दल ने समाजवादी समाज व्यवस्था को कायम करने का जो फैसला किया है और जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता पं० जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में उसका जो फैसला किया है उस फैसले को हम पूरा करके छोड़ेंगे। इसी को लेकर के अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ें और देखें। व्यक्तिगत किसी आदमी पर झूंठे आरोप लगाकर राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव को, यह कहें कि पास न किया जाय तो इतिहास में यह बात उतर जायगी और इतिहास यह कहेगा कि जमाने की रफ्तार के साथ कदम बढ़ाकर चलना चाहिये था वह कदम नहीं बढ़े। विरोधी दल के नेता से बड़ी उम्मीद थी। जब वे भाषण देते हैं तो ट्रेज़री बेन्चेज़ का हर एक आदमी यह कोशिश करता है कि वह सदन में मौजूद रहे। मुझे इस बात का खेद है कि विरोधी दल के नेता जो कुछ बातें उनके द्वारा कही गई हैं उनका प्रत्युत्तर सुनने के लिए आज यहां सदन में मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि विरोधी दल के नेता इन पंचायत चुनावों के बाद में जो शिकस्त सा अपने को समझते हैं और शिकस्त खाकर जो लौटे हैं शायद संजीदगी से भाषण देंगे। उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में यह कहा कि पंचायत राज के चुनावों से राज्य सरकार का बड़ा दखल रहा है और उन्होंने अपने भाषण में, शुरूआत में इस बात को दोहराया है कि भ्रष्टाचार बहुत जोर से इस पंचायत चुनाव में चला है। मैं श्रीमन् अदब से निवेदन करना चाहता हूं और उनकी पार्टी के सदस्यों को जो यहां बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचायें कि ये अपना मुंह दर्पण में देखें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह अपना मुंह दर्पण में देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जावेगा कि यह तो वक्त की बात है कि पंचायत चुनावों में स्वतन्त्र पार्टी का कोई उम्मीदवार चुन कर नहीं आया। उसका उन्हें भी खेद है, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि पंचायत चुनावों में राज्य सरकार की तरफ से हमने यह कोशिश की कि इन चुनावों को अच्छी तरह से चलाया जाय और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ७३२७ पंचायतों के चुनाव हुए, २३२ पंचायत समितियों और २६ जिला परिषदों के चुनाव हुये और ६६ लाख मतदाताओं ने, जिन्हें मतदान का अधिकार था, उसमें से ८० प्रतिशत लोगों ने, वोट डाले। इसके साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि ११३६८ पोलिंग बूथ मुकर्रर किये गये। ४६५१ चुनाव कराने की पार्टीज़ मुकर्रर हुई और २६६० रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए। इतने बड़े चुनाव किसी प्रजातन्त्र में किसी देश में आज तक नहीं हुए हैं जो कि राजस्थान में हमने इन दो महीनों में कराये हैं। इतने बड़े चुनावों

(हियर हियर)

में कुल ७ स्टेज पर ये चुनाव कराये गये। सबसे पहले चुनाव के अन्दर गांवों में पंच और सरपंच के चुनाव हुए। उसके बाद में पंचायत समितियों में कोऑप्शन हुए, उसके

Page No 102

(श्री मथुरादास माथुर)

बाद उप-सरपंच का चुनाव हुआ, उसके बाद पंचायत समितियों का कोऑप्शन हुआ, उसके बाद प्रधान के चुनाव हुए, जिला परिषदों के कोऑप्शन हुए और अन्त में जिला प्रमुख के चुनाव हुए। सात स्टेजेज़ थीं जिनमें चुनाव का दौर गुजरा। यह कहा गया कि चुनावों में समय लम्बा लगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बात की कोशिश की कि कानून जो सदन ने बनाया है उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाय, यह राज्य सरकार ने कोशिश की।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में कुल ५८ दिन लगे। जो चुनाव तीन साल पहले हुए थे उनमें ८२ दिन लगे। बावजूद इस बात के कि उस समय राज्य के विभाग ने कोई कोऑप्शन नहीं करवाये, फिर भी ८२ दिन लगे। और अब के कोऑप्शन नहीं करवाये फिर भी ५८ दिन ही लगे।

श्री भैरोंसिंह : इन ८२ दिनों में स्टेंडिंग कमेटीज के इलेक्शन भी शामिल हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब की बार ५८ दिन लगे हैं पंचायतों के चुनावों में, जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख सब के चुनाव शामिल हैं। यह हो सकता है अगर सदन द्वारा पास किये हुए कानून में तब्दीली करा दें, कोऑप्शन की प्रथा को हटा दें, तो वे दिन भी कम हो सकते हैं। सदन ने जो कानून पास किया था उन "बाइ लॉज" पर नजर रखते हुए हम ५८ दिन में चुनाव करा सके हैं। इन चुनावों के अन्दर तीन चार जगह के अलावा तारीख बदलने की नौबत नहीं आयी इस तरह से ७३८७ पंचायतों के चुनाव पूरे हुए। विरोधी दल के माननीय सदस्य चाहे इस बात को स्वीकार करें या न करें लेकिन जब वे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से हुए हैं। राजस्थान सरकार ने जो चुनाव कराये हैं विरोधी दल तारीफ करें या न करें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यह सही है कि इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। इस चुनाव के अन्दर एक ऐतिहासिक जो बात हुई है वह पहले किसी चुनाव में नहीं हुई। सबसे पहले वोटर्स लिस्ट का रिवीज़न करवाया, उसके बाद में यह भी कहा जिसको एतराज करना हो वे बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, मेसेन्जर के द्वारा भी एतराज लिख कर भिजवा सकते हैं। दो करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में, जिसमें ९६ लाख मतदाता भाग लेने वाले हों उसकी सूची बनायी जाय; यह इस बात का सूचक है कि हम प्रजातन्त्र में कितना विश्वास रखते हैं प्रजातन्त्र की हमारी जड़ें कितनी गहरी जा रही हैं, लोगों में कितनी आस्था पैदा हो रही है। इस पर भी हमारे विरोधी दल के नेता जिनका एक शब्द पेटेन्ट है अधिनायकवाद-वे हर भाषण में इस शब्द को दो-चार बार जरूर प्रयोग करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में अधिनायकवाद की कतई गुंजाइश नहीं है। न कहीं अधिनायकवाद है, न किसी सरकारी अफसर ने इसमें दखल किया है, न कहीं भ्रष्टाचार हुआ, न "फेवरेटिज़्म"

(श्री मथुरादास माथुर)

और न नेपोटिज्म की शिकायत है । इसके अलावा तीसरी बात जो हमने की थी वह यह कि पहले जो चुनाव हुए उसमें एक वार्ड के लिए दो घंटे मुकर्रर करते थे । उसी समय में वोट देने वाले दें लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया गया । एक वार्ड के लिये पूरा दिन का समय दिया गया इसलिये परसेन्टेज ऑफ वोट्स भी ९५ से ९९ परसेन्ट तक रहा । यह सुन कर आपको खुशी होनी चाहिये, राजस्थान की आस्था जनतंत्र में बढ़ती जा रही है, सदन भी प्रजातन्त्रीय आधार पर चुना हुआ है और उसी प्रजातन्त्र के आधार पर हम सब आगे बढ़ रहे है ।

बैलट पेपर जो बनाये गये हैं वे भी असेम्बली के बेलट पेपर के समान बनाये गये, कोई भी कसर नहीं रखी गई जिससे किसी को शिकायत की गुंजाइश मिले । चुनावों में सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात की गई हो, जिससे एक दल को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो ऐसी कोई गुंजाइश नही रखी गई । वोट देना तो जनता के हाथ में है वह मेरे अपने हाथ में नहीं इससे कोई पार्टी पिट कर आती है तो उसका दोष मुझ पर नहीं डाला जा सकता । हम भी कांग्रेस में हैं और सरकार में हैं, मिनिस्टर में और पार्टी के सदस्य में फर्क नहीं है । किसी सरकारी अधिकारी ने चुनावों में दखल किया हो, ऐसी एक भी शिकायत आयगी तो उसकी पूरी जांच करूंगा और जैसा कि असेम्बली, धारा सभा पार्लियामेंट के चुनावो में दखल देने पर सरकारी अधिकारी को सजा है वही सजा इसमें भी लागू होती है । किसी भी सरकारी कर्मचारी ने बेईमानी करप्शन किया हो तो उसके कर्मचारी लिये प्रोसीक्यूशन हो सकता है । यह कानून हमने इसमें भी लागू किया है । कोई भी ऐसी चीज आयगी तो हम सख्त से सख्त कदम उठाने में नहीं हिचकिचायेंगे । हमारे पास जो बेलट पेपर रिजेक्शन की कुल शिकायतें आयीं उनकी संख्या केवल छः है । जो भी इलेक्शन पिटीशन के अन्दर चल रही है इसलिये कोई कदम मैं उठा नहीं सकता । और दूसरी तरह की शिकायतें जो सब आयीं उनकी संख्या ३४ है जो इतने बड़े चुनाव को देखते हुए आधा और पाव परसेन्ट भी नहीं पड़ता....

श्री भैरोंसिंह : उसके लिये आपने रोडवेज की शिकायतों की तरह लिफाफा नहीं भेजा ।

श्री मथुरादास माथुर : कुल ३४ शिकायतें आयी । जहां ७३८७ पंचायतों के चुनाव हों, २३२ पंचायत समितियों और २६ जिला परिषदों के चुनाव हों उसके अन्दर भी सात स्टेजेज में चुनाव हों, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें सिर्फ ३४ शिकायतें आना उसके लिये मैं जनता को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उन अधिकारियों को भी धन्यवाद दिये वगैर नहीं रहूंगा जिनकी देखरेख में या जिन्होंने ये चुनाव कराये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, चित्तौड़ के बारे में जो स्थिति सदन के सामने रखी

(श्री मथुरादास माथुर)

गई उसके बारे में जांच करवाने के लिये था, लेकिन पता लगा उसके लिये पिटीशन हो चुकी है। उनका कहना जो था एक वार्ड के लिये ठीक नहीं था। तीन वार्ड के अन्दर जो बात कही गई, वह पोइन्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने एजीटेट हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते । जज जो बात कहेंगे यदि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती बतायेंगे तो राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही उसके लिये करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोई राज्य सरकार का अधिकारी गलती करे और उसके लिये हम सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं तो दूसरी तरफ कोई अच्छा काम करे तो उसके मुंह से अच्छे अलफाज भी निकाले जाने चाहिये। चुनाव में यदि कोई पार्टी हार जाय तो उसके लिये रिटर्निंग ऑफिसर को गालियां नहीं दे सकते। यह तो वोटर्स के हाथ में है। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर सकता है और यह गरीब इलेक्शन मिनिस्टर उसके लिये क्या कर सकता है। कराने वाले तो बड़े लांठे आदमी होते हैं। किसी ने बकरे खिलाये होंगे तो किसी ने भैंसे खिलायें होंगे, ये तो खाने और खिलाने वाले जानते होंगे। इसके लिये तो बाहर बैठकर भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग मिल कर कोड ऑफ कन्डक्ट बनायें तो मेरी पार्टी इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसके लिए राज्य को उपालम्भ नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां जहां अच्छा काम होता है उसके लिए तारीफ की जा सकती है। तो सरकारी अधिकारियों का दिल बढ़ेगा उनकी प्रजातन्त्र में आस्था बढ़ेगी और इस तरह से यह प्रजातन्त्र आगे चलने में सहायक होगा। मैं चुनावों के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। इससे ज्यादा लम्बा जाना नहीं चाहता, क्योंकि सभी माननीय सदस्य इस चुनाव में होकर आये हैं। कोई पिटकर आया है, तो कोई जीत कर आया है, कोई घायल होकर आया है इसलिए वे सब इस बारे में जानते हैं।

अब मैं दूसरी बातों की ओर आता हूं। देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने लिग्नाइट के बारे में कहा। मैं माननीय सदस्या की बहुत तारीफ करूंगा कि जिस लिग्नाइट कोयले के अन्दर किसी ने दिलचस्पी नहीं बताई इन्होंने दिलचस्पी ली है। इस बात की खुशी है जो सुझाव उन्होंने राज्य सरकार को दिये हैं उन सुझावों से हम सहमत हैं। राज्य सरकार की इच्छा है कि लिग्नाइट के आधार पर हम पावर प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं इसलिये हमने घोष कमेटी की रिपोर्ट को और आगे एक्जामिन करने के लिये प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को राय दी है। इस पर उन्होंने "रसियन एक्सपर्ट्स" को यहां बुलाया है और वे बीस पचीस दिनों से इसके लिए काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि माइनिंग सस्ता पड़ता है या नहीं। पॉवर प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा तो हम १०० मेघावाट का बिजलीघर कायम करने की योजना रखते हैं। मैं आशा करता हूं इसकी रिपोर्ट १५ मार्च तक मेरे पास आ जायगी,

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं सरकार इस बारे में जागरूक है, एक्सपर्ट्स अभी काम कर रहे हैं अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग के जरिये ८०-टन कोयला निकलता है।

ज्यादा हम इसलिए नहीं निकालना चाहते कि उसकी यूटीलिटी इस समय हमारे सामने नहीं है। फिर भी प्रिज़र्व करना चाहते हैं ताकि पावर हाउस बने तो वह कोयला काम आ सके। मैं समझता हूं इससे सदन के माननीय सभी सदस्यों को सन्तोष होगा। राज्य सरकार इस लिग्नाइट के ओपरेशन के लिये, प्रोस्पेक्टिंग के लिये, माइनिंग के लिए और उसके आधार पर पॉवर प्रोडक्शन के लिये अगर नहीं तो पेट्रो-कैमिकल हो सके तो उसके लिये रिपोर्ट आने पर विचार करेगी।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न उठाया था, इसलिये मेरा खयाल है, वे यहां हैं नहीं, पर मेरे इस उत्तर से वे भी सन्तुष्ट होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न को लेकर इस सदन में अमूमन बहुत चर्चा होती है और यह प्रश्न है राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम।

इस प्रश्न को लेकर जयपुर से आने वाले माननीय मुखियाजी ने जो सदन में बयान दिया था, मेरा ख्याल है, मैं उन मुखियाजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च का जिक्र करते हुए उन्होंने जो प्रोपोज किया....

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट देखी है मैंने उनकी।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट वह मुझे नहीं मिल रही है। पर कैपिटा, उन्होंने ६०-६१ में २६७.३ पर कैपिटा इन्कम बताई है और बिहार की २२०.६६ है उससे ऊपर राजस्थान है, यह जिक्र भाषण में किया। मैं इसके लिये निवेदन कर दूं कि पर-कैपिटा के मामले में एक दूसरी स्टेटों से मुकाबला करना ठीक नहीं रहेगा। इस पर-कपिटा का कॅल्कुलेशन करने के लिये मुख्तलिफ स्टेटों में मुख्तलिफ तरीके हैं।

(कुछ व्यवधान उपस्थित होने पर घंटी)

(अल्प विराम के अनन्तर)

यह तो कुछ ऑटोमैटिक करेंट चलता है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें मुख्तलिफ स्टेटों के मुख्तलिफ बेसिक ईयर्स हैं, मुख्तलिफ बेस हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग हैं। अन्डर डेवलप्ड मुल्कों के कैल्कुलेट करने के तरीके अलग हैं और डेवलप्ड कन्ट्रीज़ के अलग हैं। अपने यहां हिन्दुस्तान में भी भिन्न भिन्न स्टेटों में अलग अलग मैथडोलोजी हैं। अलग अलग प्राइस स्ट्रक्चर है। कोई होलसेल प्राइस

(श्री मथुरादास माथुर)

लेते हैं, कोई रिटेल प्राइस लेते हैं। कम्पोनेन्ट फैक्टर्स हैं। मध्य भारत है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन्डस्ट्रियली कॉम्पीटेन्ट हैं। वहां यह फैक्टर ज्यादा रूल करता है बनिस्पत यहां के या अन्य स्टेटों के, जहां एग्रीकल्चर पोटेन्शियलिटी ज्यादा है। कहीं एनीमल हस्बेन्डरी बायस है। अब इन सबको कम्पेअर करके कहें कि इसका तो वेलफेयर है और इसका नहीं है। तो इस तरह से इनसे यह भ्रमात्मक चीज पैदा हो जाती है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिफरेन्ट स्टेटों में डिफरेन्ट बेस ईयर्स होने से भारत सरकार के भी जितने स्टेटिस्टिक्स निकलते हैं वे भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। भारत सरकार के स्टेटिस्टिक्स ४८–४९ के बेस के हैं। ४८–४९ में राजस्थान बना ही नहीं था। यहां हम बेसिक ईयर ५४–५५ मानते हैं। जो आंकड़े कोंसटेन्ट प्राइस पर बेस करते रहे हैं वे ५४-५५ ईयर पर बेस हैं। इसलिए इसको कम्पेअर करना कॉन्स्टेन्ट प्राइस पर भारत सरकार के, यह भी उचित नहीं होगा।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह लोकनाथन् रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट, मैं भी दूसरी लेकर आया हूं। उन्होंने राजस्थान के ५७–५८ ईयर को बेस लेकर कैल्कुलेशन किया था। इसलिए इन सब रिपोर्टों को अलग अलग देखें तो कनफ्यूजन होता है और कभी-कभी विरोधी दल के सदस्य और खास तौर से जनसंघ दल के सदस्य इसे जब समझ नहीं पाते तो कह लेते हैं कि यह तो जग्लरी है, जग्लरी ऑफ फिगर्स हैं। यह बेसिस माइथोलोजी के तरीके पर कैल्कुलेट किया जाता है। अगर सब चीजें सब जगह कॉमन हों तो कम्पेरिजन हो सकता है, पर ऑल इण्डिया बेसिस पर सब कोमन अभी नहीं हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट लोकनाथम् की मैंने भी पढ़ी है। अब इन्होंने २६७.३, ६०-६१ में जो निकाली है, वह कौन सा बेसिक ईयर मानकर निकाला है। इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि एक और किताब है जो कि नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की ही है। यह वही संस्था है जिसका हवाला यहां दिया गया था। इस संस्था के डाइरेक्टर भी वही लोकनाथम् हैं।

श्री भैरोंसिंह : कौन से साल की है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ६०–६१ की है। वह भी ६०-६१ की है। यहां भी टेबल नम्बर ४ है पेज १२ है और ओकेज़नल पेपर नम्बर १२ है। यह किताब ६२ मे छपी है। उन्होंने ३ कॉलम में दिये हैं। ६१ में लिखा है कि राजस्थान की पर कैपिटा इन्कम २७० है। इसमें इन्होंने २७० बताया। इसमें किया है कि ७१ में राजस्थान की इन्कम जाकर ६०–६१ के प्राइसेज़ पर ६६६ हो जावेगी! आई एम सौरी, राजस्थान के फिगर्स २७९ हैं। उन्होंने जो ऑल इण्डिया के फिगर दिये हैं जिनमें आन्ध्र, आसाम, केरल, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात सब हैं उनमें फिफ्थ पोजीशन है राजस्थान की।

श्री भैरोंसिंह : प्राइसेज़ कब के हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ६०-६१ के हैं। उस पर २७६ दिया है। इन्डिकेशन नहीं दिया है, पर वे भी ६१ के प्राइसेज़ दे रहे हैं। ७१ तक के प्रोजेक्शन दिये हैं। और कई रीज़न्स भी दिये हैं। राजस्थान कैनाल्स की वजह भी दी है। पर उनके कैल्कुलेशन मैं नहीं जानता, क्योंकि ७१ तक सेंट परसेन्ट वही मिलेगा कौन कह सकता है अभी। पर मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि पर कैपिटा इन्कम उन्होंने २७६ इन्डिकेट की है। अब ये भी वही डाइरेक्टर हैं, वही इन्स्टीट्यूट्स हैं ,वही ६०-६१ के फिगर्स हैं और इन्हीं के फिगर्स आपने बताये थे और वे फिगर २६७ कहे है। यहां पर १२ पोइन्ट का फर्क पड़ जाता है।

श्री भैरोंसिंह : तो अब हम किसको सही मानें ?

श्री मथुरादास माथुर : सही तो मैं उसे ही कहूंगा जो राजस्थान का विभाग कहता है, करता है; अपनी तरफ से अपने तरीकों से करता है। इनके पास पूरे साधन है, पूरे आंकड़े हैं, वही पूरा काम कर सकते है। उनके पास इतने साधन नहीं, उनको इतना ज्ञान भी यहां का नहीं है। वे तो "सैल्डम सव" किसी डिस्ट्रिक्ट का करके चले जाते हैं। इसलिये उनके फिगर करेक्ट नहीं हो सकते। अब उनके इन फिगर्स को यहां क्वोट करके हम खुद भी गुमराह हो जाते हैं और जनता को भी गुमराह कर देते हैं।

मैं एक बात और कहूं। "टोकन इकोनॉमी सर्वे" राजस्थान का है। सब लोगों के पास किताबें हैं। उसमें लोकनाथन् साहब भी हैं। ६०-६१ के फिगर दिये हैं, २७६ दिये हैं इसमें भी। इसलिये इस पेपर में २७६ मिलता है और उस पेपर में २६७, कैसे किस तरह से उसमें चला गया है ? इसके बारे में जानकारी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अपने विभाग को मैंने आदेश दिया है कि दिल्ली में जाकर इस संस्था के डाइरेक्टर से मिलें और बात करें। यह फिगर किस आधार पर वे छाप देते हैं कि जिनको फिर हमारे यहां के एम. एल. ए. साहब पकड़ लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब मैं आपके दिमाग को साफ करने के लिए अपने विभाग के आंकड़े देता हूं। जिसके बारे में अथोसिटी कायम है। इतने बड़े पैमाने पर हो जाती है कि जो ६०-६१ में थर्ड प्लान में ६१-६२ और ६२-६३ और ६३ का एडवान्स एस्टीमेट तीन चीजें हैं। बाकी ६४-६५ के फिगर अवेलेबल नहीं है। और प्रोजेक्शन के बारे में अभी नहीं कहना चाहता, नहीं तो आप आगे जाकर यह उल्लेख कर देंगे कि मैंने उस समय यह कहा था। इसलिये उस बारे में नहीं कहना चाहता।

राजस्थान की कॉन्स्टेन्ट प्राइसेज़, अगर बेस ५४-५५ का लें तो ६१-६२ में २५२ आता है, ६२-६३ में २४६ और ६३-६४ में २४४।

अब इसी को करेन्ट प्राइसेज पर लें तो ६०-६१ में ३४३ जिसको गवर्नर साहब

Page No 108

(श्री मथुरादास माथुर)

ने कहा है ३५५ तक हो जावेगा, क्योंकि यह साल अच्छा जा रहा है। १९६२-६३ में ३३९ और १९६३-६४ में ३३७ है। अब इसको अगर आप ऑल इन्डिया फिगर्स से कम्पेयर करें-करेन्ट प्राइस पर तो १९६१-६२ में हमारा फिगर था ३४३ और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का फिगर था ३३६.६, हमारे फिगर्स १९६२-६३ में ३३९ थे और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के फिगर्स ३३९.४, १९६३-६४ में हमारे फिगर्स हैं ३३७ और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के फिगर्स नोट अवेलेबल। आप देखेंगे कि ७ साल में जो १९६२-६३ और १९६३-६४ में पर-कैपिट इन्कम कम हुई हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण इसका यह है कि हमारे जो राजस्थान का पोपुलेशन ग्रोथ है वह २.६ परसेन्ट है और इन तीन सालों में हम करीब ७.८ परसेन्ट पोपुलेशन में राइज़ कर गये और उसके बाद दो सालों में राजस्थान के बहुत बड़े भाग में फेमिन रहा। एग्रीकल्चर में जब स्केयर्सिटी कन्डीशन्स हो जाती हैं तो एग्रीकल्चर इन्कम कम होती है और उससे स्टेट इन्कम भी गिर जाती है। नतीजा यह होता है कि पर कैपिटा इन्कम में फाल आ जाता है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई सोच ले कि हम बराबर गिरते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। १९६४-६५ में अच्छी आमदनी हुई है, इसलिए हमारे फिगर्स १९६१-६२ के ३५० थे इस समय मैं उम्मीद करता हूं कि करेन्ट प्राइस से ३५०-३५५ तक पहुंच जायेंगे, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा........

श्री भैरोंसिंह : ये जो फिगर्स दिये हैं और आपने कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ४६ परसेन्ट का कम्पोनेन्ट १९६२-६३ में ४४ लाख था और बाद में जो फिगर्स कैल्कुलेट किये और कहा कि ३८ लाख टन हुआ, यह तो बहुत फर्क आ गया ?

श्री मथुरादास माथुर : यूज़ुअली राजस्थान में रफली ४८-५० के नीचे कुछ एग्रीकल्चर कम्पोनेन्ट्स होते हैं। हमारे स्टेट इन्कम में कन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर एक दम ८ लाख टन कम हो गया उससे कम होने पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्कम कम होगी और स्टेट इन्कम कम होगी और चूंकि पोपुलेशन बढ़ गई तो पर-कैपिटा इन्कम गिर गई।

श्री भैरोंसिंह : जिस अनुपात में अन्न का उत्पादन कम हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी वजह बताई कि दूसरे सेक्टर्स जो कि एनीमल हस्बेन्डरी है, मेडीकल है इनमें प्राग्रेस हुई है। आप चाहें तो मैं डिटेलवाइज़ बता सकता हूं। उसमें कुछ बढ़ा है, इसलिए कुछ एग्रीकल्चर फॉल हुई है, वह कुछ कम्पेन्सेट हुई है। यह नहीं है कि दूसरे सेक्टर जो ५२ परसेन्ट रहे हैं उनको भी वैरी करना पड़ता है। उससे राइज़ हुई है, इसलिए इतनी कमी हुई, वर्ना बहुत ज्यादा कमी होती।....

श्री भैरोंसिंह : आपके खुद के फिगर्स से टैली नहीहोते ।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय भी वही एप्रोच फिगर्स दिये थे क्योंकि केल्कुलेट होकर नहीं आये थे। १९६३-६४ के एडवांस फिगर्स बता रहे हैं ३३७ ! हो सकता है कि ये ३३८ हो जायें । मेरे पास तो १९६४–६५ के प्रोजेक्शन हैं, लेकिन उसको देने से इन्कार इसलिए करता हूं कि तुम मेरी बात को पकड़ लोगे कि ऐसे तुमने अपने भाषण में कह दिया । माननीय उपाध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि इस सफाई के बाद हमारे जनसंघ के मुखिया को मेरी बात समझ में आई होगी –नहीं आई होगी तो हम आपस में बाहर समझ लेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता ने तीन पंच साला. योजनाओं के लिए कहा। उनके पेटेन्ट तीन सेन्टेन्स हैं कि जो कि ३ साल से निरन्तर कहते आ रहे हैं । एक तो "Plan is over ambitious, (2) Priorities are wrong, (3) Programme is not fulfilled."

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है माननीय विरोधी पक्ष के नेता से छिपा हुआ नहीं है । मैं यह मानता हूं कि कोई भी प्लान जो कि अण्डर डेवलप्ड स्टेट रह चुकी हो, जिसके यहां पर इकोनोमिक और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हुआ हो उस प्रान्त को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारा प्लान तो ओवर एम्बीशियस नहीं था । हमने प्लान्स बनाये और हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए सदन की इजाजत से हमने "कोर ऑफ दी प्लान" बनाया और उसके बाद में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारा थर्ड प्लान है इस थर्ड प्लान में जो कुछ भी हमने फिक्स किया था टार्गेट और जो भी हमारे आंकड़े थे वे करीब करीब हमारे 'कोर ऑफ दी प्लान' में फिजिकल परफोर्मेन्स ९८ परसेन्ट हो जायेगा और फिजिकल परफोर्मेन्स में जो हमारे रिवाइज्ड टार्गेट्स थे उसको, एक-दो सेक्टर को छोड़कर, मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर इतनी स्केयर्सिटी कन्डीशन्स आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो पोटेन्शियलिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करना चाहता था उसमें पर्फोर्मेन्स बहुत अच्छा रहा है । उसके बाद में एनीमल हस्बेन्ड्री में, एजुकेशन में, मेडीकल में जितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खुलने थे खुल गए, डॉक्टर्स की कमी हमारे पास जरूर है । हमारे राज्य में दो मेडीकल कॉलेज, और खोलने के बारे में कार्यवाही की गई है और फोर्थ प्लान में दो मेडीकल कॉलेज और होंगे । मैं यह कह सकता हूं और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि राजस्थान का प्लान पर्फोर्मेन्स हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स से, जो हमारे यहां पर लिमिटेड सोर्सेज हैं और एफीशियेन्सी है वह दूसरों से कम नहीं हैं । हो सकता है उसको और आगे सुधारने की आवश्यकता हो । माननीय सदस्यों को संतोष तो है ही नहीं, हमें भी नहीं है । और भी आगे काम करना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा हालत में हमारे पर्फोर्मेन्स हर एक सेक्टर में ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमें चिन्ता करने की जरूरत है । इसलिए विरोधी दल के नेता तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्लान को पढ़ लेते और मैं हर साल एक पोथी भेंट कर देता हूं ।

(श्री मथुरादास माथुर)

कम से कम आप उसको पूरा पढ़ लें और फिर सदन में बात करें तो आपको तसल्ली हो जायेगी...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ४ साल में ४७ परसेन्ट यूटीलाइजेशन हुआ है आपके वैरियस डिपार्टमेंन्ट्स का।

श्री मथुरादास माथुर : आप मैथेमेटिक्स में वीक मालूम पड़ते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने एम. एस सी. किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): समझने में फर्क रह जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : कोर ऑफ दी प्लान को छोड़कर जो कि २३६ का था जिसको २०२ का कर दिया हम अगर २०३ या २०२ करोड़ रुपया खर्च नहीं करते और उसका रिजल्ट आया नहीं हो तो आपको ओलम्बा देने की गुंजाइश रह जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और ज्यादा बहस नहीं करते हुए जो तीसरे प्लान के जो रिवाइज्ड टार्गेट्स थे उनको राज्य सरकार ने और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने पूरा करने की कोशिश की है। और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कामों में–रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में ३०० गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि वे १ हजार गांव हो जायेंगे बाई दी एण्ड ऑफ दी थर्ड प्लान। उसमें टारगेट बढ़ा है। कहीं टार्गेट कम हुआ है। शिक्षा में टार्गेट कम हुआ है। जहां तक लड़कों की शिक्षा का सवाल है हमने टार्गेट को पूरा किया है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में टार्गेट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए स्टेट का टोटल ६ से ११ की एज ग्रुप का टार्गेट कम हो गया है। ११ से १३, १७ से २० के जितने भी टार्गेट हैं सब पूरे हुए हैं। मैं एक एक फीगर को पढ़ कर आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में, इस मामले में राज्य सरकार पूरी सतर्क है और विभागों ने काम पूरा किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान खींचा है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भीलवाड़ा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कहा कि आंकड़े गलत हैं। गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया था अगले साल उस वक्त हमारा ६७ पर्सेन्ट फेमिलीज को कवर करने का ओरीजिनल टार्गेट था। तीसरी पंचसाला योजना के अन्त तक राजस्थान में सहकारी क्षेत्र के अन्दर ६७ पर्सेन्ट फेमिलीज राजस्थान की चली जायंगी उसको रिवाइज करके ५८ पर्सेन्ट कर दिया तो गवर्नर साहब ने अगले साल के लिए ५८ पर्सेन्ट के आंकड़े दिये थे और इस वक्त ६७ पर्सेन्ट पर आपने कह दिया कि गवर्नर साहब को बहका दिया। सदन की इजाजत से ५८ पर्सेन्ट रिवाइ किये गये थे और मुझे खेद है कि हम उसमें ३५ पर्सेन्ट तक ही पहुंच पाये हैं। इसके लिए भी हमारे पास वजुहात मौजूद है कि हम ३५ पर्सेन्ट

Page No 111

(श्री मथुरादास माथुर)

फेमिलीज़ को कवर कर पाये । दूसरे आंकड़े विलेजेज़ को कवर करने का था सेन्ट-पर्सेन्ट । वह हम अभी तक ७९ पर्सेन्ट कर पाये हैं । अभी एक साल बाकी है । हमें उम्मीद है कि उस समय तक हम ९०–९१ पर्सेन्ट को कवर कर लेंगे । फेमिलीज़ को कवर करने में हमारा शोर्टफॉल है । मेम्बरशिप का टार्गेट पूरा हो रहा है, जैसा कि गवर्नर साहब ने अभिभाषण में कहा है ।

एक बात और कहूंगा । ओवरड्यूज़ के बारे में, कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो बातें इस सम्बन्ध में आपको बतलाना चाहता हूं-एक ड्यू और एक ओवरड्यू । हम जो कर्जा दे देते हैं, अगर हम समझ लेते हैं कि कर्जा अदायगी नहीं हो रही है । पांच लाख और तीन लाख के बड़े बड़े आँकड़े देते हैं, मगर ओवरड्यू वह होता है जो अदायगी का समय होता है । उस समय पर अदा नहीं कर सके तो उस तारीख के बाद ओवरड्यु बनता है और तब हम लोगों को एलार्म होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार बड़ी सतर्क है, क्योंकि उससे सोसाइटी डिफॉल्टर बन जाती है, कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर बन जाता है, सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर बन जाता है, एपेक्स बैंक डिफॉल्टर बन जाता है, रिज़र्व बैंक डिफॉल्टर बन जाता है और फिर क्रेडिट बन्द हो जाती है और कोआपरेटिव मूवमेंट ठप्प हो जाता है । इसलिए इस बात की कोशिश की जाती है । मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, जो आपके और मेरे हाथ में नहीं होती हैं । अकाल पड़ता है, तब रेमिशन होता है । उसके बाद लोगों को राहत बांटी जाती है,४-५ करोड़ की राहत बांटी गई । उस समय हमारे सहकारी विभाग का इन्सपेक्टर जाकर रुपया वसूल करे तो कहां से वसूल हो इसलिए हमको रोकना पड़ता है, इसलिए ओवर ड्यूज़ के आंकड़े जितने भी बढ़ गये थे इसका कारण यह था कि सिर्फ दो साल तक कुछ इलाकों में और एक साल तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके में अकाल पड़ा था । ओवरड्यूज़ बढ़ने के बावजूद जब आज जमाना ठीक हुआ तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की और कोशिश करने के बाद १९६ लाख का जो ओवरड्यूज़ हो गया था, मैं मानता हूं कि यह हुआ था दो साल में और इस कन्डीशन में भी १४२ लाख रुपया वसूल कर लिया । उस हद तक ओवरड्यूज़ कम हो गये और बाकी के लिए बराबर कोशिश की जायगी । इसका एक स्पेशल कम्पेन चलाया गया और यहां तक मेरे एक साथी ने कहा कि सहकारी विभाग का इन्सपेक्टर तो पुलिस विभाग के इन्सपेक्टर की तरह वसूली कर रहा है । मेरे साथी यहां बैठे बैठे गरदन हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कर रहा है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इन्सपेक्टर रियेलाइजेशन पुलिस विभाग की तरह से नहीं करता है और न पुलिस विभाग ऐसा करता है । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर रुपया नहीं देगा किसान, तो उस पर बोझ बढ़ेगा और उसकी हालत बिगड़ जायगी । हमको देना और लेना पड़ता है ताकि क्रेडिट का फ्लो होता रहे । ओवरड्यू होने पर रिज़र्व बैंक

(श्री मथुरादास माथुर)

की खास इजाजत लेकर यह किया है ताकि क्रेडिट कामयाब हो और लोन देते रहें जिससे कि देश का उत्पादन कम न हो जाय । वह क्रेडिट का फ्लो होता रहे और यह रियलाइजेशन हमने किया है वह रियलाइजेशन १४२ लाख का है वह सराहनीय है ।

उसके बाद जो सहकारिता की कमजोरियां है उनको ठीक करने के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ, ताकि सहकारिता की बुनियाद मजबूत हो और सब लोग उसको अपना लें; तो आगे जाकर जो नवनिर्माण हम करना चाहते हैं उसको बहुत बड़ा सहयोग मिल सके । मैं सहकारिता कानून में संशोधन पेश कर रहा हूं । उसमें हम कई तब्दीलियां ला रहे हैं । इस कानून को हमें डाइनेमिक, एक क्रान्तिकारी कानून बनाना पड़ेगा । यह सिर्फ एक व्यवसायिक कानून नहीं होगा । यह समाज के परिवर्तन का मेडमरिफेसिस का कानून बनेगा । मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य इस पर जोरों से विचार कर रहे हैं । उनके सहयोग से ऐसा कानून बनेगा जिससे कि सहकारी आन्दोलन को प्रगति मिले, जिसमें आज जो ऐसे लोग घुस जाते हैं । जो सहकारिता के नाम पर शोषण करते हैं वे उसमें जगह न पा सकें ।

उसके साथ साथ सबसे बड़ी सहकारिता की जो कमजोरी है जो कि आप लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि हम क्रेडिट को मार्केट से लिंक नहीं कर सकते हैं । उसमें आप लोगों का सहयोग चाहते हैं जगह जगह ताकि खाद्य समस्या में वितरण का कार्यक्रम और प्रोक्योरमेंट का कार्यक्रम आगे बढ़े । मैंने अगले साल के लिए कुछ टार्गेट बनाया है । मैं उम्मीद करता हूं कि मौके पर आपके सामने पेश करूंगा, चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस वगैरह पर या अगले साल के बजट की बहस पर कहूंगा तो उस पर आप विचार रखूंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बाढ़दार साहब ने कुछ कानूनी बातें कहीं । खास तौर से एक बात कही कि हमारे यहां राज्य सरकार ने, आपको मालूम है कि मैंने इस सदन में कहा है कि 'लॉ कमीशन' की रिपोर्ट को हमने काफी हद तक मन्जूर कर लिया है । सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी में कुछ एमर्जेंसी की वजह से जिस तेजी के साथ बढ़ना चाहते थे उस तेजी के साथ नहीं बढ़ पाये हैं । फिर भी राजस्थान में ६७ पर्सेन्ट सबडिवीजन के हैड क्वार्टर्स पर इसको कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हल्के २ प्रगति की ओर चल रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "लॉ-कमीशन" की जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात कही गई है; उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है । जिसमें एडवोकेट जनरल, होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि राजस्थान की आज की सामाजिक हालत में यह करना मुनासिब होगा ? इस पर माननीय सदस्यों द्वारा भी विचार किया जायगा । कानून के एक सिद्धान्त को लेकर अपनी हालात में अगर वह फिट नहीं होता है तो उसके करने से बजाय प्रगति के हानि हो सकती है; वह

Page No 113

(श्री मथुरादास माथुर)

कानून ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति की प्रगति को ध्यान में रखते हुए वह कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके बाद माननीय सदस्यों द्वारा विचार करके उस पर निर्णय लिया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ बातें और भी कही हैं। कुछ उन्होंने लीव वैकेन्सी के बारे में कहा कि कुछ जगह खाली थीं, उन पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलैक्ट करके लिस्ट हाई कोर्ट को भेज दी हैं। वह जगह भर दी जायगी और उसके बाद इस तरह की कठिनाई नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर अपनी तवज्जोह दी उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उनको हरेक विभाग की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आपके अच्छे सुभावों से हमको प्रगति करने का अवसर मिलता रहे और हमारी त्रुटियों को ठीक करने का मौका मिलता रहे। हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर मिनिमम् वेजेज़ के बारे में जिक्र किया है कि वे अभी तक आउट नहीं किये हैं। मैं नम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करना चाहता हूं और उनकी अदम मौजूदगी में उनकी कुर्सी से निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार ने और खास तौर से ट्रान्सपोर्ट विभाग में जो कि मेरे पास है, उसके अन्दर जो मिनिमम वेजेज़ के लिए एक कमेटी बैठी थी फिर बोर्ड के पास में गया। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया उसके बाद राजस्थान सरकार ने २४ फरवरी १९६५ को गजट नोटिफिकेशन निकाला है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं वह यह है—

अनस्किल्ड	...	६०) रु.
सेमी स्किल्ड	...	८५) रु.
स्किल्ड	...	१००) रु.
ट्रैफिक स्टाफ ६५), ८५) और		१००) रु
ऑफिस स्टाफ	....	१००) रु.
इन्सपेक्टोरेट स्टाफ	...	१००) रु.

यह रिपोर्ट हमने मंजूर की है, जो कि कमेटी ने सिफारिश की थी और ३, ४, ५ केटेगरीज़ हमने सेमीस्किल्ड और स्किल्ड की मुकर्रर कर दी है।

इतना ही नहीं, बल्कि ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में जिक्र किया, उसके बाद दूसरे विभाग हैं उसमें कंस्ट्रक्शन एंड मेन्टेनेन्स ऑफ रोड्स एण्ड बिल्डिंग्ज़ ओपरेशन्स में काम करने वाले आदमी हैं। उनके बारे मे अलग अलग केटेगरीज के मैकेनिक्स, लेबर इत्यादि हैं उनके लिए भी इसको लागू किया है। इसके साथ साथ तीसरे हमारे यहां स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं उन पर बराबर मिनिमम वेजेज़ को लागू किया है जो एडवाइज़री बोर्ड है, जिसमें मजदूरों के नुमाइन्दे बैठते हैं उस बोर्ड की सिफारिशों को सेन्ट पर्सेन्ट लागू करने का फैसला किया है......

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : आपने इसको गजट में नोटिफाइ कर दिया है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : आप घर जायेंगे तब तक मिल जायगा ।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप उसकी तारीख बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : २४ फरवरी, १९६५ ।

श्री मानिकचंद सुराणा : गजट नोटिफिकेशन को आपने बैंक डेट में छापा । उस दिन छपा नहीं था और आज तक पहुंचा नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : नोर्मली गजट शनिवार को छपता है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपके पास गजट की कॉपी हो तो उसे सदन की मेज पर रखें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह छः फीट का गजट मेरे पास मौजूद है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : गजट ६ फीट का नहीं होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपको लड्डू से मतलब है या लड्डू की परात से मतलब है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपको दुःख क्या हो गया ? यदि फैसला हो गया ?......

श्री मानिकचद सुराणा : आप समझे ही नहीं कि मुद्दा क्या है और बोलने लगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने कहा कि लागू नहीं किया और सरकार ने कहा कि लागू कर दिया, तो इसमें आपको दुःख क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं मेज पर रख सकता हूं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : सरकार के पास गजट नहीं है, सरकार झूंठ बोल रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): २७ तारीख को आपके डिप्टी कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेन्ट के पास पहुंचा है । मैं चैलेन्ज करके कहता हूं कि यह २४ तारीख को नहीं छपा है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपका जो चैलेन्ज हुआ है उस चैलेन्ज से मुझे बहस में नहीं पड़ना है ।......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है । उन्होंने गवर्नर के द्वारा गलत बात सदन में कहलाई है । सितम्बर के बाद शिड्यूल के मुताबिक कोई फैसला इस मुतल्लिक नहीं हुआ था और २४ तारीख को गवर्नर से झूंठी बात कहला दी । बाद में २७ तारीख को केबिनेट की मीटिंग बुला कर मुख्य मंत्रीजी ने इस पर डिसीजन लिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्रीजी ने कब डिसीजन लिया, उसके बारे में हर कोई आता है और कह देता है । केबिनेट की बात खुदा को भी मालूम नहीं होती इनको तो भला-उसका क्या पता लगेगा ?

(श्री मथुरादास माथुर)

रामानंदजीने सवाल रेज़ किया था कि सरकार रिपोर्टों को मंजूर नहीं कर रही है ।। मैं कहता हूं कि २४ तारीख को मंजूरकरके गजट में नोटिफिकेशन हुआ । मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उनको देखते हुए उधर की तरफ से तालियां बजनी चाहिये थीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तालियां तो मैं दोनों हाथों से बजा सकता हूं लेकिन २४ तारीख के नाम पर फ्रॉड किया, क्योंकि २७ को मंजूर किया ।....

श्री मथुरादास माथुर: कोई फ्रॉड नहीं है । फ्रॉड लफ्ज़ के आप लोग आदी है राज्य सरकार फ्रॉड नहीं करती : जनता के साथ फ्रॉड करने का सवाल नहीं है । राज्य सरकार ने जो तीन चीजें मंजूर की हैं उसका बदजायका कैसे किया जाय ! उसका यह प्रयत्न है, वरना राज्य सरकार ने ऐसा कदम उठाया है राजस्थान में जिसकी तारीफ की जानी चाहिये थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कोई एहसान नहीं किया है । राजस्थान के ५ लाख मजदूरों ने कराया है । आपकी इन्टक ने भी धमकी दी थी, तब किया है; तब सरेन्डर हुए हो, सीधे हाथ नहीं दिया है ।

श्री मानिकचंद सुराणा :ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर, उन्होंने इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव...

(मंत्री महोदय के खड़े होने पर)

आपके ऑर्डर के पश्चात् या तो मंत्रीजी बैठ जायं या मैं बैठ जाऊं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्पीकर महोदय को एक विशेषाधिकार भंग होने का प्रस्ताव दिया जा चुका है । एक तो रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है और एक मैंने अध्यक्ष महोदय के पास भेजा है । इस संबंध में बहस सदन में हो रही है, मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि २४ फरवरी को यह रिकमन्डेशन स्वीकार कर ली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका है ? आपने जो रिकमन्डेशन मंजूर की है उसमें विवाद करने का प्रश्न नहीं है । जो कुछ किया है उसको हम भी एप्रिशियेट करते हैं, लेकिन गवर्नर महोदय के भाषण में कहा है कि २४ फरवरी को यह परिवर्तन कर दिया गया है, क्या यह परिवर्तन उस रोज हो चुका था ? खाली भाषण में लिखने से या मुंह से बात कहने से गजट में छप नहीं सकता, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाय और नोटिफिकेशन गजट में शाया हुआ है तो वह रखा जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं नहीं कह सकता कि गजट में निकला या नहीं, लेकिन २४ तारीख को फैसला हो चुका था । गवर्नर महोदय के अभिभाषण से पहले राज्य सरकार ने फैसला ले लिया था । यह आपका भ्रम है कि फैसला नहीं हुआ था, निराधार है ।....

श्री मानिकचंद सुराणा : २४ को निर्णय लिया था या नहीं; लेकिन यह स्पष्ट है कि गवर्नर के भाषण तक विज्ञप्ति नहीं निकली थी ।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नर के अभिभाषण के पहले तीन सब्जेक्ट्स पर जिनको मैंने पढ़ा निर्णय हो चुका था।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: २४ को मीटिंग सुबह हुई थी या बाद में ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नर के भाषण से पहले राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया था, यह आप नोट कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २७ की कार्यवाही को २४ को होना बता रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप केबिनेट में मौजूद नहीं थे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।....

श्री मानिकचंद सुराणा : कितने बजे केबिनेट की मीटिंग हुई थी प्रोसिडिंग्ज़ रख दीजिये सदन की मेज पर।

श्री मथुरादास माथुर : सुबह हुई थी, २३ की शाम को हुई थी ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नर के वहां चाय पीने के बाद हुई थी...

श्री मथुरादास माथुर : केबिनेट की मीटिंग में और भी एजेन्डा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ रूट्स के नेशनलाइज़ेशन के बारे में कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन होने के बाद बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स फैसला करते हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अगले साल वे ४०० मील करीब रूट का नेशनलाइज़ेशन करेंगे। ३०० मील करीब अजमेर से अहमदाबाद और १०० मील का दूसरा निर्णय कर रहे हैं।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई लोग टिकटों के पैसे जमा कराते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कराने की बात कही। इसके लिये फ्लाइंग स्क्वेड नियुक्त कर दिये हैं और उन्होंने काफी केसेज पकड़े भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कोर्पोरेशन्स हैं, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे दूसरे हों इनके धणी धोरी या मालिक जनता है और उनके नुमायन्दा होने के नाते आप लोग सहयोग दें और बातें बतावें; ताकि ये जो कोर्पोरेशन्स इन्फेन्सी में हैं वे आगे तरक्की कर सकें। राज्यपाल के अभिभाषण में जो मुद्दे बताये हैं और जिक्र किया है, मेरे विभाग से संबंधित बातों का मैंने जिक्र किया है, मैं मानता हूं आपको संतोष होगा और जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, बुधवार दिनांक ३ मार्च, १९६५ के म. पू.. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८ का उत्तर देखिये)

प्राइमरी स्कूल उमर, पंचायत समिति हिन्डोली के स्कूल की छात्र संख्या

	कक्षा १		कक्षा २	कक्षा ३	कक्षा ४	कक्षा ५
		ब				
छात्र	२२	४१	१७	१०	१९	१५
छात्राएं	४	९	३	–	१	१
	२६	५०	२०	१०	२०	१६

कुल १२४ छात्र व १८ छात्राएं

Page No 118

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिये)

कोटा-भोपाल पर पकड़े गये भ्रष्टाचार मामलों की सूची

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	भ्रष्टाचार का विवरण	कार्यवाही
(१)	श्री रामौतार परिचालक	२८ सवारियों से बिना टिकट श्री टी.ए. जेंदी, सहायक यातायात निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया।	दोनों मामलों में जांच की की गई। जांच के बाद परिचालक की सालाना वृद्धि रोक दी गई।
(२)	श्री रामौतार परिचालक	दो सवारियों से बिना टिकट श्री रामनारायण यातायात निरीक्षक ने पकड़ा।	
(३)	श्री इन्द्रमल	तीत सवारियों से बिना टिकट श्री कान्तिचन्द जोशी डिपो मैनेजर ने पकड़ा।	चेतावनी दे दी गई।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर देखिये)

(१) अगस्त माह १९६४ में निम्नलिखित तारीखों को निम्नलिखित समयों के लिये टौंक में बिजली बन्द रही ।

तारीख	समय जब से बिजली बन्द हुई कब से	कब तक	कितने समय के लिये	विशेष विवरण
३-८-६४	९।२५ प्रातःकाल	१०।२० प्रातःकाल	५५ मिनिट	इन्सलेटर ब्रेक होने के कारण ।
७-८-६४	९।२० प्रातःकाल	१।०० सायंकाल	१ घंटे ४० मि.	तेज वर्षा और हवा
११-८-६४	८।५५ सायंकाल	९।३० सायंकाल	३५ मिनिट	जम्पर टूट जाने के कारण ।
२३-८-६४	५।१० सायंकाल	५।१२ सायंकाल	२ मिनिट	अस्थाई खराबियों के कारण ।
२८-८-६४	७।१५ सायंकाल	७।२० सायंकाल	५ मिनिट	
२९-८-६४	३।२० सायंकाल	३।२१ सायंकाल	१ मिनिट	
३०-८-६४	८।४० सायंकाल	८।४३ सायंकाल	३ मिनिट	

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर देखिये)

(१) जयपुर महारानी कालेज की विज्ञान की विभिन्न प्रयोग शालाओं का १९६४-६५ का बजट निम्न प्रकार से है :—

		स्थाई	विशेष
(१)	भौतिक शास्त्र	४०००)	४०००)
(२)	रसायन शास्त्र	८०००)	७०००)
(३)	बनस्पति शास्त्र	२०००)	२०००)
(४)	जीव विज्ञान शास्त्र	४०००)	४०००)
(५)	गैस प्लांट, बनस्पति उद्यान तथा फागरी		३५००)

———

DISTRIBUTION OF THE LABORATORY GRANTS FOR THE VARIOUS SCIENCE DEPARTMENTS OF MAHARAJA'S COLLEGE JAIPUR FOR THE SESSION 1964-65.

S.No.	Name of Department	Allocation		Total
		Out of Lab. Grant.	Out of Equp. & apparatus Grant.	
1.	Chemistry	Rs. 25,000/-	Rs. 6,500/-	Rs. 31,500/-
2.	Physics	Rs. 6,000/-	Rs. 8,000/-	Rs. 14,800/-
3.	Zoology	Rs. 3,000/-	Rs. 4,000/-	Rs. 7,000/-
4.	Botany	Rs. 3,000/-	Rs. 4,000/-	Rs. 7,000/-
5.	Geology	Rs. 1,000/-	Rs. 3,000/-	Rs. 4,000/-
6.	Mathematics	Rs. —	Rs. 1,000/-	Rs. 1,000/-
7.	Statistics	Rs. —	Rs. 500/-	Rs. 500/-
8.	Miscellaneous	Rs. 2,000/-	Rs. 3,000/-	Rs. 5,000/-
	Total	Rs. 40,000/-	Rs. 30,000/-	Rs. 70,000/-

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २ मार्च, १९६५)

स्कम्म संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७५४	अन्तिम से ४	:(आसीन्द)	(आसीन्द) :
७५८	शीर्ष	(श्री गिरगारी लाल व्यास)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)
७५९	अन्तिम से ४	" एक	एक
७६०	१३	मंत्री बताने	मंत्री यह बताने
७६१	अन्तिम से २	थी श्रवणलाल	श्री श्रवणलाल
७६२	११	श्री भैरवलाल 'कालाबदल'	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
,,	२०	तो	तो पैसा
७६३	अन्तिम से ५	(अजमेर-	(अजमेर सिटी-
७६४	५	नहीं	नहीं
,,	१६	(रकगनाइज़्ड)	(रिकग्नाइज़्ड)
७६५	१२	श्री लक्ष्मीकुमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
७६६	शीर्षक	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
७७०	शीर्ष	(श्री मथुरादार माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
७७१	अन्तिम से ६	लड़कियो	लड़कियों
७७२	अन्तिम से ६	श्री रघुनाथ बिश्नोइ	श्री रघुनाथ बिश्नोई
७७४	शीर्षक	२ मार्च, ६५	२ मार्च, ६५
७७५	३	मर्ि सक	मासिक
७७७	८	न कहने	न यह कहने
७७८	शीर्ष	(श्री रघुनाथ विश्नोई)	(श्री मथुरादास माथुर)
७८१	१	श्रो हरलाल मीणा	श्री हरलाल मीणा
,,	अन्तिम से ८	बे	वे
,,	,, ,, ४	सूर्ची	सूची
७८६	४	छूग्राछूत	छुआछूत
७८८	,,	३ मार्च ६५	२ मार्च, ६५
,,	५	श्रो	श्री
,,	अन्तिम	वरते	करते
७९०	६	श्री हीराभाई कुशलगढ़):	श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :
७९२	३	बैंद	वैद

१	२	३	४
७९७	८	मेट्रिक	मेट्रिक
,,	१२	श्री तेरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२०	(लूनकणसर)	(लूणकरणसर)
,,	२२	गेजुएट	ग्रेजुएट
८०२	१५	प्रनिनिधि	प्रतिनिधि
८०३	५	वतने	वताने
८०४	४	नहीं किया ।	विभाग ने नहीं किया ।
,,	८	श्र' निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	अन्तिम से ६	सॉस्कृतिक	सांस्कृतिक
८०५	१	श्री अध्यत्न	श्री अध्यक्ष
,,	६	लंब चौड़ा	लम्बा-चौडा
,,	अन्तिम से ५	छात्रार्ये	छात्राए
८०७	६	श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'	श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'
८०८	१३	श्री भैंरवलाल काला बादल-	श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' :
८०९	१६	इस्टीटयूशन्स	इन्स्टीट्यूशन्स
८१०	१०	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
८१२	शीर्ष	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
८१५	६	श्री श्रवणलाल । :	श्री श्रवणलाल :
,,	१६	वित्त-मन्त्र	वित्त-मन्त्री
८२०	१	सैंकन्डरीं	सैकन्डरी
,,	३	वैंद श्री गोबिन्द सहाय	वैद्य श्री गोविन्द सहाय
८२५	अन्तिम से २	(उप मंत्री) राजस्व :	(उप-मंत्री, राजस्व) :
८२६	शीर्षक	२ मार्च, ६५- पुरःस्थापित	२ मार्च, ६५-पुरःस्थापित
,,	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
,,	अन्तिम से ४	वधकरण	वंधकरण
८२७	१	(बोडो	(बोर्डो
८२८	१३, १४	उपस्थापक	उपस्थापन
८३१	अन्तिम से ८	(स्वायत शासन	(स्वायत्त शासन)
८३३	२०	(१२. ११ म. प.)	(१२.१८ म. प.)
८३७	२२	फर्टीलाजइर्स	फर्टीलाइजर्स
८४२	शीर्ष	(श्री मोतीलाल चौधरी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
८४९	स्तम्भ	८५९	८४९

१	२	३	४
८५३	अन्तिम से ८	घ र	ओर
८५८	शीर्ष	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
८५९	अन्तिम से ४	अनिश्चित	अनिश्चितता
८६३	७	िभाव	सुभाव
,,	१९	हमारी गरबी	हमारी गरीबी
८६४	शीर्ष	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
८६७	७	प्रोड्यू किएस	प्रोड्यूस किए
८६८		———	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
,,	१८, १९	नमानीय	माननीय
,,	अन्तिम से ५	वितनण	वितरण
,,	अन्तिम	अनिबार्य	अनिवार्य
८७०	शीर्षक	–२ मार्क, ६५–	–२ मार्च, ६५–
,,	११	वषं	वर्ष
८७१	१४	जिम्मा	जिम्मा
८७३	१९	ओीर	ओर
८७८	१९	से । बात	से बात
८७९	७	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
८८३	६	निबेदन	निवेदन
,,	९	chan es	chain lies
८८४	६	श्र ी अमरसिंह	श्री अमरसिंह
८८६	शीर्षक	-२ माच, ६५-	-२ मार्च, ६५
८९८	शीर्ष	(श्री नाथूराम मिध	(श्री नाथूराम मिर्धा)
९९९	अन्तिम से ६	श्री विजयसिंह कटारा	श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०)
९२७	अन्तिम से २	फसला	फैसला
९३८	१३	श्री नाथूराम मिर्धा :	श्री नाथूराम मिर्धा :
९४०	७	कारप्रोरेशन	कोर्पोरेशन
,,	१०	फसल हाथ में ली है,	
९४४	शीर्षक	२७ फरवरी, ६५–	२ मार्च, ६५–
९५३	,,	वाद:विवाद	वाद-विवाद
९६०	,,	२ माच, ६५	२ मार्च, ६५
९६१	,,	वाय–विवाद	वाद-विवाद

१	२	३	४
६६५	शीर्षक	ग्रेत्तर	अग्रेत्तर
६६८, ६७८	,,	२ मार्च, ६५–	२ मार्च, ६५–
६७०	,,	२ माच, ६५–	२ मार्च, ६५–
६७३	१२	ओवरड्यूज	वे ओवरड्यूज
६७८	अन्तिम से ६	श्री मानिकचद सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६७६	८	(रायसिहनगर)	(रायसिंहनगर)
६८१	अन्तिम से ६	भ्रम	भ्रम